M.P./BHOPAL/642/2018-20

• बुंदेलखंड में एक्सप्रेस-वे ने पकड़ी रफ्तार • केवल 2 फीसदी को 100 दिन काम

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

राजनीति नहीं राष्ट्रनीति

वर्ष 19, अंक-4 16 से 30 नवंबर 2020 पृष्ठ-48 मूल्य 25 रूपये

शिवराज बने सिरमौर

R.N.I. NO.HIN/2002/8718

We Deal in Pathology & Medical Equipments

Anu Sales Corporation

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M. : 9329556524, 9329556530

E-mail : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

आर्थिकी

9 | बजट पर पहरा

मप्र में उपचुनाव के बाद शिवराज सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संकट है। क्योंकि सरकार की आमदनी में भारी गिरावट आ चुकी है और खर्चे बढ़ गए हैं। कोरोनाकाल में भी...

राजपथ

10-11 | राजनीति नहीं राष्ट्रनीति

मप्र में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव के ठीक एक दिन बाद यानी 4 नवंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंचे तो राजनीतिक हलचलें तेज हो गईं। प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में तरह-तरह के कयास...

तहकीकात

13 | गरीबों के भाग्य में सड़ा-गला

मप्र में गरीब व कुपोषितों के घरों में बांटने के लिए शासन स्तर से भेजे गए चने की बोरियां खोली गईं तो उसमें से चने के साथ कीड़े निकल रहे हैं। कीड़े लगने से चना पूरी तरह खराब हो चुका है। बावजूद इसके चने की रैक उतारी गई और बांटने के लिए बिना जांच के ही...

भर्राशाही

18 | महंगी होगी बिजली

मप्र में जल्द ही उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लग सकता है। मप्र में उपचुनाव खत्म होने के बाद अब बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि बिजली कंपनियां पहले ही बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी करना चाहती थीं लेकिन...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र की 28 सीटों पर हुआ उपचुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं था। इस चुनाव परिणाम पर प्रदेश सरकार का भविष्य निर्भर था। इस चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए पार्टियों ने वह सभी हथकंडे अपनाए जो नैतिक और अनैतिक भी थे। लेकिन उपचुनाव जीतने में माहिर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार भी करिश्मा दिखाया और 19 सीटें जीतकर न केवल अपनी सरकार बरकरार रखी, बल्कि भाजपा को भी मजबूती प्रदान की।

16-17

20

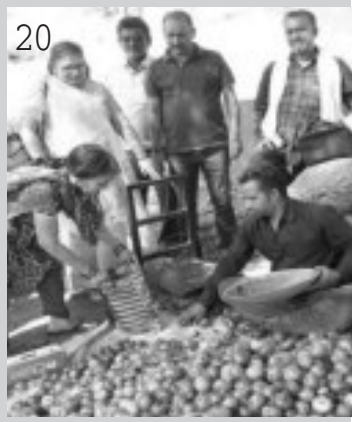

36

45

राजनीति

30-31 | केंद्र और राज्यों के बीच टकराव

आखिर केंद्र और राज्यों के बीच शून्य की एक स्थिति पैदा हो गई है। कारण यह है कि मजबूत केंद्र शायद राज्यों के प्रति अपने दृष्टिकोण में सहभागिता की भूमिका से दूर चला गया है और इसका नतीजा राज्यों में केंद्र के प्रति सम्मान की कमी के रूप में सामने आया है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ बहुतायत...

राजस्थान

35 | गुर्जर आंदोलन धुआं-धुआं

आखिरकार राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन 12वें दिन खत्म हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर सहमति बन गई है। सब कमेटी और गुर्जर संघर्ष समिति के बीच वार्ता में 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है। 5 मांगों पर गुर्जर...

बिहार

38 | मोदी ने बचाई लाज

बिहार के चुनावी परिणाम हर किसी के लिए बेहद चौंकाने वाले रहे। महागठबंधन को अपनी हार पर विश्वास नहीं हो रहा और न ही कांग्रेस अपनी हार पचा पा रही है। वहीं चुनावों में नीतीश कुमार के लिए जनता की नाराजगी खुलकर दिखी। लॉकडाउन में नीतीश...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

जीत के बाद अध्यक्षी को लेकर रार

शा यर निदा फाजली का एक शेर है...

दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं
तुम्हे भी देख सकूं, खुद को भी संभाल सकूं।

ये पंक्तियां उपचुनाव के बाद मप्र की राजनीति में निर्मित हालत पर सटीक बैठ रही हैं। दरअसल, उपचुनाव के परिणाम आने के साथ ही भाजपा नेताओं में सुरक्षित पद पर बैठने को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। कोई मंत्री बनना चाह रहा है तो कोई विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनकर चैन की सांस लेना चाहता है। पार्टी के कई वरिष्ठ विधायकों को लगता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शायद ही जगह मिल पाएगी। इसलिए वे विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए लॉबिंग में जुट गए हैं। उपचुनाव में बंपर जीत के बाद प्रदेश की सत्ता पर और मजबूती से डट गई भाजपा को अब विधानसभा अध्यक्ष चुनना है। कोरोना के कारण फिलहाल प्रोटेम स्पीकर ही सदन की कार्यवाही कराते हैं, लेकिन अब नया अध्यक्ष चुना जाना है। पद एक है और दावेदार कई। भाजपा के अलावा अब कांग्रेस भी इस पद के लिए अपनी पसंद बता रही है। भाजपा के कुछ नेताओं ने विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष बनाने की मांग की है, वहीं कांग्रेस का कहना है महाकौशल को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मप्र की सियासत में एक बार फिर दावेदारी शुरू हो गई है। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद भाजपा जिस ताकत के साथ सत्ता में कायम रही, वही उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब अंचल विशेष के संतुलन को साधना उसके लिए चुनौती है। महाकौशल से आने वाले प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई विधानसभा अध्यक्ष बनने की मंशा पाले हुए हैं। अभी वे संगठन के सामने खुलकर अपनी बात रख भी नहीं पाए हैं कि पूर्व कांग्रेसी और अब भाजपा विधायक मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बंपर वोटों से जीतने के बाद कहा है कि विंध्य से ही विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उनकी इस मांग का अजय विश्नोई ने हवा दे दी है। उनका कहना है अब समय आ गया है जब भाजपा तमाम अंचलों में संतुलन बनाएं क्योंकि यह संतुलन विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के काम आएगा। विश्नोई ने कहा- 'विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग मैंने 3 महीने पहले भी उठाई थी।' अजय विश्नोई का नाम भी विधानसभा अध्यक्ष की दौड़ में चल रहा है। इस पर विश्नोई का कहना है मैं खुद को इतने बड़े पद के लायक नहीं समझता। एक ओर भाजपा जहां विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस ने महाकौशल का कद बढ़ाने की मांग उठाई है। वैसे भाजपा ने कभी भी इस अंचल पर विशेष गौर नहीं किया है। बीती सरकार में अंचल का कद बढ़ा जहां मुख्यमंत्री के साथ-साथ तीन कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महाकौशल से आते थे। लेकिन इस दफा यह अंचल सूना पड़ा है। उधर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा भी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार बैठे हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए भाजपा में शुरू हुई रार किस मुकाम पर पहुंचती है। गौरतलब है कि उपचुनाव में बंपर जीत मिलने के बाद भाजपा के नेता क्षेत्रवार सरकार और संगठन पर दबाव बढ़ाने लगे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा यह है कि या तो उनके क्षेत्र को मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले या फिर विधानसभा अध्यक्ष उनके क्षेत्र से बनाया जाए। वैसे सत्तारूढ़ दल में पद और कद को लेकर हमेशा से तकरार रहती है। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ऐसी तकरार को सलीके से शांत भी करना जानती है।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 4, पृष्ठ-48, 16 से 30 नवंबर, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.)
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2018-20

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार, **जयपुर:-** आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21
नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,
मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

कैसे सुधरेंगे हालात

हम मप्र के कदम आत्मनिर्भरता की बजाय कर्ज पर निर्भरता की ओर लगातार बढ़ते देख रहे हैं। मार्च 2020 से शिवराज सरकार अपने कार्यकाल के 7 महीनों में राज्य को चलाने के लिए 10 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। ऐसे ही अगर सरकार कर्ज लेती रही तो हालात ठीक कैसे होंगे।

● **प्रमोद कुमार,** रायसेन (म.प्र.)

फर्जी उठा रहे फायदा

सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि 5 फीसदी लाभार्थियों का रैंडम फिजीकल वेरीफिकेशन कर अपात्रों की पहचान की जाए। साथ ही धोखेबाजों पर नकेल कसकर उनसे रकम वापस ली जाए। मप्र में भी कई फर्जी किसान सम्मान निधि ले रहे हैं।

● **संजय सेन,** भोपाल (म.प्र.)

सरकार उठाए ठोस कदम

मप्र के ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाकों में कच्ची शराब बनाने और बेचने का गोरखधंधा चल रहा है। शराब जहरीली बनकर लोगों की जान ले सकती है। हाल ही में उज्जैन 16 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

● **आदर्श श्रीवास्तव,** इंदौर (म.प्र.)

कैसे रुकेगी बच्चों की तस्करी?

मप्र में बच्चों की तस्करी दशकों से हो रही है। उन्हें मजदूरी कराने के लिए तस्करी कर दूसरे प्रदेशों में ले जाया जाता है। शासन और प्रशासन की तमाम कोशिश के बाद भी तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हाल ही में जारी हुई केंद्र सरकार की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लापता होने के मामले में देश में मप्र पहले नंबर है। प्रदेश से रोजाना 25 से ज्यादा और महीने में 800 से ज्यादा बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं। ये रिपोर्ट जनवरी 2014 से दिसंबर 2019 तक की है। इन 6 सालों में प्रदेश से 52 हजार 272 बच्चे गुम हो चुके हैं। देश में 3 लाख 18 हजार 748 गुमशुदा बच्चों में बीस फीसदी अकेले मप्र से हैं। सरकार को बच्चों की तस्करी के मामले में ठोस कदम उठाना चाहिए।

● **पद्मा यादव,** राजगढ़ (म.प्र.)

बढ़ेगा बीज का संकट

प्रदेश में सोयाबीन बीज का संकट फिर बढ़ेगा। इस कारण किसानों को एक बार फिर से नकली बीज माफिया का शिकार होना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नकली बीजों से नुकसान पहुंचा है। इस बार प्रदेश की कंपनियों ने बड़ी मात्रा में सोयाबीन का नकली बीज बनपाया है। इस कारण जहां खेती का रकबा घटा है, वहीं पैदावार भी घटी है। उधर, कंपनियां नकली बीज बेचकर मालामाल हो गई हैं। देश को 60 फीसदी सोयाबीन उत्पादन देने वाले मप्र में इस बार नकली बीज और मौसम की मार से पीले सोने की पैदावार 65 फीसदी गिरी है।

● **रीतेश कटारिया,** जबलपुर (म.प्र.)

शानदार स्वच्छता मिशन

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार को 53,000 रुपए का फायदा पहुंचा है। अध्ययन के मुताबिक स्वच्छता मिशन के कारण दस्त की बीमारी में कमी और साफ-सफाई में लगने वाले समय की बचत हुई है। इस मिशन के चलते गरीब तबके को इसकी लागत का करीब 2.6 गुना फायदा हुआ है, वहीं समाज को 5.7 गुना फायदा पहुंचा है। यह एक अच्छा मिशन साबित हो रहा है।

● **रंजीत सिंह,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

भय का भूत

साढ़े तीन साल बीत गए पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार गैरसैंण को सूबे की स्थाई राजधानी बनाने का अपना चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई है। सूबे के स्थापना दिवस 9 नवंबर को बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका ऐलान कर देंगे पर ऐसा नहीं हो पाया। लगता है कि बिहार चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री को डरा दिया। गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने से पर्वतीय क्षेत्र के लोग भले खुश हो जाएं पर मैदानी क्षेत्र में तो उलटा असर पड़ सकता है। डेढ़ साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आशंका तो रहती ही है। मूल और दल बदलकर पार्टी में आए दोनों खेमों में खींचतान की समस्या से सूबे में भाजपा उबर कहां पाई है। असंतोष न बढ़ जाए, यही डर तो मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं करने दे रहा। जिन्हें मंत्री पद की आस है, वे भी खुन्नस खाने लगे हैं। ऊपर से ज्यादातर भाजपा विधायकों की यह शिकायत सनातन है ही कि नौकरशाही उन्हें भाव नहीं देती। और तो और कई मंत्री तक यह रोना रो चुके हैं। गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित करने के बजाय मुख्यमंत्री ने यही कहा कि देहरादून स्थाई राजधानी है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले होती थी। इस बयान से पर्वतीय क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा है। मुख्यमंत्री की ही नहीं पार्टी की उलझन भी बढ़ी है।

कोई अविजित नहीं

योगी आदित्यनाथ उप्र चुनाव के नतीजों पर अगर खुश हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। 7 में से 6 सीटें जीतना यह तो जताता ही है कि सरकार विरोधी हवा नहीं है। पर देखना होगा कि भाजपा को 36.73 फीसदी वोट ही मिले हैं। यानी गैर भाजपा दल एक हो जाएं तो 2022 में सूबे में भाजपा के अविजित होने को लेकर पार्टी के नेता खुद को निश्चिंत नहीं मान सकते। चुनाव के नतीजों ने कई संदेश दिए हैं। मसलन अजित सिंह के रालोद का अब जाटों तक में असर नहीं बचा। बुलंदशहर सीट पर उनके उम्मीदवार की न केवल जमानत जब्त हो गई बल्कि वह पांचवें नंबर पर आया। प्रयोग के तौर पर ही सही, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने विरोधियों को चौंकाया है। अक्टूबर में ही तो उनकी आजाद समाज पार्टी का चुनाव आयोग से पंजीकरण हुआ था कि उन्होंने बुलंदशहर में उम्मीदवार उतार दिया। 13 हजार वोट पाकर उनका उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आया। मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद खतरे की घंटी हो सकते हैं। दलितों के युवा तबके में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। दो सीटों पर दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस के लिए भी उप्र में संभावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।

नए ईडी की तलाश शुरू

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के वर्तमान निदेशक का कार्यकाल 18 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। केंद्र सरकार की इस एजेंसी का काम कालेधन से जुड़े मामलों की जांच करना है। सीबीआई की तरह ही ईडी की कार्यशैली लगातार विवादों के घेरे में रहती आई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि वर्तमान सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ इस एजेंसी का जमकर दुरुपयोग करती है। सत्ता के गलियारों में इस आरोप की पुष्टि करते कई उदाहरण गिनाए जाते हैं। ऐसे में इस संस्था का सर्वोच्च पद पाने के लिए नौकरशाहों में जमकर कॉम्पीटिशन रहना स्वाभाविक है। वर्तमान ईडी एसके मिश्रा अपना दो बरस का कार्यकाल पूरा करने तो वाले हैं, लेकिन सूत्रों की मानें तो वे अगले दो बरस का सेवा विस्तार पाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति चाहिए होगी। मिश्रा के स्थान पर ईडी बनने वालों में राजस्व मंत्रालय की खुफिया एजेंसी डीआरआई के वर्तमान महानिदेशक बालेश कुमार, मुख्य आयुक्त मुंबई कस्टम अमित जैन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सचिव एसएम सहाय का नाम भी खासी चर्चा में है। चर्चा गर्म है कि केंद्र सरकार इस एजेंसी में बतौर मुखिया एसके मिश्रा को बनाए रखने के मूड में है।

नड्डा की बल्ले-बल्ले

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा का ग्राफ बिहार में एनडीए की वापसी और उप्र, मप्र, गुजरात आदि राज्यों में हुए उपचुनाव की जीत के बाद खासा बढ़ गया है। पहले कार्यकारी, बाद में पूर्णकालिक अध्यक्ष बने नड्डा को प्रधानमंत्री मोदी का बेहद करीबी माना जाता है। गत दिनों दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को नड्डा के लिए तालियां बजाने और नारे लगाने के लिए स्वयं मोदी ने कहा। फिर क्या था 'नड्डा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं' से भाजपा मुख्यालय गुंजायमान हो उठा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री का नड्डा की पीठ थपथपाना भाजपा के भीतर बदल रहे सत्ता समीकरणों के चलते हैं। पिछले काफी अरसे से गृहमंत्री अमित शाह का रुतबा कम होने की बातें उठने लगी है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद साथी कहे जाने वाले अमित शाह इन दिनों पार्टी मामलों में इन्हीं बदलते समीकरणों के चलते खास सक्रिय नहीं हैं। इसलिए नड्डा का कद बढ़ाया जा रहा है।

फिर चल पड़ी साइकिल

1990 के बाद से उप्र में विलुप्त प्रजाति बन चुकी कांग्रेस के साथ-साथ सपा और बसपा में भी लकवा-सा मार गया नजर आ रहा है। बसपा प्रमुख मायावती तो इतनी हताश हैं कि अपने कोर वोट बैंक को भीम आर्मी के पाले में जाने से रोकने तक का प्रयास नहीं करती दिख रही हैं। कांग्रेस में जरूर थोड़ी-बहुत जान प्रियंका गांधी के चलते पड़ी है लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद प्रियंका पार्टी को आईसीयू से बाहर लाने में विफल रही हैं। केवल सपा की साइकिल एक बार फिर से ट्रैक पर चलती नजर आ रही है। पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस और बसपा नेताओं ने सपा का दामन थामना शुरू कर दिया है। भाजपा से नाराज चल रहे नेता भी अब अपना भविष्य सपा में तलाश रहे हैं। राहुल गांधी की करीबी कांग्रेसी नेता अनु टंडन ने कांग्रेस से नाता तोड़ सपा ज्वाइन कर ली। उनके इस कदम को 2022 विधानसभा चुनावों के साथ-साथ केंद्र की राजनीति को कॉरपोरेट घरानों के बदलते मिजाज से जोड़कर देखा जा रहा है।

60 दिन नहीं 365 दिन का अध्यक्ष

मप्र में उपचुनाव में 19 सीटें जीतने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी और मजबूत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विधानसभा अध्यक्ष बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दावेदार नेता राजनीतिक वीथिका में जमावट करने लगे। प्रदेश के एक कद्दावर विधायक और पूर्व मंत्री विधानसभा अध्यक्ष बनने की मंशा पाले हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि महाकौशल क्षेत्र से आने वाले नेताजी ने पूर्व में अपनी मंशा संगठन को भी बता दी थी। अब जब एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हुई है तो उनके मन में भी उल्लास जगा है। पूर्व मंत्रीजी की मंशा को भांपते हुए कुछ खबरचियों ने जब उनसे पूछा कि क्या आप विधानसभा अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो उन्होंने तपाक से उत्तर दिया कि भाई ! बनना तो चाहता हूं, लेकिन 60 दिन का नहीं बल्कि 365 दिन का अध्यक्ष। दरअसल, प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी जबसे सरकार में आई है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लगातार कयास चल रहे हैं। लेकिन कोरोना के कारण अभी तक प्रोटेम स्पीकर से काम चलाया जा रहा है। अब जब प्रदेश में उनकी पार्टी की मजबूत सरकार है और कोरोना का कहर भी कमजोर पड़ता दिख रहा है, ऐसे में माननीय की इच्छा अध्यक्ष बनने की जागृत हो गई है। माननीय परिपक्व राजनेता हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के जानकार भी हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या उनकी मंशा पूरी हो पाती है।

10 हजार की साड़ी, 8 हजार से हारी

शीर्षक पढ़कर आप भी आश्चर्यचकित हुए होंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के शीर्षक आश्चर्यजनक होते ही हैं। लेकिन शीर्षक एकदम सत्य घटना पर आधारित है। दरअसल, उपचुनाव के दौरान एक विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार की साड़ी वाली प्रत्याशी की खूब चर्चा रही है। जिस प्रत्याशी की यहां चर्चा हो रही है, वे पूर्व में कई चुनाव बड़े अंतर से जीतती आई थीं। उन्हें इस बात का गुमान था कि उनके क्षेत्र की जनता उपचुनाव में भी उन्हें बड़ी जीत दिलवाएगी। लेकिन जनता को माननीया उपचुनाव में तनिक भी नहीं भायीं। इसकी वजह यह है कि अपने आप को गरीब और दलित की बेटी बताने वाली माननीया 10 हजार रुपए की साड़ी पहनकर विधानसभा क्षेत्र में घूम रही थीं। अपनी हर बैठक और सभा में यही कहती थीं, कि मैं गरीब और दलित की बेटी हूं। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक वोट देकर मुझे जिताएं। उनकी हाईप्रोफाइल गरीबी क्षेत्र के बहुसंख्यक मतदाताओं को बिलकुल नहीं भायी। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने उनकी नई पार्टी के पदाधिकारियों से साफ-साफ शब्दों में कह दिया था कि ऐसी गरीब की बेटी को हम कतई वोट नहीं देंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि 10 हजार की साड़ी वाली गरीब की बेटी 8 हजार वोट से चुनाव हार गईं।

रेत का कर्ज चुकाया

इस बार के उपचुनाव में एक मंत्रीजी की रिकार्डतोड़ जीत प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी पूर्व पार्टी से बगावत करके नई पार्टी में शामिल होने वाले इन माननीय के खिलाफ इनके क्षेत्र में जबरदस्त एंटी इनकंबेंसी थी। आशंका जताई जा रही थी कि उपचुनाव में मंत्रीजी बुरी तरह हार जाएंगे। इसकी एक वजह यह भी थी कि क्षेत्र के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री और उनके पुत्र ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन इन सबके बावजूद माननीय ने रिकार्डतोड़ जीत दर्ज की। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि इस विधानसभा और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने रेत का कर्ज चुकाते हुए माननीय के पक्ष में जमकर जमावट की थी। सूत्र बताते हैं कि माननीय के विधानसभा क्षेत्र में स्थिति खराब होने की खबर मिलते ही सरकार के मुखिया ने उन्हें जिताने का जिम्मा संभाला। उन्होंने उनके क्षेत्र में न केवल खूब सभाएं कीं, बल्कि अपने नाते-रिश्तेदारों को उन्हें जिताने की जिम्मेदारी देकर मैदान में उतार दिया। सरकार के मुखिया और उनके रिश्तेदारों की मेहनत दिन पर दिन फलीभूत होती गई और उपचुनाव में माननीय मंत्रीजी को रिकार्ड वोटों से जीत मिली। जीत मिलने के बाद माननीय गर्दन ऊंची करके चल रहे हैं और कहते फिर रहे हैं कि मैंने कमाल कर दिखाया। जबकि पूरी मेहनत सरकार के मुखिया और उनके नाते-रिश्तेदारों ने की है।

आला अफसरों की आफत

हर आईएएस और आईपीएस का ख्वाब रहता है कि वह राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में पदस्थ रहे। इंदौर तो अफसरों के लिए स्वर्ग साबित होता है, लेकिन जो अफसर भोपाल में पदस्थ होता है, उसकी आफत आ जाती है। खासकर पुलिस विभाग के अफसरों के लिए तो भोपाल में पदस्थापना किसी चैलेंज से कम नहीं है। भोपाल में डीआईजी बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जब किसी अफसर की पदस्थापना होती है तो वह राजनीति की चक्की में गेहूं की तरह पिसने लगता है। यही हाल पुराने शहर के एसपी का भी होता है। देखने में यह आया कि इन दोनों पदों पर जो भी अफसर पदस्थ होता है, वह नित्य नए आरोपों से घिरा रहता है। आलम यह है कि अगर वह किसी नेता से नजदीकी बढ़ाता है, तब भी उसकी मुश्किल बढ़ जाती है और नहीं बढ़ाता है, तब भी। स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। वर्तमान में भोपाल में पदस्थ डीआईजी की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। उन्हें यहां से चलता करने के लिए सत्तारूढ़ दल पूरी तरह घेराबंदी कर रहा है।

ऊपरी कमाई का कमाल

जब किसी विभाग में ऊपरी कमाई होती है तो उस पर सबकी नजर लगी रहती है। मप्र में ऊपरी कमाई वाले एक विभाग की ऊपरी कमाई ने इस बार उपचुनाव में कमाल कर दिखाया है। दरअसल, इस विभाग के मंत्री रहे माननीय भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। भले ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अघोषित तौर पर वे विभाग के मंत्री ही थे। सो, उन्होंने विभाग से होने वाली ऊपरी कमाई का उपयोग उपचुनाव में अपनी विरोधी पार्टी के नेताओं पर न्यौछावर किया। गौरतलब है कि माननीय पूर्व में उसी पार्टी के नेता रह चुके हैं। अत: वे जानते थे कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किस नेता की क्या साख है। उन्होंने साखदार नेताओं को ऊपरी कमाई से उपकृत किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि विपक्षी पार्टी को 16 हजार बूथों पर एजेंट ही नहीं मिले। इससे न केवल माननीय को जीत का स्वाद मिला, बल्कि उनकी पार्टी के कई नेताओं की नैय्या पार लग गई। माननीय ने एक तीर से कई शिकार करके अपनी नई पार्टी के दिग्गज नेताओं का विश्वास भी हासिल कर लिया।

भ्रम में रहकर कोई काम मत करिए। कन्फ्यूज व्यक्ति न सिर्फ डरा हुआ होता है, बल्कि असफल भी होता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन जब भ्रमित हुए तो कृष्ण उनकी स्थिति को समझ गए और उनका कन्फ्यूजन दूर किया।

● **पंडित विजयशंकर मेहता**

इस बार आईपीएल का सीजन हमारे लिए वैसा नहीं रहा जैसी हमें उम्मीद थी, पर हम और बेहतर तथा मजबूत बनकर अगले साल आएंगे। कई रोमांचक मुकाबले दिल की धड़कनें रोक देने वाले और यादगार लम्हे इस साल हमें मिले। यह सफर उतना लंबा नहीं था, फिर भी रोमांचक रहा। मैं फैंस को शुक्रिया कहना चाहती हूं, जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहे।

● **प्रीति जिंटा**

मोदी सरकार में ईवीएम नहीं बल्कि एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन चलती है। देश को गुमराह करने के लिए मोदी और उनकी सरकार तरह-तरह के प्रपंच रचते रहती है। लॉकडाउन करके देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने तथा करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने के बावजूद मोदी अपने आपको देश का सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते हैं।

● **राहुल गांधी**

भारत के निशाने पर हमेशा पाकिस्तान रहता है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए भारत कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन हम विश्व समुदाय को बता दें कि पाकिस्तान अपने पड़ोस से बेहतर संबंध बनाए रखना चाहता है।

● **इमरान खान**

अगर आज मैं सिंगल हूं तो सिर्फ अजय देवगन की वजह से ही हूं। मैं और अजय 25 साल से एक-दूसरे को जानते हैं। वे मेरे कजिन समीर आर्य के पड़ोसी और क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। जब मैं छोटी थी तो समीर और अजय मुझ पर कड़ी नजर रखते थे और जिस भी लड़के को मुझसे बात करते देखते, उसे पीट दिया करते थे। दोनों बहुत बड़े गुंडे थे। अब मैं हर दूसरे दिन अजय से कहती हूं कि मेरे लिए सूटेबल लड़का ढूंढो। लेकिन वह ध्यान ही नहीं देता है। वैसे मेरा और अजय का रिश्ता काफी अच्छा है। सभी मेल एक्टर्स में से अगर मेरे लिए कोई ज्यादा मायने रखता है तो वह अजय है।

● **तब्बू**

वाक्युद्ध

कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ है। कांग्रेस पार्टी जम्मू-कश्मीर से धारा-370 बहाल करने को लेकर एजेंडा चला रहे पीपल्स अलायंस फार गुपकर के साथ है। यह गुपकर अलायंस है या गुप्तचर अलायंस है। धारा-370 को बहाल कराना गुपकर का एजेंडा है। इस एजेंडे को चलाने में कांग्रेस भी उनके साथ शामिल है।

● **संबित पात्रा**

कांग्रेस को अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि कांग्रेस कितनी देशभक्त है। भाजपा अपने आप को देशभक्त बताने के लिए एजेंडा बनाए। पिछले छह साल के दौरान भाजपा ने अपने आप को देशभक्त और दूसरों को देशद्रोही बताने का ही तो काम किया है।

● **रणदीप सिंह सुरजेवाला**

बजट पर पहरा

मप्र में उपचुनाव के बाद शिवराज सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संकट है। क्योंकि सरकार की आमदनी में भारी गिरावट आ चुकी है और खर्चे बढ़ गए हैं। कोरोनाकाल में भी सरकार ने हितग्राही मूलक योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि सरकार के सामने उपचुनाव था। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश को स्वयं और केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में कमी आई है। इसका असर बजट पर भी पड़ा है। लोक निर्माण, जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा सहित 8 विभागों को छोड़कर 44 विभागों को स्वीकृत बजट का 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा खर्च करने की अनुमति नहीं दी गई है। पिछले साल की आर्थिक मंदी और इस साल कोरोना संकट से प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और राज्य करों से होने वाली आमदनी को मिलाकर करीब 15 हजार 815 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सरकार को अपने जरूरी खर्चे चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। पिछले 7 माह में सरकार 11,500 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले चुकी है। दूसरी तरफ, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ सरकार को कई छूट देनी पड़ रही है। इसका असर भी खजाने पर पड़ रहा है। यही वजह है कि कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की आखिरी किश्त, वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते में वृद्धि का भुगतान रोकना पड़ा।

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना, लाडली लक्ष्मी, हाउसिंग फॉर ऑल, मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना, निर्मल भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमृत योजना अशासकीय, स्कूलों को आरटीआई के तहत ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, समेत 21 योजनाओं में बगैर वित्त विभाग की अनुमति के भुगतान करने पर भी रोक लगा दी गई है। वित्त सचिव ने बजट अनुमान को लेकर विधानसभा में एक स्मृति पत्र भी पेश कर दिया है जिसके मुताबिक कोरोना महामारी के कारण केंद्र और राज्य की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा है। स्वयं के कर और केंद्रीय करों के हिस्से से मिलने वाली राशि में 15 हजार 815 करोड़ रुपए की कमी रहने की संभावना है। केंद्र सरकार ने फरवरी में जो बजट अनुमान प्रस्तुत किया था तब मप्र को केंद्रीय करों की राशि 61,840 करोड़ रुपए प्रस्तावित की थी, लेकिन कोरोना के कारण स्थिति बदल चुकी है। अब राजस्व में कमी और वर्ष 2019-20 में प्राप्त 4400 करोड़ रुपए अधिक राशि का सहयोग समायोजन करते हुए सरकार को यह राशि देगी। वहीं, राज्य के स्वयं के कर से 48 हजार 801 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है।

अनुमानत: प्रदेश पर करीब 2 लाख 28 हजार 181 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें सर्वाधिक 1 लाख 54 हजार 604 करोड़ रुपए का ऋण बाजार, 29,251 करोड़ रुपए अल्प बचत, 24,856 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, 11,572 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया जा चुका है। एफआरबीएम के तहत मप्र को जीडीपी से 3.5 प्रतिशत तक का बिल लेने की मंजूरी है। इस हिसाब से मप्र सरकार इस वित्तीय साल में औसत 34 हजार करोड़ रुपए तक कर ले सकती है। शिवराज सरकार ने गत दिनों बाजार से 1 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इससे पहले 7, 13 और 21 अक्टूबर को सरकार बाजार से 1-1 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। शिवराज सरकार अपने 7 माह के कार्यकाल में 9वीं बार कर्ज ले रही है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 4 अक्टूबर को 20 साल के लिए एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी की गई है। केंद्र से अतिरिक्त मदद लेना मुश्किल रहेगा क्योंकि केंद्र के राजस्व में भी कमी आई है। कोरोना के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। इसलिए अतिरिक्त टैक्स लगना आसान नहीं। जीएसटी के कारण टैक्स की भी लिमिट है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य 16 हजार 100 करोड़ रुपए है। इसमें से 8 हजार 663 करोड़ रुपए अक्टूबर तक जमा हो चुके हैं। हालांकि यह भी पिछले साल के अक्टूबर तक हुए कलेक्शन से 22 फीसदी कम है। वित्तीय वर्ष 2019-20 अक्टूबर तक 11 हजार 157 करोड़ रुपए एकत्रित हो चुके थे। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने से मप्र की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। लॉकडाउन लगने के तीन-चार महीनों में प्रदेश सरकार ने सोचा था कि जीएसटी कलेक्शन में 30 से 40 फीसदी की कमी रहेगी। यह अक्टूबर में 22 प्रतिशत पर पहुंच गई। अनुमान है कि यह नवंबर-दिसंबर में और घटेगी।

● **नवीन रघुवंशी**

जीएसटी कलेक्शन से आस

कोरोनाकाल के कारण आई आर्थिक मंदी अब प्रदेश से भी मंद पड़ने लगी है। इसके संकेत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ताजा संग्रह से मिले हैं। प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले इस साल अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में 35 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। यह अभी तक किसी भी महीने में बढ़ोतरी का रिकॉर्ड है। इसके पीछे ऑटो-मोबाइल, पार्ट्स, रेडिमेड सेक्टर, जनरल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ड्रायफ्रूट और टाइल्स के साथ अन्य कारोबार में बढ़ोतरी को बड़ी वजह माना जा रहा है। यही रफ्तार और सकारात्मकता नवंबर से मार्च तक बनी रही तो मप्र स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी के कलेक्शन के लक्ष्य को 80 से 90 प्रतिशत तक हासिल कर लेगा। राज्य सरकार ने व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने स्तर से भी कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस और सातवें वेतनमान के एरियर की अंतिम किश्त का 25 प्रतिशत देकर प्रयास किए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग का मानना है कि नवंबर में भी ग्रोथ बरकरार रहेगी। सितंबर और अक्टूबर में मिली ग्रोथ की मुख्य वजह यह भी है कि कोरोना संक्रमण के कारण अप्रैल, मई, जून, जुलाई में न कोई कारोबार हुआ और न ही रिटर्न दाखिल हुए। अगस्त से व्यापारियों ने कारोबार खोला तो रिटर्न भी जमा हुए। अक्टूबर में इतनी बड़ी ग्रोथ का यह एक प्रमुख कारण है। अच्छा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर के साथ फरवरी-मार्च में होता है। नवंबर में भी ग्रोथ रह सकती है।

राजनीति नहीं राष्ट्रनीति

संघ प्रमुख मोहन भागवत की हर गतिविधि को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। खासकर संघ प्रमुख जब भी मप्र आते हैं तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। नवंबर के पहले पखवाड़े में संघ प्रमुख 4 दिन भोपाल में रहे। इस दौरान 5 और 6 नवंबर को बैठक आयोजित कर पदाधिकारियों के साथ मंथन हुआ। इस बार के मंथन में राजनीति पर नहीं बल्कि राष्ट्रनीति पर चर्चा की गई। संघ प्रमुख ने पदाधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के दौरान चलाए गए कार्यों के साथ ही प्रवासी मजदूरों के रोजगार पर चर्चा की।

मप्र में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव के ठीक एक दिन बाद यानी 4 नवंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंचे तो राजनीतिक हलचलें तेज हो गईं। प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। कोई उनके इस दौरे को उपचुनाव से जोड़कर देख रहा था तो कोई सरकार बनाने से लेकर। लेकिन राजधानी के शारदा विहार में 2 दिन तक क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने राजनीति पर कोई चर्चा नहीं की।

दरअसल, संघ कोरोना वायरस के कारण देश में आई आपदा को अवसर में बदलने में जुटा हुआ है। इसके तहत संघ लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने में जुटा हुआ है। इसी की समीक्षा के लिए मोहन भागवत बार-बार भोपाल आ रहे हैं।

संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बैठक में संघ प्रमुख ने मार्च से नवंबर तक के कार्यों की समीक्षा की। भोपाल से पहले ये बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। भोपाल की बैठक में संघ के मध्यक्षेत्र (मध्यभारत, मालवा, महाकौशल और छत्तीसगढ़) की प्रांत टोली, क्षेत्र टोली और मध्य क्षेत्र में रहने वाले केंद्रीय अधिकारी मौजूद थे। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर साल अखिल भारतीय स्तर पर कार्यकारी मंडल की बैठक करता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण यह बैठक केंद्रीय स्तर पर आयोजित न होकर क्षेत्रवार की जा रही है। संघ की भौगोलिक रचना के अनुसार पूरे देश में 11 क्षेत्र हैं जिनमें से एक मध्य क्षेत्र भी है। इसी मध्य क्षेत्र की बैठक 5 और 6 नवंबर को भोपाल में हुई।

गौरतलब है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल में लगातार दौरे हो रहे हैं। इससे पहले बीते 5 महीने के भीतर ही संघ प्रमुख मोहन भागवत तीन बार भोपाल आ चुके हैं। भोपाल में उन्होंने न केवल प्रांतीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ भी अहम बैठकें की हैं। यह माना जा रहा है कि संघ मप्र में अपनी पैठ और मजबूत कर रहा है जो संगठन के साथ-साथ राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है। संघ की नजर कहीं न कहीं मप्र में लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर भी है। लेकिन उससे अधिक कोरोनाकाल की गतिविधियों पर इस समय संघ का फोकस है।

संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि कैसे प्रवासी मजदूरों को उनके गांवों और कस्बों में काम मिले संघ इसकी योजना बना रहा है। इसका पूरा फोकस सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर के आव्हान पर रखा गया है। संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि **संगठन के स्वयंसेवकों ने** प्रवासी श्रमिकों के लिए जिला स्तर पर एक सर्वेक्षण किया था। पदाधिकारी के अनुसार, सर्वे में पता चला कि कुछ लोग तो जहां जिस शहर में काम करते थे वहां वापस जाने की इच्छा व्यक्त की है जबकि अधिकतर ने कहा है कि वे अपने गांवों और कस्बों में ही नौकरी करना चाहते हैं।

फीडबैक के आधार पर, संघ अपने गांवों के विकास के माध्यम से उन संस्थानों तक पहुंच बना रहा है जो प्रवासी श्रमिकों को नौकरियों में मदद कर सकते हैं। संघ ने कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे इंस्टीट्यूट से भी इस मामले में संपर्क किया है जो प्रवासियों को नौकरी दे सकते हैं। इस अधिकारी ने आगे कहा कि प्रवासियों में से अधिकांश उप्र, पश्चिम बंगाल, मप्र और बिहार वापस लौट गए थे। इसी अधिकारी ने बताया, कई प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि उनके मौजूदा स्किल के आधार पर, वे अपने गांव और कस्बों में ही नौकरी करना चाहते हैं। इसी

अब छोटी-छोटी टोलियों में लगेंगी शाखाएं

भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्षेत्रीय बैठक के तीसरे दिन सरसंघचालक मोहन राव भागवत ने कहा कि कोरोनाकाल में संपर्क में आए नए कार्यकर्ताओं को सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि सरकारों के भरोसे समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब छोटी-छोटी टोलियों में शाखाएं लगाई जाएंगी। स्वावलंबन का भाव समाज में स्थाई रूप से स्थापित हो, इसके लिए प्रयास करना है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोनाकाल में किए गए सेवा कार्य से समाज में संघ के प्रति विश्वास बढ़ा है। बैठक में सरकार्यवाह भैयाजी जोशी के अलावा मध्य प्रांत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पदाधिकारियों ने बताया कि देशभर में पर्यावरण संरक्षण हेतु स्वयंसेवकों द्वारा कई प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें जल संरक्षण के लिए संघ के विभिन्न संगठन तथा कार्यकर्ता बोरी बंधान करके जल को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। बैठक में कोरोनाकाल के दौरान संघ की भूमिका पर चर्चा हुई। इस दौरान तय किया गया कि अगले दो साल तक सेवा कार्यों पर ही फोकस किया जाएगा। यानी सेवा भारती को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ताकि समाज के बीच अधिक से अधिक काम हो सके। हालांकि इसका लाभ भविष्य में भाजपा को ही होगा।

फीडबैक के आधार पर संघ श्रमिकों को रोजगार देने की कार्ययोजना बना रहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर कहते हैं कि सेवा, अनुशासन, संयम और देशभक्ति ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान है। देश पर कोई भी आंच आने पर संघ अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर राष्ट्र व समाज की मदद के लिए सेवा कार्य करता रहा है। कोरोनाकाल में भी संघ द्वारा वृहद स्तर पर जरूरतमंदों के लिए मुहिम जारी रही। उन्होंने बताया कि विशेष तौर पर राष्ट्र व संस्कृति की अलख जगाने के लिए संघ द्वारा कुटुंब शाखाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें स्वयंसेवक अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर उन्हें देशभक्ति व संस्कारों की सीख दे रहे हैं। इसमें नए परिवारों को भी जोड़ा जा रहा है।

सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि संघ समय के साथ-साथ व परिस्थितियों के अनुसार अपने में परिवर्तन करता रहा है। कुटुंब शाखा उसी का एक उदाहरण है। कोरोना संक्रमण के चलते संघ ने पहली बार सामूहिक शाखा को निरस्त किया। ऐसे में स्वयंसेवकों को सक्रिय बनाए रखने के लिए कुटुंब शाखा का संचालन हो रहा है। जिसमें स्वयंसेवक परिवार के साथ संघ के विचार व सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। महापुरुषों की गौरव गाथा के बारे में भी युवा पीढ़ी को जानकारी दी जा रही है।

कुटुंब शाखा के बारे में नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इसके माध्यम से लाखों की संख्या में लोग जुड़े। साथ ही संस्कारों को पुनर्जीवित करने और अगली पीढ़ी के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में गति आई है। उप्र-उत्तराखंड के प्रचार प्रमुख कृपाशंकर कहते हैं कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्वयंसेवक बिना भेदभाव किए मदद के लिए आगे आ रहे हैं। संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख अजय मित्तल ने बताया कि लॉकडाउन में संघ ने आगे बढ़कर सेवा कार्य किए। मप्र में भी

संघ के स्वयंसेवकों ने हर जिले में जरूरतमंदों के यहां भोजन के साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई।

देश का हृदय प्रदेश होने के कारण संघ प्रमुख के दिशा-निर्देश पर संघ भोपाल को केंद्र में रखकर देशभर में कोरोनाकाल में सामाजिक कार्य कर रहा है। इसलिए संघ प्रमुख लगातार मप्र का दौरा कर कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। दो दिवसीय इस बैठक के पहले दिन कोरोनाकाल के दौरान संघ की भूमिका पर चर्चा हुई। इस दौरान तय किया गया कि अगले दो साल तक सेवा कार्य में फोकस रहेगा इसके लिए संघ का चेहरा बदलने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संघ का फोकस सेवा भारती और विद्या भारती सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने पर रहेगा। संघ मूल रूप से शाखा आयोजित करता है, लेकिन इसके साथ अनुषांगिक संगठन विद्यार्थी परिषद और मजदूर संघ भी सक्रिय भूमिका में हैं। बैठक में तय किया गया है कि सेवा भारती और विद्या भारती को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ताकि समाज के बीच अधिक से अधिक काम हो सके। हालांकि इसका लाभ भविष्य में भाजपा को ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर होगा। संघ के पदाधिकारी यह भी मानते हैं कि अब समय के साथ बदलाव भी जरूरी है।

संघ के सूत्र बताते हैं कि कोरोनाकाल में वर्चुअल शाखा संघ के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। संघ ने **अपने प्रचारकों** के साथ इस बात पर मंथन भी किया था कि वर्चुअल शाखा संघ के दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बन सके जो कोरोनाकाल में सफल रहा। कोरोनाकाल के लंबा रहने से संघ ने अपनी गतिविधियों को वर्चुअल माध्यम से जारी रखा और संघ काफी हद तक वर्चुअल प्लेटफार्म को अब स्वीकार कर चुका है। परिवार शाखाओं में शामिल होने वाले संघ के स्वयंसेवक भी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर राष्ट्रवाद की भावनाएं एक-दूसरे को साझा कर रहे हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

मलिन से मुस्लिम बस्तियों तक

संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं कि 'संघ किरण घर-घर देने को अगणित नंदादीप जलें, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा दिनरात गलें।' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा गीत के ये शब्द स्वयंसेवकों पर अक्षरशः खरे उतरते हैं। आपदा की जिस घड़ी में लोग अपने घरों से निकलना सुरक्षित नहीं मानते। वहां हजारों स्वयंसेवक अपनी परवाह किए बगैर गरीबों और जरूरतमंदों की भूख मिटाने में जुटे हैं। बिना प्रचार-प्रसार के उनकी मौन साधना सुबह चाय वितरण से देर रात भोजन बांटने तक चलती है। जरूरतमंद लोगों की भूख मिटाने का काम संघ की ओर से किया जा रहा है। सामान्य दिनों में शाखा के जरिए समाज को मानसिक और वैचारिक रूप से स्वस्थ बनाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आपदाकाल में सबसे बड़ी चुनौती का बीड़ा उठाए हुए है। यह कार्य है लॉकडाउन के कारण घरों में बंद हुए लोगों तक भोजन पहुंचाने का। इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत स्वयंसेवकों ने घर-घर तक पका हुआ भोजन से लेकर राशन सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया। यह सेवा कार्य समान रूप से चल रहा है, चाहे वह हिंदू बाहुल्य इलाका हो या फिर मुस्लिम बाहुल्य कैंट। क्षेत्र की मजदूर व मुस्लिम बस्तियों में भोजन पहुंचाने का दायित्व संभाल रहे संदीप कहते हैं कि सेवा कार्य में भेदभाव कैसा? संघ सबको समान मानता है। सुबह से लेकर देर रात तक सारे प्रबंध देखने वाले कानपुर पश्चिम के जिला प्रचारक प्रवीण थक जाते होंगे? इस सवाल पर वे कहते हैं कि दूसरों की सेवा से जो आनंद मिलता है, वह थकावट आने ही नहीं देता। स्वयंसेवक तो अर्हिनश काम करता है।

स्मार्ट सिटी की कछुआ चाल

मप्र के चारों महानगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लगभग एकसाथ शुरू हुए थे, लेकिन भोपाल को छोड़कर किसी अन्य शहर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। प्रदेश के चारों महानगरों में से ग्वालियर स्मार्ट सिटी की रफ्तार सबसे धीमी है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि शहर के विकास को गति नहीं मिल पा रही है। वहीं स्मार्ट सिटी का फंड दूसरे शहरों को ट्रांसफर किया जा रहा है।

ग्वालियर स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी चाल से नगरीय प्रशासन आयुक्त ने भोपाल स्मार्ट सिटी के खाते में 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा दिए हैं। भोपाल स्मार्ट सिटी से अगर समय पर पैसा वापस नहीं मिला तो आने वाले समय में ग्वालियर के विकास में पैसों की कमी आड़े आ सकती है। वहीं पैसे जाने के मामले को तूल पकड़ता देख नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन ने कहा है कि पैसे जल्द ही वापस आ जाएंगे।

ग्वालियर स्मार्ट सिटी के खाते में वर्तमान में 250 करोड़ के करीब रुपए जमा है। इस राशि का उपयोग वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्टों एवं नवीन प्रोजेक्टों के लिए किया जाना है। लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकांश प्रोजेक्ट कछुए की गति से चल रहे हैं। इसके कारण इस राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहीं भोपाल स्मार्ट सिटी को किन्हीं प्रोजेक्टों के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने नगरीय प्रशासन आयुक्त से पैसों की मांग की। इस मांग को देखते हुए उन्होंने ग्वालियर स्मार्ट सिटी के खाते से 50 करोड़ रुपए भोपाल स्मार्ट सिटी के खाते में ट्रांसफर करने का आदेश नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन को दिया। इसके बाद ग्वालियर स्मार्ट सिटी के खाते से यह पैसा भोपाल स्मार्ट सिटी के खाते में ट्रांसफर किया गया है।

मप्र में भोपाल स्मार्ट सिटी का काम सबसे तेजी से चल रहा है। जहां तक ग्वालियर स्मार्ट सिटी का सवाल है तो यहां स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट कछुआ चाल से चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी ग्वालियर के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट अभी तक योजना में है तो कई प्रोजेक्टों पर अभी तक कार्य भी प्रारंभ नहीं हो पाया है। स्वर्ण रेखा नदी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के पास है, लेकिन अभी तक स्वर्ण रेखा नदी में यह निर्णय नहीं हो पाया है कि इसमें क्या किया जाए कि इसके अंदर साफ पानी बहे। साथ ही अभी तक यह भी निर्णय नहीं हो पाया है कि इसे किस प्रकार सुंदर बनाया जाए, इस पर सड़क बनाई जाए, अथवा पुल बनाया जाए। वहीं अमृत योजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी में फिर से सीवर की लाइन डाली जा रही है। अगर यह सीवर लाइन नदी के किनारे सड़क के नीचे डाली जाती है, और नालों के पानी को साफ कर फिर इसे स्वर्ण रेखा नदी में छोड़ा जाता तो पानी साफ बह सकता है। लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है।

शहर में करीब 241 करोड़ रुपए की लागत से शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए स्मार्ट रोड बनाई जानी है। लेकिन अभी तक इसकी टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जानी है। इसके लिए जगह-जगह स्टेशन एवं बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने है। इस पर सरकार की 40 प्रतिशत सब्सिडी भी है। लेकिन अभी तक यह कागजों में ही है। शहर की सड़कों पर स्मार्ट सिग्नल लगाए जाने हैं, लेकिन अभी तक यह भी कार्य धीमी गति से चल रहा है। मोती महल का सौंदर्यीकरण किया जाना है, इसके अभी एक हिस्से जिसमें कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना हुआ है, यह भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। अभी भी इसके एक हिस्से में कार्य किया जा रहा है। जबकि हालत यह है कि स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों और अधिकारियों के पास बैठने के लिए पर्याप्त कैबिन तक नहीं बने हैं।

वहीं टाउन हॉल के सौंदर्यीकरण का कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के प्रारंभ होने से पहले का चल रहा है। लेकिन अभी तक यह पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है, इसके कारण इसका अभी तक लोकार्पण नहीं हो सका है। तारामंडल (प्लेनिटोरियम) बनाने के लिए गोरखी स्काउट को स्मार्ट सिटी ने लिया है। लेकिन यहां पर अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका है, जबकि स्काउट को निगम ने 2019 में अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही इसकी अभी तक रेट भी निर्धारित नहीं हो सकी हैं। ऐसे में ग्वालियर में स्मार्ट सिटी का काम बाधित पड़ा है।

● **अरविंद नारद**

2300 करोड़ का प्रोजेक्ट

केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी की सूची में ग्वालियर को भी शामिल कर दिया है। इसके लिए नगर निगम ग्वालियर ने करीब 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंट मेहता एंड मेहता द्वारा तैयार कर केंद्र को भेजे थे। उक्त प्रोजेक्ट में महाराज बाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में रेक्ट्रोफिटिंग कर विरासत को संजोते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए गत वर्ष केंद्रीय मंत्री वैंकैया नायडू की ग्वालियर यात्रा के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महापौर विवेक शेजवलकर और तत्कालीन निगमायुक्त अनय द्विवेदी ने दिल्ली जाकर नायडू से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर शहर के प्रजेंटेशन से संबंधित जानकारी को साझा किया था। जिस पर नायडू ने तोमर को सकारात्मक परिणाम के लिए आश्वस्त भी किया था। ग्वालियर के स्मार्ट सिटी बनाने का रास्ता साफ होने के बाद शहर के लोगों को लगा था कि उन्हें भी देश-दुनिया के स्मार्ट शहरों के जैसी सुविधाएं ही मिल सकेंगी। पुरातात्विक स्थलों का न केवल संरक्षण होगा, वरन उनके आसपास से गुजरने पर भी राजसी माहौल जैसी अनुभूतियां होगी। सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी, लेकिन अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण स्मार्ट सिटी निर्माण की गति तेज नहीं हो पा रही है। इससे शहर के लोगों में निराशा का भाव है। उधर, स्मार्ट सिटी का 50 करोड़ रुपए भोपाल ट्रांसफर होने से लोगों को यह लगने लगा है कि शासन-प्रशासन ग्वालियर की जगह भोपाल को प्राथमिकता दे रहा है।

गरीबों के भाग्य में सड़ा-गला

मप्र में गरीब व कुपोषितों के घरों में बांटने के लिए शासन स्तर से भेजे गए चने की बोरियां खोली गईं तो उसमें से चने के साथ कीड़े निकल रहे हैं। कीड़े लगने से चना पूरी तरह खराब हो चुका है। बावजूद इसके चने की रैक उतारी गई और बांटने के लिए बिना जांच के ही अफसरों ने इसे उचित मूल्य दुकानों पर सप्लाई कर दिया। श्योपुर में मामले का खुलासा होने के बाद अब अन्य जिलों से सैम्पल मंगाए जा रहे हैं।

गरीबों व कुपोषितों को पोषित करने के लिए मूंग दाल के बाद अब चना बांटा जा रहा है। हाल ही में शासन स्तर से 106 मीट्रिक टन चना बांटने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को सप्लाई किया गया। जिसे निगम ने खाद्य आपूर्ति विभाग को दे दिया और खाद्य आपूर्ति विभाग ने बिना जांचे ही यह चना गरीबों में बांटने के लिए उचित मूल्य दुकानों पर भेज दिया। इस चने की खराब क्वालिटी की पोल तब खुल गई, जब पांडोला गांव के उचित मूल्य दुकान पर चना बांटने के लिए बोरी खोली गई। इसमें चने के साथ कीड़े भी निकले जिसने चने खाकर उन्हें खोखला कर दिया था। भेजे गए चने को लेकर लोगों ने कहा कि यह जानवरों के खाने लायक भी नहीं है और इसे हमें भेजा गया। अब इस पर अफसरों का तर्क है कि वह मामले की जांच कराएंगे और खराब चने को वापस भेज देंगे। इस चने को अब बांटा नहीं जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम को मिला 106 मीट्रिक टन चना नेफेड द्वारा भेजा गया था जिसे 6 माह से अधिक समय से स्टॉक कर रखा गया था। अब जब चने में कीड़े लगने लगे तो आनन-फानन में नाफेड ने इसे बांटने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के सुपुर्द कर दिया और नागरिक आपूर्ति निगम ने गुणवत्ता जांचे बिना ही इसे खाद्य आपूर्ति विभाग को गरीबों में बांटने के लिए भेज दिया। बावजूद इसके नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों का कहना है कि पुराने चने व चावल में तो कीड़े लग ही जाते हैं चाहे वह सरकारी हो या फिर निजी।

खराब चने को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर शासन व प्रशासन को जमकर कोसा। लोगों ने कहा कि जब बांटने का समय था तब तो स्टॉक में रखा और अब खराब होते ही जिसे जानवर भी न खाएं, उस चने को गरीबों में बांटने के लिए भेजा गया जबकि नियम है कि कोई भी खाद्य सामग्री बिना जांचे उचित मूल्य दुकानों पर नहीं आती। बावजूद इसके कीड़े लगा बदबूदार व खोखला चना भेजा गया। नागरिक आपूर्ति निगम श्योपुर के डीएम डीएस कटारे कहते हैं कि हमें नाफेड से उक्त चना बांटने के लिए प्राप्त हुआ है। कहीं कोई एक-दो बोरी में ही दिक्कत होगी। इसे हम वापस करवा देंगे। बाकी उचित मूल्य दुकानों का चना भी चेक कर लेंगे। इसमें हमें 106 मीट्रिक टन चना प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच कराएंगे।

बटेगा 9 पोषक तत्वों से तैयार चावल

सामान्य चावल को अब विटामिन और मिनरल्स से युक्त करके लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। इसे 'फोर्टिफाइड राइस केरनेल्स' कहा जाएगा। मिलिंग प्लांट में तैयार इस पोषण युक्त चावल के एक दाने को 100 दानों में मिलाकर उन जिलों में वितरित किया जाना है, जहां अनुसूचित जाति-जनजाति के ऐसे लोग रहते हैं, जिन्हें पोषण की जरूरत है। भारत सरकार ने देश के पंद्रह राज्यों के एक-एक जिले में इसे लागू किया है, मप्र का सिंगरौली जिला इस स्कीम में शामिल है। बाद में इसे राज्यों के आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार इस स्कीम में 174 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्यों को 25 फीसदी पैसा मिलाना होगा। पांच राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने इसे लागू कर दिया, लेकिन मप्र में फाइल मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन और वित्त में अटकी है। फोर्टिफाइड राइस आंगनबाड़ी, मिड-डे-मील और पीडीएस के जरिए दिया जाएगा। मप्र में इससे पहले मई-जून 2018 से फोर्टिफाइड नमक दिया जा रहा है। एक किलो चावल पर 73 पैसे खर्च होंगे- एक किलोग्राम चावल के फोर्टिफिकेशन पर 73 पैसे खर्च होंगे। इसमें से 75 फीसदी केंद्र सरकार को और शेष राशि राज्यों को देनी है। तीन साल के इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर इसे बाद में पिछड़े (आकांक्षी) जिलों में लागू कर दिया जाएगा।

सरकार गरीबों की भूख का विशेष ध्यान रखती है। वैसे यह सरकार की मजबूरी भी है। आखिर उन्हीं के वोट से तो सरकार का जन्म होता है। गरीब सरकार को जन्म देने के बाद इसे अभिजात्य झूलाघर में छोड़ने के लिए विवश होते हैं। सरकार वहीं से संस्कार धारण कर शान से सिंहासन पर सवार हो जाती है। सरकार उसके जन्म दाताओं की चिंता कर उन्हें अनाज तो भेज देती है। लेकिन उस अनाज पर भ्रष्टाचार की इल्लियां और लापरवाही की फफूंद लगने से बचा नहीं पाती है। गरीब अनाज के साथ इन्हें भी निगलने के लिए अभिशप्त होता है। गरीब का भूखा पेट सब पचा लेता है। आखिर सरकार एक वोट के बदले गरीबों को छप्पन भोग तो नहीं भेज सकती है।

जनता को देश की पवित्र माटी से प्रेम करना सीखना चाहिए। गुणवत्ताहीन अनाज के साथ यदि यह मिट्टी भी पेट में जाती है तो स्वयं को धन्य समझना चाहिए। यही सच्चा राष्ट्रवाद है। वैसे भी पेट में जाने के बाद अनाज सड़ना ही है। यदि पहले से ही सड़ा हुआ अनाज खा लिया तो कौन-सा आसमान टूट पड़ा। नेता-अफसरों को देखो। ये लोग सड़क, पुल, नहर, कोयला, चारा और न जाने क्या-क्या खा लेते हैं और डकार तक नहीं लेते। और यह जनता है कि देश हित में सड़ा अनाज तक नहीं खा सकती। अब सरकार मुफ्त में बासमती चावल तो बांट नहीं सकती। जो मिल रहा है उसे पकाओ-खाओ और प्रभु के गुण गाओ। सरकार यह तो नहीं कह रही है कि काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। इसलिए निर्भीक होकर सरकारी प्रसाद ग्रहण करो। जब कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाया तो इस सड़े हुए अनाज की क्या बिसात है।

● **राकेश ग्रोवर**

चंबल पर कॉरपोरेट की नजर

दशकों से कुख्यात रहे चंबल को उपजाऊ बनाने के लिए कई प्रयास हो चुके हैं। लेकिन अभी तक सरकार चंबल की किस्मत को बदलने में कामयाब नहीं हो पाई है। एक बार फिर से चंबल को चमन बनाने की कवायद चल रही है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस कवायद में चंबल को कॉरपोरेट को ना सौंप दिया जाए। दरअसल, विश्व बैंक की मदद से चंबल के बीहड़ों के समतलीकरण और इसे कृषि योग्य बनाने हेतु केंद्रीय कृषि मंत्रालय और मप्र सरकार के बीच पिछले दिनों संभावनाओं की तलाश में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान चंबल को उपजाऊ बनाने के मसौदे पर चर्चा की गई। ऐसे में लोगों को उम्मीद जगी है कि चंबल में डकैत की जगह अब फसलें उगेंगी।

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में ग्वालियर-चंबल संभाग की 3 लाख हैक्टेयर परती बीहड़ भूमि हेतु जिस प्लान के लिए योजना विकसित हुई है, उसकी 'पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट रिपोर्ट' पेश होनी है जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। तोमर मानते हैं कि यह परियोजना न सिर्फ क्षेत्र की भूमि को कृषि योग्य बनाएगी बल्कि क्षेत्रीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी मुहैया कराएगी। उन्होंने प्रस्तावित 'चंबल एक्सप्रेस' हाईवे को इस परियोजना से जोड़ते हुए कहा कि इस सबके पूरा हो जाने से समूचे बीहड़ क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास होगा। इसके विपरीत स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस क्षेत्र में कार्यरत पर्यावरणविदों का आरोप है कि इस कथित विकास के पीछे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट की घुसपैठ और स्थानीय किसानों के विनाश का षड्यंत्र छिपा है। उनका यह मानना है कि अगर ऐसा सचमुच घटा तो तबाह हो चुके ये किसान 'बागियों' की नई फौज के रूप में जन्म लेंगे और बीहड़ों में शांति हमेशा-हमेशा के लिए गुम हो जाएगी।

चंबल के बीहड़ों के विकास की मौजूदा योजना कोई नई योजना नहीं है। 1960 से लेकर 1990 के दशकों में दोनों मोर्चों पर पूरे जोर-शोर से 'एक्शन' होते रहे हैं लेकिन अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद इनमें से कोई भी 'कामयाबी की दास्तान' नहीं बन सके हैं। सवाल यह उठता है कि आजादी के बाद के 60 सालों के जिन पुराने रास्तों पर चलकर इन्हें नाकामी मिलती रही है, इस बार भी वही राह चुनी गई है या कोई नई डगर ढूंढी जा रही है? 10 साल तक छोटे-मोटे स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार की माथाफोड़ी के बाद केंद्र सरकार ने 1971 में 'मेगा रेवाइन रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट' चलाया। लक्ष्य था 80 हजार हैक्टेयर बीहड़ भूमि (55 हजार हैक्टेयर बीहड़ भूमि को कृषि योग्य और 25 हजार हैक्टेयर को जंगलातों के लिए) विकसित किया जाए। इस प्रोजेक्ट में मप्र, राजस्थान और उप्र के क्षेत्रों में फैले बीहड़ थे। मजेदार बात यह है कि 25 वर्षों के कार्यकाल में इससे जुड़ी 19 उप परियोजनाओं के बूते केवल 2 हजार हैक्टेयर बीहड़ भूमि का ही पुनरुद्धार हो सका। 1980 और 1990 के दशक में मप्र सरकार के वन विभाग ने 'हवाई बीज विभाग' की स्थापना की ताकि हवाई जहाज के जरिए बीजों का छिड़काव किया जा सके। सरकारी जहाजों द्वारा 'बबूल', 'विलायती बबूल' और 'जंगल जलेबी' आदि के बीजों का छिड़काव हुआ लेकिन कामयाब नहीं हो सका। बीज या तो बारिश में बह गए या बगल के खेतों में चले गए और वहां उगकर किसानों के लिए खेती के कामकाज में बड़ा व्यवधान बनकर खड़े हो गए जबकि भिंड, मुरैना आदि क्षेत्र जबरदस्त उपजाऊ धरती वाले हैं।

नवंबर 2016 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीहड़ को समतल करके कृषि योग्य बनाने हेतु एक नई महत्वाकांक्षी परियोजना को केंद्र के समक्ष भेजा। उक्त परियोजना में मुख्यत: चंबल, सिंध, बेतवा, क्वारी और यमुना की सहायक (ट्रीब्यूट्री) नदियों वाले मुरैना, भिंड और श्योपुर आदि क्षेत्रों के 68,833 हैक्टेयर बीहड़ों को केंद्र में रखा गया था। 1200 करोड़ रुपए के बजट वाली उक्त परियोजना में केंद्र बनाम राज्य के बजट का अनुपात 80:20 था। यानी केंद्र के जिम्मे 900 करोड़ रुपए और शेष राशि राज्य सरकार और उन किसानों के हिस्से में आने का प्रावधान था, जिन्हें भविष्य में उक्त परिवर्धित भूमि मिलती। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही परियोजना साकार होगी।

● **विकास दुबे**

3 लाख हैक्टेयर की योजना

मौजूदा परियोजना में 3 लाख हैक्टेयर बीहड़ भूमि को कृषि और वन क्षेत्र के लिए विकसित करने की बात है। मप्र कृषक कल्याण और कृषि विकास विभाग के अध्ययन के अनुसार बीहड़ में पसरा कुल क्षेत्र 3.97 मिलियन (लगभग 40 लाख) हैक्टेयर है जिसकी चपेट में मप्र, राजस्थान, उप्र और गुजरात राज्य आते हैं। इसमें अकेले मप्र का हिस्सा 70 प्रतिशत (29 लाख हैक्टेयर) है। 6 दशकों की ढेरों कोशिशों के बावजूद उक्त अध्ययन बताता है कि प्रति वर्ष बीहड़ का होने वाला विस्तार 9.5 प्रतिशत है यानी भूमि क्षरण के चलते हर साल बीहड़ 8000 हैक्टेयर भूमि निगल रहा है। तब मौजूदा परियोजना को लेकर 2 सवाल सीधे-सीधे खड़े होते हैं। पहला, कि क्या उन कारणों का अध्ययन किया गया जिनके चलते वे सारे प्रयास और परियोजनाएं फेल साबित हुईं। दूसरा, कि क्या नई परियोजना में नए तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं या पुराने 'प्रयोगों' की ही पुनरावृत्ति होने वाली है। मुख्यतः इस क्षेत्र के बीहड़ों की धरती के साथ 4 प्रकार की कठिनाइयां हैं। पहली तो यह कि यहां की मिट्टी बड़ी कठोर और कड़ी है। यदि इन्हें समतल कर दिया जाए तो वर्षा इन्हें फिर से बीहड़ों में तब्दील कर देती है। दूसरी मुश्किल थी कि सरकारी प्रभुत्व वाली भूमि को किसानों में कैसे स्थानांतरित किया जाए। तीसरी दिक्कत थी कि बहुत से किसानों ने इसे कृषि योग्य बनाने की कोशिश की लेकिन कामयाब कोई न हो सका और चौथा संकट था बीहड़ों को कृषि जोतों में बदलना किसानों के लिए असंभव था।

गहराया केन-बेतवा लिंक परियोजना विवाद

केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत उप्र और मप्र के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। इस मामले में अब शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना में उप्र को 700 एमसीएम से ज्यादा पानी नहीं दिया जाएगा। इस विवाद को हल करने के लिए लगातार उप्र और मप्र सरकार से समन्वय बना रहे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुख्यमंत्री शिवराज ने फोन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार उप्र को 700 एमसीएम से ज्यादा पानी नहीं दे सकेगी। परियोजना जल्द शुरू करने पर आपसी सहमति बनाने पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परियोजना पूरा करने के लिए दोनों राज्यों के साथ जल्द बैठक करने की बात कही है।

बीते साल की तुलना में इस साल प्रदेश में दो लाख हैक्टेयर से ज्यादा सिंचाई करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने के लक्ष्य पर काम करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। बीते साल 29 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हुई थी। इस साल 31 लाख हैक्टेयर में सिंचाई करने का लक्ष्य तय किया गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर मप्र और उप्र सरकार के बीच विवाद चला आ रहा है। इस विवाद को निपटाने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में अक्टूबर में बैठक होनी थी। लेकिन प्रदेश में उपचुनाव के कारण यह बैठक स्थगित कर दी गई। अब यह बैठक दिवाली के बाद होगी।

गौरतलब है कि है कि 25 अगस्त 2005 को मप्र, उप्र और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ था। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि प्रारंभ में 533 एमसीएम पानी उप्र को देने की बात थी, जो बाद में 700 एमसीएम तक पहुंच गई। मप्र इसके लिए भी तैयार हो गया, जबकि परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा डूब में आ रहा है। गांवों का विस्थापन भी होगा। इसके बाद भी उप्र की ओर से रबी सीजन के लिए 900 एमसीएम पानी दिए जाने की मांग रख दी गई, जिससे प्रदेश बिल्कुल भी सहमत नहीं है। केंद्र सरकार के सामने भी यह मामला उठ चुका है। कई दौर की बैठकों के बाद 23 अप्रैल 2018 को मप्र, उप्र और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच जब बैठक हुई तो उसमें इस बात पर सहमति बनी कि 700 एमसीएम पानी मिलेगा। बाद में केंद्र सरकार ने उप्र को 788 एमसीएम पानी देना तय कर दिया था। लेकिन जुलाई 2019 में उप्र की सरकार ने 930 एमसीएम पानी मांग लिया जिसे मप्र ने इनकार कर दिया था।

परियोजना लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 5-5 प्रतिशत दोनों राज्य लगाएंगे। एमओयू का मसौदा भी तैयार हो गया था, लेकिन फिर मप्र में विधानसभा चुनाव आ गए और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कांग्रेस सरकार आने पर परियोजना को लेकर अपेक्षित गति नहीं आई। एक-दो औपचारिक तौर पर बैठकें हुईं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। मप्र में पानी बंटवारे को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके तहत उप्र को रबी सीजन में 700 एमसीएम और खरीफ सीजन में 1000 एमसीएम पानी देने का प्रस्ताव है। पानी बंटवारे के विवाद को लेकर ही केन-बेतवा लिंक परियोजना बीते 15 साल से अधर में अटकी हुई है। साल 2005 में दोनों राज्यों के बीच पानी का बंटवारा हो गया था। लेकिन बाद में उप्र ने पानी की मांग बढ़ाकर विवाद बढ़ा दिया था। इसी वजह से मप्र और उप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी की समस्या भी हल नहीं हो पा रही है। इस परियोजना के तहत केन नदी पर डोंढन में बांध बनाया जाएगा। 77 मीटर ऊंचे और 19 हजार 633 किलोमीटर वर्ग की जलग्रहण क्षमता वाले इस मुख्य बांध में 2 हजार 853 एमसीएम पानी भंडारण की क्षमता होगी। इससे छतरपुर और पन्ना जिले की 3 लाख 23 हजार जमीन सिंचित होगी। बांध के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व की 5 हजार 258 हैक्टेयर जमीन सहित कुल 9 हजार हैक्टेयर जमीन डूब जाएगी। इसमें बसे सुकुवाहा, भावर खुवा, घुगरी, वसोदा, कुपी, शाहपुरा, डोंढन, पिलकोहा, खरयानी और मेनारी गांव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। योजना के तहत तीन अन्य बांध बेतवा नदी पर बनेंगे। रायसेन व विदिशा जिले में मकोडिया बांध से 56 हजार 850 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। वहीं, बरारी बैराज से ढाई हजार और केसरी बैराज से दो हजार 880 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। परियोजना से मप्र के छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ जिले की 3 लाख 96 हजार और उप्र के महोबा, बांदा और झांसी जिले में दो लाख 65 हजार हैक्टेयर (कुल छह लाख 60 हजार हैक्टेयर) क्षेत्र में सिंचाई होगी।

● **जितेन्द्र तिवारी**

दोनों सूबों में जल की समस्या

बताया जाता है कि साल 2005 में मप्र और उप्र के बीच जल बंटवारा हो गया था लेकिन बाद में उप्र सरकार की मांग बढ़ गई जिसके चलते विवाद हो गया। इस विवाद के चलते ही मप्र और उप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र में पीने के पानी और सिंचाई के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विवाद को सुलझाने के लिए सितंबर में दोनों राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने उस बैठक जल बंटवारे पर विवाद की वजह से परियोजना में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने विवाद के समाधान के लिए दोनों ही राज्यों से अक्टूबर तक प्लान मांगा था। बीते 29 अक्टूबर को बैठक प्रस्तावित थी जो उपचुनावों के चलते स्थगित कर दी गई। अब यह बैठक दीपावली बाद होने जा रही है। इस बैठक में दोनों राज्य अपनी कार्ययोजना रखेंगे। सूत्रों का कहना है कि मप्र जल संसाधन विभाग ने पानी की जरूरत की योजना में साफ उल्लेख किया है कि रबी के सीजन में उप्र को 700 एमसीएम और खरीफ में 1000 एमसीएम पानी ही दिया जा सकेगा। इससे ज्यादा पानी देने पर मप्र में 4.47 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की मुश्किलें आएंगी। विभाग का कहना है कि परियोजना में जंगल, जमीन और वन्यप्राणियों के लिए रहवास क्षेत्र का नुकसान मप्र उठाएगा ऐसे में पानी पर ज्यादा हक उसका है।

राजनीति रसूख का ऐसा वायरस होता है, जो अच्छे-अच्छों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। राजनीति के इसी वायरस ने अध्यात्म की अलख जगाने वाले कंप्यूटर बाबा को जकड़ लिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि आज उनके साम्राज्य पर प्रशासन का हथौड़ा बरस रहा है। यही नहीं इस वायरस ने बाबा को जेल की सैर भी करवा दी है। साथ ही बाबा का रहा-सहा रसूख भी ध्वस्त हो गया।

राजनीति का वायरस

कुछ साल पहले तक अध्यात्मिक गुरु कम्प्यूटर बाबा का रसूख ऐसा था कि शासन-प्रशासन उनके सामने नतमस्तक रहता था। लेकिन जबसे बाबा को राजनीति का चस्का लगा उनके दुश्मनों की फौज खड़ी हो गई। यही नहीं राजनीति के वायरस ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया कि वे सत्तापक्ष के खिलाफ अभियान चलाने लगे। जिसका परिणाम यह हुआ है कि बाबा का पूरा साम्राज्य तहस-नहस हो गया है। जो प्रशासन बाबा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था, उसने उनके आश्रम पर बुलडोजर चलवा दिया। यही नहीं अपनी करतूतों के कारण बाबा को जेल की हवा भी खानी पड़ी है।

कम्प्यूटर बाबा का असली नाम नामदेव दास त्यागी है। वर्ष 1998 में नरसिंहपुर के एक संत ने कम्प्यूटर बाबा नाम दिया था, क्योंकि बाबा का दिमाग तेज चलता था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बाबा के कम्प्यूटर में राजनीति का वायरस आ गया था। भाजपा के शासनकाल में कम्प्यूटर बाबा ने अपना अवैध साम्राज्य गोम्मटगिरी टेकरी के समीप बढ़ाया। तब उन पर शिकंजा नहीं कसा गया, लेकिन कम्प्यूटर बाबा ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देना शुरू कर दिया था। सरकार के खिलाफ उन्होंने नर्मदा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया था, तब भाजपा सरकार ने उन्हें नदी न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन चुनाव के पहले कम्प्यूटर बाबा ने इस्तीफा देकर यात्रा निकाल ली और तब इंदौर में एक बड़ा आयोजन भी किया था। बाबा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस का साथ देने के कारण वैसे ही कम्प्यूटर बाबा पर सरकार की नजरे टेढ़ी थी। इस साल बाबा की जन्म कुंडली स्थानीय अफसरों ने तैयार कर ली थी। कम्प्यूटर बाबा ने 15 साल पहले जब टेकरी पर अतिक्रमण करना शुरू किया था, तब तत्कालीन कलेक्टर विवेक अग्रवाल से उनका विवाद हो गया था। कम्प्यूटर बाबा ने तब राजवाड़ा पर धरना दिया था। उनके समर्थन में सैकड़ों साधु चौक पर ही धुनी रमाकर बैठ गए थे। तब अग्रवाल ने मंच पर आकर कम्प्यूटर बाबा से माफी मांगी थी और बाबा ने धरना समाप्त किया था।

भाजपा और कांग्रेस दोनों शासनकाल में राज्यमंत्री का दर्जा पा चुके नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा के ग्राम जम्बूडी हप्सी के खसरा नंबर 610/1 और 610/2 की 46 एकड़ से ज्यादा जमीन में से दो एकड़ पर फैले लग्जरी आश्रम पर जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे को तोड़ने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह करीब 7 बजे से शुरू हुई कार्रवाई दोपहर 12 बजे खत्म हुई और पूरे आश्रम को चार पोकलेन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के बाद 10 ट्रकों में सामान भरा गया और बाबा के साथी गंगादास के सुपुर्द कर दिया गया। इसमें रजाई, गद्दे, टीवी, फ्रीज, एसी, अलमारी, कुर्सियां, पेंटिग्स, फोटो, टेबल, बुलेट, कार, बाथरूम का सामान, क्रीम, सूटकेस, किचन का सामान, पलंग, कमंडल, माला आदि कई सामग्रियां शामिल हैं। आश्रम में सीसीटीवी भी लगे हुए थे। इस दौरान अशांति फैलाने के आरोप में बाबा और उनके सहयोगी रामचरण दास, संदीप द्विवेदी, रामबाबू यादव, मोनू पंडित, जगदीप सहित कुल सात लोगों को एसडीएम राजेश राठौर द्वारा अगले आदेश तक जेल भेज दिया गया। बाबा को सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 5 में रखा है, जहां वे आराम से ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने जेल में कोई विरोध नहीं किया है और प्रशासन की कार्रवाई से खौफ में नजर आ रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार आश्रम पर हो रही कार्रवाई की सूचना प्रशासन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहले ही दे दी थी। वहां से हरी झंडी

कई शहरों में कब्जे के प्रमाण

कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ रेत माफिया से वसूली के सुराग मिले हैं। प्रदेश के अन्य कई शहरों में कब्जे के भी प्रमाण मिले हैं। बाबा के नाम पर सांवेर के अजनोद में तीन हैक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री और एक पासबुक भी मिली है। जांच से सामने आया है कि दोनों ही जगह बाबा ने कालेधन का उपयोग किया, ताकि पासबुक में पैन नहीं देना पड़े। हर बार 50 हजार से कम राशि यानी 49-49 हजार रुपए जमा किए गए। अजनोद की गाइडलाइन से कीमत 27.69 लाख रुपए थी, लेकिन बाबा ने जून-2009 में 10 लाख में खरीदी। इसके लिए फॉर्म-16 लगाकर आयकर दायरे में नहीं आने का प्रमाण भी लगा दिया। किसी शंकर नाम के व्यक्ति से खरीदी इस जमीन की गाइडलाइन कीमत आज 75 लाख से ज्यादा है, बाजार मूल्य 2.50 करोड़ है। यह खाता करीब एक साल पहले 1.79 लाख रुपए से खुला था। बाबा इसका एटीएम उपयोग करते थे और इससे पांच-दस हजार रुपए की राशि कैश निकालते रहते थे। साथ ही गिफ्ट शॉप व अन्य दुकानों से छोटी खरीदी में भी इस खाते की राशि का उपयोग होती था। बीच-बीच में किसी ने इस खाते में 49-49 हजार करके निर्धारित समय पर राशि जमा कराई। फिलहाल खाते में करीब 25 हजार रुपए जमा हैं।

मिली कि अवैध कब्जा है तो सख्ती से कार्रवाई की जाए। बाबा ने हाल ही में मप्र की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा भी निकाली थी। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद कार्रवाई की रूपरेखा बनी।

कलेक्टर मनीष सिंह ने धर्मस्थल और कानून व्यवस्था को देखते हुए इसमें अलग-अलग अधिकारियों की टीम गठित की। कार्रवाई के एक रात पहले तक कलेक्टर, डीआईजी, निगमायुक्त और एडीएम अजय देव शर्मा को ही इसकी जानकारी थी। पूरी टीम को सुबह थाने पर एकत्र होने के लिए कहा गया। सुबह 6 बजे सभी को बताया गया कि बाबा के आश्रम पर कार्रवाई है। इसके बाद एसडीएम राठौर और नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव की टीम को बाबा के पास भेजा गया। उनके द्वारा विरोध करने पर गिरफ्तार किया गया। आश्रम से 10 ट्रक सामान निकला है। सामान हटाने में निगमकर्मियों को दो घंटे लग गए। इसमें महंगे सोफे, टीवी, एसी, फ्रिज, अलमारी, क्रिस्टा कार जो मूसाखेड़ी के किसी रमेश सिंह तोमर के नाम पर है, एक बंदूक, बुलेट, महंगी क्रीम, साबुन आदि शामिल है। चार माह पहले नगर निगम से बाबा को आश्रम के अवैध निर्माण हटाने का नोटिस गया था, लेकिन तब सामने आया कि यह जगह निगम की सीमा में नहीं आती है। इसके बाद प्रशासन के पाले में गेंद गई। लेकिन जम्बूडी हप्सी गांव में पंचायत होने के चलते मामला पहले पंचायत के पास कार्रवाई के लिए गया और वहां से प्रस्ताव पास कर एसडीएम हातोद को पत्र गया कि बाबा पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद तहसीलदार हातोद ममता पटेल की कोर्ट में केस चला और इस दौरान बाबा ने निर्माण के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए, जिसके चलते उनके आश्रम पर कब्जा हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया और दो हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।

1965 में जन्मे नामदेव दास त्यागी को नरसिंहपुर में साल 1998 में एक बाबा ने उनके गैजेट प्रेम और हमेशा लैपटॉप साथ में रखने के चलते कम्प्यूटर बाबा नाम दिया था। साल 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी से उन्हें उम्मीदवार बनाने की मांग की थी, लेकिन बात नहीं बनी। साल 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उन्होंने नर्मदा यात्रा में हुए पौधरोपण को लेकर आरोप लगाए और यात्रा की घोषणा की। अप्रैल 2018 में राज्यमंत्री बना दिए गए। बाद में भाजपा से मोहभंग हुआ और कांग्रेस की तरफ झुक गए। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की जीत के लिए यज्ञ भी किया। बाबा ने गोम्मट गिरी आश्रम की जमीन पर हुए विवाद के बाद सबसे पहले राजबाड़ा पर आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन मंत्री और वर्तमान भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अनशन खत्म करवाया था। अंबिकापुरी स्थित श्रीसिद्ध कालीधाम मंदिर को लेकर हुई हत्या के मामले में भी बाबा को लेकर आरोप लगे थे। 2011 में कम्प्यूटर बाबा ने गोम्मट गिरी आश्रम पर लघु कुंभ आयोजित किया था। इसके प्रचार के लिए उन्होंने हेलिकॉप्टर से गांव-गांव में पर्चे वितरित किए थे।

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंदौर में बदले की भावना से कम्प्यूटर बाबा का आश्रम व मंदिर बिना नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है। यह राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि पहले बाबा भाजपा के साथ थे, तब अतिक्रमण नहीं दिखा। पहले वह संत लग रहे थे और अब शैतान लग रहे हैं। देपालपुर से कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने कहा कि जिसे प्रशासन तोड़ रहा है, वो मंदिर कलोता समाज ने बनवाया था। इस पर कार्रवाई का कलोता समाज विरोध करता है। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कम्प्यूटर बाबा को लेकर बयान दिया है कि उन्हें धर्म की पताका फहराना चाहिए थी, लेकिन वो राजनीति का वायरस फैला रहे थे। उन्हें धर्म को आगे ले जाना चाहिए, लेकिन वो उस तरह के काम न करते हुए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वह किसी संत को शोभा नहीं देता। उनमें राजनीति का वायरस घुस गया था।

● सुनील सिंह

भाजपा शासन में ही इंस्टाल हुआ था कम्प्यूटर

जिस कम्प्यूटर बाबा को भाजपा के नेता कोस रहे हैं, उन्होंने भाजपा के शासनकाल में ही अपना नाम और काम बढ़ाया। यानी एक तरह से नामदेव त्यागी का कम्प्यूटर भाजपा के ही राज में इंस्टाल हुआ और भाजपा सरकार ने जाते-जाते उन्हें राज्यमंत्री पद से नवाजा भी, लेकिन कांग्रेस और दिग्विजय सिंह से नजदीकी के चलते बाबा ने जाती सरकार को अलविदा कह दिया और कांग्रेस के पाले में आ गए, जहां उनका रुतबा बरकरार रहा। नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने गोम्मटगिरि पर मंदिर बनाया और उसके बाद वहां कब्जा करना शुरू किया। उस समय जैन समाज ने पहाड़ी पर अतिक्रमण को लेकर खूब लड़ाई लड़ी। तत्कालीन कलेक्टर विवेक अग्रवाल ने कार्रवाई की तो कम्प्यूटर बाबा राजबाड़ा पर अन्य बाबाओं के साथ प्रदर्शन करने बैठ गए थे। बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया और कम्प्यूटर बाबा का कब्जा वहां बरकरार रहा। भाजपा की सरकार के दौरान कम्प्यूटर बाबा का कामकाज खूब फला-फूला। बड़े-बड़े धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ राजनीतिक आयोजनों में कम्प्यूटर बाबा को खूब तवज्जो मिली और उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। बाबा के आश्रम में कुछ भाजपा नेता भी जाते थे और उसे अपने कार्यक्रम में बुलाते थे। बाबा ने शिवराज सरकार के दौरान नर्मदा किनारे हुए पौधरोपण घोटाले को लेकर आवाज उठाई थी और इसको लेकर नर्मदा परिक्रमा शुरू करने की धमकी दी और कहा कि वे इस घोटाले को सामने लेकर आएंगे। 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले बाबा को शिवराज सरकार ने राज्यमंत्री का दर्जा देकर उपकृत किया। उनके साथ इंदौर के ही योगेन्द्र महंत को भी यह दर्जा दिया गया था। हालांकि सरकार जाती देख वे कांग्रेस के पाले में कूद गए और बाद में कांग्रेस ने भी खूब तवज्जो दी। भाजपा के राज में ही बाबा ने सारी बारीकियां सीखीं और उसका उपयोग अब वे भाजपा के खिलाफ ही कर रहे थे। कुछ महीनों पहले भी उनके आश्रम पर कार्रवाई होना थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया तो कार्रवाई रुक गई थी।

कोरोना संक्रमणकाल में बिजली कंपनियों की आर्थिक सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है। कंपनियों के पास राजस्व नहीं आ रहा है। यही स्थिति रही तो बिजली सप्लाई निरंतर देना आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है। कंपनियां बिजली के दाम भी बढ़ाना चाह रही है।

महंगी होगी बिजली

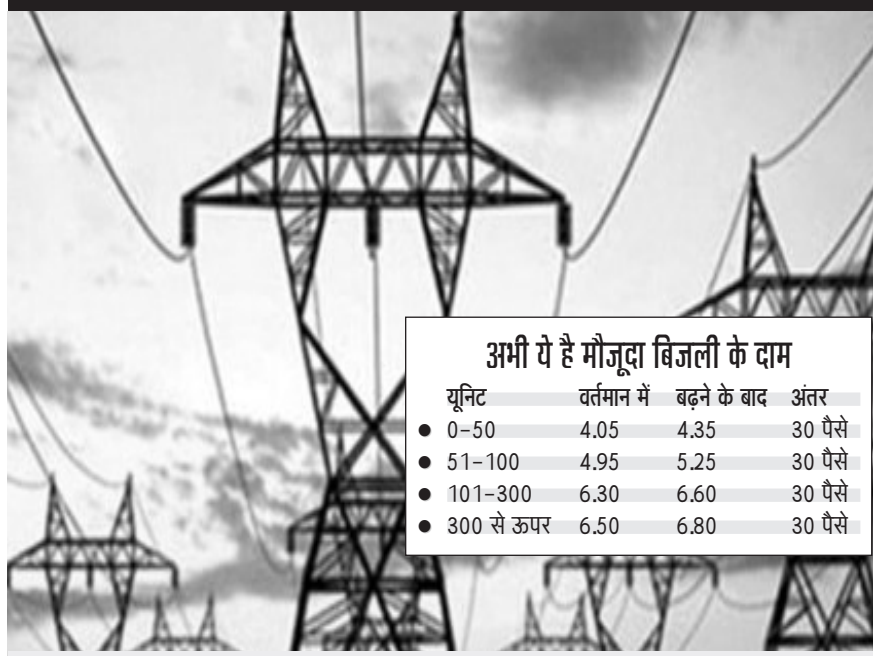

अभी ये है मौजूदा बिजली के दाम

यूनिट	वर्तमान में	बढ़ने के बाद	अंतर
● 0-50	4.05	4.35	30 पैसे
● 51-100	4.95	5.25	30 पैसे
● 101-300	6.30	6.60	30 पैसे
● 300 से ऊपर	6.50	6.80	30 पैसे

आय-व्यय के आंकलन पर तय होगी दर

मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के राजस्व महाप्रबंधक फिरोज मेश्राम ने बताया कि बिजली की कीमत तय करने का निर्णय मप्र विद्युत नियामक आयोग करती है। कंपनी अपनी वार्षिक जरूरत के अनुसार आय-व्यय का आंकलन कर दर बढ़ाने की अनुमति मांगती है। नया टैरिफ याचिका बनाने में पिछले साल के गैप को कम करने के लिए दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में 6500 करोड़ यूनिट के लगभग डिमांड बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में बिजली की उपलब्धता और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजली की कीमतों में बढ़ोत्तरी करना होगा। चालू वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनियों ने 39,332 करोड़ रुपए के आय और 41,332 करोड़ रुपए व्यय का आंकलन किया था। इसी दो हजार करोड़ रुपए की भरपाई के लिए कीमतों में 5.25 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति मांगी थी, जो नहीं मिल पाई।

मप्र में जल्द ही उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लग सकता है। मप्र में उपचुनाव खत्म होने के बाद अब बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि बिजली कंपनियां पहले ही बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी करना चाहती थीं लेकिन पहले कोरोना वायरस और फिर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के चलते उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं हो पाया। खबर है कि विद्युत कंपनियां बिजली की दरों में 7 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार करने में जुट गई हैं।

मप्र सरकार बदलने के बाद से अटका हुआ बिजली का नया टैरिफ लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। 7 प्रतिशत तक दरें बढ़ाई जा सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उपचुनाव हो जाना। दरअसल, कोरोनाकाल के अलावा उपचुनाव होने के कारण सरकार भी नया टैरिफ लागू करने के पक्ष में नहीं बताई जा रही थी। 7 महीने तक मामला टलता रहा, सुनवाई भी नहीं हुई। अब उपचुनाव के बाद जल्द फैसला हो सकता है जो बिजली उपभोक्ताओं के लिए भार बढ़ाने वाला होगा। वजह यह है कि सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है और इस साल 8 महीने में मप्र की तीनों बिजली कंपनियों को दो हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।

जानकार बताते हैं कि पॉवर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से तैयार कराई जा रही टैरिफ याचिका में इस बार औसतन 7 प्रतिशत तक बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों से लेखा-जोखा मांगा गया है। उन्हें 30 नवंबर तक विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर करना है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिजली कंपनियों ने औसत 5.25 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़ाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस पर निर्णय नहीं हो पाया। लगभग तीन हजार करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई के लिए इस बार बिजली बिलों के दामों में बढ़ोत्तरी होना तय माना जा रहा है। पॉवर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें बीते सालों में हुए नुकसान को जोड़कर बिजली की कीमत तय करने की तैयारी है। तीन हजार रुपए से अधिक घाटे की भरपाई के लिए अलग-अलग श्रेणी में 4 से 12 प्रतिशत तक कीमत बढ़ाने की तैयारी है। औसतन ये 7 प्रतिशत के आसपास रहेगी।

मप्र विद्युत नियामक आयोग में 30 नवंबर तक याचिका पेश करने के लिए मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने तीनों वितरण कंपनियों से आय-व्यय का लेखा-जोखा मांगा है। बिजली कंपनियों ने वर्ष 2019-20 में 5575 करोड़ यूनिट बिजली बेची थी। वहीं 2020-21 में 6 हजार करोड़ यूनिट बिजली बेचने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त तक कंपनी 2050 करोड़ यूनिट बिजली बेच पाई है। उसे उम्मीद है कि रबी सीजन में डिमांड बढ़ने पर 6 हजार करोड़ यूनिट का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।

विद्युत कंपनियां घाटे का हवाला देते हुए बिजली की दरों में इजाफा करने की तैयारी में हैं और वो अपना प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को जल्द भेज सकती हैं। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो फिर उपभोक्ताओं को बिजली का करंट लग सकता है। विद्युत कंपनियों का कहना है कि कोरोनाकाल में विद्युत कंपनियों को भी काफी घाटा लगा है और उनके पास राजस्व नहीं आ पा रहा है। अगर दाम नहीं बढ़ाए गए तो संकट बढ़ सकता है और निरंतर बिजली सप्लाई देना भी मुश्किल हो सकता है। बता दें कि साल 2020-21 में बिजली कंपनियों ने औसत 5.25 फीसदी दाम बढ़ाने की अनुमति विद्युत नियामक आयोग से मांगी थी लेकिन पहले कोरोना और फिर उपचुनाव के चलते इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। अब जब उपचुनाव हो चुके हैं तो कंपनियां फिर से प्रस्ताव तैयार करने में जुट गई हैं जिन्हें विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा।

● **प्रवीण कुमार**

कहां गई संवेदना

विश्व में अब तक कई महामारियां आई हैं, लेकिन कोविड-19 पहली ऐसी महामारी है, जिसके डर से लोगों की सद्भावना और संवेदना भी मर गई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोग अपने स्वजनों की अस्थियों का विसर्जन करने से भी कतरा रहे हैं।

तीन साल पहले सीरिया के समुद्र तट पर निर्जीव पड़े तीन साल के ऐलान कुर्दी के शव की तस्वीर ने सारी दुनिया की सामूहिक संवेदना को झकझोरकर रख दिया था। ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों ने उस तस्वीर के प्रकाशित होने के बाद अपने देशों की सीमा शरणार्थियों के लिए खोलने का फैसला किया। वैसी कितनी ही तस्वीरें कोरोना संकट की महामारी के इस दौर में भारत में बन रही हैं पर क्या किसी की संवेदना के तार झंकृत हो रहे हैं? असल में वह महामारी का दौर नहीं था तो दुनिया विचलित हुई पर अब कोई विचलित नहीं हो रहा है क्योंकि सब अपनी चिंता में हैं।

इसका असर यह देखने को मिला कि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति को घर परिवार और समाज में अछूत माना जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि संक्रमित की मौत के बाद भी उसकी अस्थियों के साथ भी संवेदना नहीं दिखाई जा रही है। देशभर के विश्रामघाटों पर कोरोना से मरे लोगों की अस्थियां विसर्जन का इंतजार कर रही हैं। मप्र की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में पिछले 7 महीने से अंतिम संस्कार के बाद पवित्र नदियों में विसर्जन का इंतजार कर रहीं अस्थियों को नर्मदा नदी में विधानपूर्वक विसर्जित किया गया। गत दिनों रामबाग मुक्तिधाम से एक क्विंटल से ज्यादा अस्थियों को लेकर समिति सदस्य नर्मदा किनारे पहुंचे। यहां पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ मृतकों की आत्माओं की शांति की प्रार्थना के साथ अस्थियों को विसर्जित करवाया। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अस्थियों का विसर्जन बिना अंतिम संस्कार अधूरा होता है।

कोरोना के कारण 24 मार्च से इंदौर पूरी तरह से लॉक हो गया था। इसके बाद से लंबे समय तक लोग घरों में बंद रहे। कोरोना के कारण लगातार मौतें होती रहीं। इस दौरान कुछ लावारिस लाशें भी आईं और कुछ सामान्य मौतें भी हुईं। इस दौरान संक्रमण नहीं फैले, इस कारण कोरोना संक्रमित शव का निगम-प्रशासन द्वारा ही अंतिम संस्कार करवाया गया। ऐसे में यहां अस्थियां लेने भी कई लोग नहीं पहुंच पाए। ये अस्थियां लंबे समय से मुक्तिधाम के लॉकर में रखी थीं।

रामबाग मुक्तिधाम पर ही मार्च से लेकर अक्टूबर महीने तक 1 क्विंटल से ज्यादा अस्थियां एकत्रित हो गईं, जिन्हें पवित्र नदियों में प्रवाहित करने का काम रामबाग मुक्तिधाम एवं दशा पिंड विकास समित ने किया। सभी अस्थियों को लॉकर से निकालकर बोरी में भरा गया। नर्मदा नदी में विसर्जन के पहले मुक्तिधाम में ही सभी अस्थियों का विधिपूर्वक पूजन किया गया। सभी प्रक्रिया को समिति सदस्यों ने ही संपन्न करवाया।

रामबाग मुक्तिधाम विकास समिति अध्यक्ष सुधीर दांडेकर ने बताया कि मुक्तिधाम में कोरोनाकाल में लगे लॉकडाउन के बाद से ही अंतिम संस्कार के बाद यहां रखी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पाया था। इसमें वे लोग भी थे, जिन्हें या तो कोरोना से डर था या परिवार ही क्वारैंटाइन था। कुछ लोग तो प्रतीकात्मक रूप से दो-चार अस्थियां लेकर चले गए। उन्होंने अस्थियों के विसर्जन के लिए निवेदन किया था। इतने समय में एक क्विंटल से ज्यादा अस्थियां एकत्रित हो गई थीं, जिन्हें विधि-विधान से पूजन के बाद नर्मदा नदी में प्रवाहित किया गया।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की भयावहता बढ़ी तो मरीजों के साथ-साथ अफसरों की संवेदनाएं भी मरने लगी हैं। कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद आम आदमी हो या नामी सबके शव के साथ ऐसे व्यवहार किए गए, जिसे देखकर लोग कांप उठते थे। कहीं श्मशान घाट में शव को घसीटा जाता था तो कहीं अधजली हालत में शव पड़ा दिखता। इसकी वजह यह है कि महामारी सबसे पहले इंसान की संवेदना पर चोट करती है। अपने जीवन और वर्तमान के संकटों की चिंता में इंसान प्यार, दोस्ती, इंसानियत जैसी बातें भूल जाता है। अल्बैर कामू ने अपनी महान रचना 'प्लेग' में लिखा है- हकीकत यह है कि महामारी से कम सनसनीखेज और नीरस घटना कोई नहीं हो सकती। बड़ी मुसीबतें ज्यादा देर तक रहती हैं तो नीरस बन जाती हैं। कोरोना महामारी में भी ऐसा ही हो रहा है। महामारी जितनी फैल रही है और इससे मरने वालों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ रही है, सनसनी उतनी कम होती जा रही है। लोग आंकड़ों के प्रति उदासीन होने लगे हैं। मरने वालों का आंकड़ा जितना बड़ा हो रहा है वह उतना ही छोटा नजर आने लगा है। अखबार ऐसी खबरों से भरे हैं कि भारत में दिल का दौरा पड़ने से हर महीने कितने लोग मरते हैं या सांस की गंभीर बीमारी से कितने लोग मरते हैं, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कितने लोग मर जाते हैं और उसके मुकाबले कोरोना महामारी से मरे लोगों की संख्या कितनी मामूली है।

● **लोकेन्द्र शर्मा**

प्रियजनों का शव लेने से इंकार कर चुके हैं लोग

जब महामारी शुरू हुई तो संख्या को लेकर ऐसी उदासीनता नहीं थी और न कोरोना की खबर सनसनी से परे थी। पर अब इसकी सनसनी खत्म हो गई है, बढ़ती हुई संख्या छोटी लगने लगी है और लाखों लोगों का पलायन समस्या का समाधान दिखने लगा है। याद करें, जब कोरोना वायरस की महामारी शुरू हुई थी तब किसी कोरोना संक्रमित की मौत और उसके अंतिम संस्कार को लेकर कैसी दारूण कथाएं सुनने को मिली थीं। लोग इस बात से दुखी हो रहे थे कि उन्हें अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार भी ठीक से करने को नहीं मिल रहा है। पर क्या अब कहीं से ऐसी खबर आ रही है? अब तो खुद लोग अपने प्रियजनों का शव लेने से इंकार कर रहे हैं या अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर रहे हैं और वीडियो रिकार्डिंग से अंतिम संस्कार देख कर संतोष कर रहे हैं।

बिचौलियों की जद में प्याज

इन दिनों आलू-प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अब तक शायद ही कभी आलू की कीमतें पचास रुपए के पार पहुंची हों। लेकिन इस बार प्याज के साथ आलू भी प्रतियोगिता करते नजर आ रहा है। टमाटर तो बारिश के दिनों में अक्सर लाल होता रहा है। इसलिए उसकी महंगाई से हैरत नहीं हुई है। आलू-प्याज की इस बार की महंगाई अचंभे में डाल रही है।

मप्र सहित देशभर में बिचौलियों और व्यापारियों ने प्याज के गोरखधंधे में कितनी मुनाफाखोरी की है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मार्च-अप्रैल में किसानों ने जिस प्याज को 7 रुपए किलो की दर से बेचा था, वह पिछले 5 माह के दौरान 60 से 90 रुपए प्रति किलो के दर से बिकी। भारत में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है और वहीं की लासलगांव की मंडी से प्याज के दाम तय होते हैं। नासिक जिले के कैलाश जाधव ने लॉकडाउन के दौरान अप्रैल-मई में अपना प्याज 700 रुपए क्विंटल बेच दिया था, लेकिन अब उसी मंडी में प्याज 6000-9000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है। बढ़ी महंगाई का फायदा कैलाश जाधव को नहीं मिल पाया। मौजूदा दौर का ज्यादातर प्याज कारोबारियों और बड़े किसानों का है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इस महंगाई से किसान को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। फायदा मिल रहा है लेकिन महंगाई के मुकाबले काफी कम है।

ध्यान रहे कि मप्र में लगभग 6 से 8 लाख किसान पूरी तरह प्याज की खेती पर निर्भर हैं। प्याज की ज्यादातर खेती मालवा और निमाड़ क्षेत्र में होती है। देश में मप्र दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। प्रदेश में सालाना 102.9 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। प्रदेश में प्याज की पैदावार तीनों मौसम में यानी खरीफ, लेट खरीफ और रबी में होती है। प्रदेश में मुख्य प्याज उत्पादक जिलों में इंदौर, सागर, शाजापुर, खंडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शिवपुरी, मालवा, राजगढ़, धार, सतना, खरगौन और छिंदवाड़ा है। कृषि मामलों के विशेषज्ञ और मप्र की पूर्व कमलनाथ सरकार में कृषि सलाहकार रहे केदार सिरोही कहते हैं कि प्याज के भाव स्थिर नहीं रह पाते। कभी ये डेढ़-दो रुपए प्रति किलोग्राम तो कभी इनका भाव 22 रुपए और कभी 100 रूपए प्रति किलो तक भी पहुंच जाता है। इसकी वजह है इसका सरकारी आंकड़े का सही नहीं होना। सरकारी आंकड़ा पिछले आंकड़े के अनुमान के आधार पर होता है, जिससे स्टॉक पोजीशन सही नहीं होती है। आंकड़ों में जब प्याज की कमी बताई जाती है, तब बंपर आवक हो जाती है, जबकि व्यापारी जमीनी स्तर पर कार्य करता है, वह इसका लाभ उठा ले जाता है।

मप्र सहित देश में साल में दो बार प्याज की खेती होती है। जो प्याज इस वक्त देश में खाया जा रहा है वो मार्च-अप्रैल का खुदा हुआ है। जिसका किसान भंडारण करते हैं, और जरूरत के मुताबिक बेचते हैं। आमतौर पर भी भंडारण के पारंपरिक तरीकों के कारण लगभग एक तिहाई प्याज खराब ही होता है। ज्यादा उत्पादन के बावजूद विदेश से प्याज आयात करने का सबसे बड़ा कारण यही है। हम अपने प्याज को सुरक्षित नहीं रख पाते और किसान मजबूरी में उसे औने-पौने दाम में बेचते हैं। फिर भी बाद में प्याज खराब होता है और जरूरत पूरी करने के लिए हम विदेश से महंगा प्याज मंगाते हैं। उद्यानिकी विभाग के आंकड़ों की मानें तो मप्र में 8 हजार गोदाम भी नहीं है। हालांकि, गोदाम बनाने के लिए योजनाएं तो बनी, लेकिन प्रोत्साहन के आभाव में पूरी तरह से धरातल पर नहीं आ सकी। मप्र के बड़े प्याज के उत्पादक जिले आगर, शाजापुर, रतलाम, शिवपुरी, उज्जैन, देवास, इंदौर, रीवा में भी लोगों को महंगा प्याज ही खाना पड़ रहा है। कृषि मामलों के विशेषज्ञ केदार सिरोही कहते हैं कि लगभग 40 सालों से प्याज के किसान एक तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद बीज अनुसंधान, फसल के तरीके और प्याज के किसानों को तकनीकी मदद के लिए खास प्रयास नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि किसान पर मौसम डोमिनेट करता है और बारिश होते ही प्याज के खेत, नर्सरी और रखी फसल खराब हो जाती है। सिरोही कहते हैं कि महंगे बीज के इस्तेमाल और खराब मौसम से जूझकर किसी तरह किसान प्याज तैयार कर देता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि वह अपने प्याज को अपने पास रखे और सही दाम मिलने पर बेचे। दूसरा कि वह ज्यादा उत्पादन के समय अपनी फसल कम दाम में बेच दे।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

40 लाख टन पैदावार, फिर भी किसान बेहाल

मप्र में प्याज की पैदावार 40 लाख टन के पार है, जो खपत की तुलना में तीन गुना तक अधिक है। फिर भी इसकी बढ़ी कीमतें आंखों में आंसू ला रही है। पिछले साल रिकार्ड 150 रुपए किलो तक प्याज महंगा था, जबकि अब 60 से 90 रुपए किलो तक भाव है। इसकी मुख्य वजह प्रदेश में प्याज भंडारण के लिए पर्याप्त गोदाम न होने हैं। इस कारण मार्च-अप्रैल में किसान कौड़ियों के भाव पर प्याज बेच देते हैं, जो व्यापारी खरीदकर दूसरे राज्यों में पहुंचाते हैं। इससे सितंबर-अक्टूबर तक प्रदेश का प्याज खत्म हो जाता है और महाराष्ट्र व कर्नाटक पर निर्भर हो जाते हैं। व्यापारी वहां से प्याज लाकर ऊंचे दाम पर बेचते हैं। अबकी बार अधिक बारिश होने के कारण महाराष्ट्र व कर्नाटक की फसलें भी बर्बाद हुई हैं। इस कारण वहां से प्याज नहीं आ रही है। ऐसे में बिचौलिए मांग और आपूर्ति का माहौल बना रहे हैं। जो किसान सहेजकर रखे प्याज को मंडियों में बेचने आते हैं, उनसे बाहर या गांव में पहुंचकर ही खरीद लिया जाता है। फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कनार्टक में भेज देते हैं। बचा प्याज स्थानीय फुटकर व्यापारी को ज्यादा कीमत पर दिया जाता है, जो बाजार में आकर दोगुना महंगा हो जाता है।

फाइल में दबी नर्मदा समृद्धि योजना

कॉरिडोर की प्रस्तावित चौड़ाई 60 से घटाकर की 30 मीटर

जबलपुर शहर विकास के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर की प्रस्तावित चौड़ाई 60 मीटर से घटाकर 30 मीटर कर दी गई है। इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हालांकि शासन के इस निर्णय पर सुझाव व आपत्ति के लिए शहरवासियों को तीस दिन का समय दिया गया है। जिससे उपयुक्त सुझाव या आपत्ति होने पर उसके तकनीकी पक्षों पर विचार कर आवश्यक सुधार किया जा सके। नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर की चौड़ाई घटाकर आधी किए जाने के निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनने वाले इस कॉरिडोर की चौड़ाई घटाए जाने पर जहां प्रोजेक्ट उतना कारगर नहीं रहेगा, समीप ही निर्माण होने से नर्मदा में सीधे तौर पर प्रदूषण बढ़ेगा और आसपास के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास कई रसूखदारों की जमीनें हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि इन्हीं रसूखदारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर की चौड़ाई कम कर दी गई है। जिससे की वे आसपास अपने बड़े होटल, रेस्टोरेंट, बारातघर, शोरूम से लेकर अन्य निर्माण कर सकें और उनकी ज्यादा जमीन भी प्रभावित न हो।

मप्र में सत्ता परिवर्तन क्या हुआ नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर योजना ठंडे बस्ते में चली गई। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने 3 जनवरी 2020 को नए एलायमेंट वाला नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद से एक साल बीतने को है पर सड़क बनाने का निर्णय अब तक नहीं लिया जा सका। स्थानीय स्तर से शासन को महीनों पहले प्रस्ताव भेजा गया था जिसका कोई जवाब नहीं मिला। बता दें कि नर्मदा नदी के तटीय हिस्से तिलवारा से भटौली यानी ग्वारीघाट के बीच नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर तैयार करने की महत्वाकांक्षी योजना बनी थी। इसके तहत तिलवारा से ग्वारीघाट तक पिच रोड बनाई जानी प्रस्तावित रही। पहले इस सड़क की चौड़ाई 60 मीटर रखी गई थी लेकिन बाद में उसे आधा कर 30 मीटर कर दिया गया था। इसके लिए नया एलायमेंट जारी किया गया था।

नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय भोपाल की ओर से जारी तिलवारा से भटौली के बीच नए एलायमेंट में प्रस्तावित मार्ग का नोटिफिकेशन जारी किया था। दरअसल सड़क की चौड़ाई कम करने के पीछे ग्वारीघाट के आसपास रहने वालों के निर्माण को बचाने के लिए चौड़ाई कम की गई थी। नए नोटिफिकेशन में सड़क की चौड़ाई 30 मीटर कर दी गई। ऐसा करने पर सड़क की लंबाई लगभग 12 किमी से ज्यादा हो रही है। इस पूरी लंबाई में सात गांव की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इनमें तिलवारा, ललपुर, ग्वारीघाट, जिलहरी घाट, भटौली, परसवारा और गौरेया घाट गांव शामिल होंगे।

नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर की सड़क का नया एलायमेंट नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में ही जारी हो चुका था। प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है। अब शासन को ही निर्णय लेना है। नर्मदा नदी के तटीय हिस्से तिलवारा से शुरू होकर भटौली यानी ग्वारीघाट के बीच प्रस्तावित नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर की सड़क सरकार बदलते ही अटक चुकी है। पहले यह सड़क 60 मीटर बनाने का प्रस्ताव था लेकिन बाद में उसे 30 मीटर चौड़ाई में बनाने का निर्णय लिया गया। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने 3 जनवरी 2020 को नए एलायमेंट वाला नोटिफिकेशन जारी किया था। पूरा एक साल बीत जाएगा और सड़क बनाने का निर्णय नहीं लिया जा सका। शासन स्तर पर प्रस्ताव महीनों पहले जा चुका है। यह सड़क पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी गई है।

शहर की जीवनदायिनी और सुकूनदायिनी नर्मदा नदी के किनारे करीब साढ़े आठ किलोमीटर का खूबसूरत कॉरिडोर तैयार किए जाने की कवायद तेज कर दी गई है। अब तक के सबसे बड़े नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मूर्तरूप देने का काम स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से किया जाएगा। लगभग 400 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 8.5 किमी लंबे 6 लेन वाले कॉरिडोर के साथ 20 मीटर चौड़ा नर्मदा दर्शन पथ भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए जबलपुर नगर निगम प्रदेश का ऐसा पहला नगर निगम भी बनने जा रहा है, जो पहली बार मप्र नगर पालिक अधिनियम-1956 की धारा-291 का इस्तेमाल करने जा रहा है। इस धारा का इस्तेमाल कर निगम द्वारा प्राधिकरण की तरह नगर विकास की इस योजना को मूर्तरूप दिया जाएगा।

2300 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में प्रस्तावित नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर अंतर्गत नर्मदा नदी को गंदा होने से बचाने की योजना भी है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद उक्त क्षेत्र का विकास होगा। ऐसे में नर्मदा के प्रदूषित होने की संभावना भी ज्यादा है। इसके लिए इस प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बनाए जाएंगे। नर्मदा दर्शन पथ पर विद्युत व्यवस्था के लिए सोलर एनर्जी के इस्तेमाल की भी योजना है। नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर से शहर के भीतर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा। गौर-तिलहरी की ओर से शहर के भीतर आकर तिलवारा की ओर जाने वाले वाहन इस कॉरिडोर से सीधे निकल जाएंगे। तिलवारा से तिलहरी-गौर जाने वाले वाहन भी शहर में आने की जगह कॉरिडोर से निकलेंगे। इसके साथ ही यह कॉरिडोर पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करेगा। व्यू प्वाइंट, नर्मदा दर्शन पथ सहित कई ऐसे काम होंगे, जिससे पर्यटक वहां पहुंचेंगे।

नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर में नर्मदा नदी के किनारे से लेकर 300 मीटर तक के हिस्से में सिर्फ ग्रीनरी होगी। इस हिस्से में हरियाली बढ़ाने और अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। इस हिस्से में कोई भी निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। यह कॉरिडोर तिलवारा घाट रोड स्थित ब्रॉडगेज रेल लाइन से नर्मदा किनारे तक से प्रारंभ होकर भटौली तक जाएगा। प्रारंभ से आखिर तक एक ओर ब्रॉडगेज लाइन किनारे से इसकी सीमा प्रारंभ होगी, जो कि अंत इसी तरह रहेगी। दूसरे छोर की सीमा शुरू से आखिर तक नर्मदा किनारे से प्रारंभ होगी।

● **रजनीकांत पारे**

चिड़ियाघर पर राजनीति

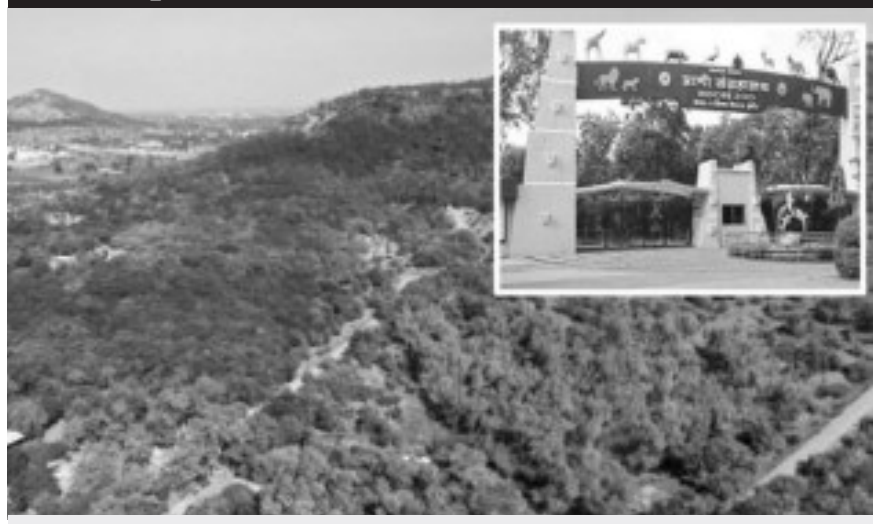

इंदौर जू को वर्तमान जगह से हटाकर रालामंडल अभयारण्य शिफ्ट करने के पीछे बायपास के दोनों ओर मौजूद 5 से ज्यादा गांवों की जमीन का खेल है। रालामंडल अभयारण्य से सटकर रालामंडल, सनावदिया, बिहाडिया, नायता मुंडला, उमरिया मौजूद हैं। चूंकि रालामंडल नोटिफाइड अभयारण्य है, ऐसे में इसके 10 किलोमीटर के हिस्से में निर्माण के लिए वन विभाग की एनओसी की जरूरत होती है। इस राह को आसान कराने के लिए यहां चिड़ियाघर शिफ्ट कराने की तैयारी है, क्योंकि इसके बाद ये अभयारण्य नहीं रह जाएगा। ऐसे में उसके आसपास निर्माण की बाध्यता खत्म हो जाएगी। इंदौर के चिड़ियाघर को शिफ्ट करने की मंत्री विजय शाह की ख्वाहिश को लेकर ये आरोप पूर्व पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लगाए हैं।

पूर्व मंत्री वर्मा के मुताबिक चिड़ियाघर के आसपास के क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जबकि अभयारण्य के आसपास अनुमति देने पर बाद में उलझने के डर से ही शहर से एक साथ दो-दो सौगात छीनने की कोशिश की जा रही है। इंदौर शहर के बीच से जू के हटने से शहरवासियों को परेशानी तो होगी, साथ ही शहर के पास में मौजूद अभयारण्य भी इंदौर से चला जाएगा। 1989 में बने रालामंडल अभयारण्य को वैसे तो केंद्र सरकार ने जब अभयारण्य के तौर पर अनुमति दी थी, उस समय से ही इस पर अभयारण्य नियम लागू हो गए थे। इसके मुताबिक इसके 10 किलोमीटर क्षेत्र में निर्माण या खनन प्रतिबंधित है, लेकिन वन विभाग द्वारा इसमें परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव बनाया है, जिसमें इसकी बाउंड्री के 100 मीटर बाद से अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसे आधार मानकर रालामंडल, नायता मुंडला, बिहाड़िया आदि गांवों में अनुमति दी जा रही है।

रालामंडल अभयारण्य के आसपास के गांवों में जमीनों के भाव ज्यादा हैं। बाजार भाव के हिसाब से रालामंडल से लगे आवासीय गांव मुंडला नायता की जमीनों का बाजार भाव 8600 रुपए वर्गमीटर है। वहीं, गाइडलाइन में यहां का भाव 4500 रुपए वर्गमीटर है। इसी तरह से पास में लगे बिहाडिया और सनावदिया गांव की गाइडलाइन के हिसाब से जमीनों की कीमत 3600 रुपए और 1500 रुपए वर्गमीटर है, जबकि बाजार में यहां की जमीनों की कीमत 3700 रुपए से ज्यादा है। इसी तरह से रालामंडल गांव की जमीनों की बाजार भाव से कीमत 8500 रुपए वर्गमीटर तक है, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक यहां जमीनों के भाव 4 हजार रुपए तक हैं। यहां गाइडलाइन के भाव इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अभयारण्य के पास में होने के कारण जमीनों को विकसित नहीं किया जा रहा है। उसमें बार-बार कई आपत्तियां आती हैं।

लाखों पेड़-पौधों के जरिए शहर तक शुद्ध हवा पहुंचाने वाले रालामंडल को 14 साल में दूसरी बार सरकार ने कैफेटेरिया, मनोरंजन केंद्र का लेवल लगाकर डी-नोटिफाई करने की कोशिश की। चिड़ियाघर को शिफ्ट करने का प्रस्ताव भले ही अधर में हो, पर ये स्पष्ट है कि मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के तहत इसे संरक्षित रखने के लिए आसपास कोई इंडस्ट्री या ऐसी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे यहां के ईको सिस्टम को नुकसान पहुंचे। चिड़ियाघर का प्रस्ताव लाने से पहले वन मंत्री विजय शाह पहले भी यहां के लिए एम्युजमेंट पार्क शुरू करने का सुझाव दे चुके हैं। यह तब का मामला है, जब पहली बार उन्होंने ये विभाग संभाला था। तब मुख्य वन संरक्षक एसएस निनामा ने एम्युजमेंट पार्क जैसी गतिविधि शुरू करने की तैयारी भी कर ली थी। अब जब शाह के पास फिर ये महकमा है तो चिड़ियाघर की शिफ्टिंग के लिए बैठकें शुरू हो गईं। हालांकि वन विभाग के अफसर इसमें बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभयारण्य का सुरक्षा घेरा बनाने के लिए ईको सेंसिटिविटी कमेटी बनी थी। कमेटी ने 50 मीटर का दायरा बनाया, जिसमें सभी गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गईं, लेकिन इस फैसले से पहले ही रालामंडल के चारों तरफ फार्म हाउस, टाउनशिप, कॉलेज, ढाबे खुल गए और अतिक्रमण भी हो गया। 2006-07 में रालामंडल को पीपीपी मोड पर देने का प्रस्ताव तत्कालीन वन संरक्षक ओपी चौधरी ने तैयार किया। 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से यहां ओपन एयर रेस्त्रां, कॉटेज सहित कई निर्माण की योजना बनी थी। डी-नोटिफाई की प्रक्रिया करते, उसके पहले लोगों का विरोध हो गया और इसे निरस्त करना पड़ा। प्रमुख सचिव वन विभाग अशोक वर्णवाल कहते हैं कि रालामंडल में आने वालों को अच्छी सुविधा मिल सके, इसके प्रयास किए जाएंगे। बच्चों के लिए गार्डन, झूले, पार्किंग, अभयारण्य के बाहर हल्का-फुल्का चाय, नाश्ता मिल जाए यह सब संसाधान यहां जुटाएंगे। इसे डी-नोटिफाई करने की योजना नहीं है।

● श्याम सिंह सिकरवार

समिति की मंजूरी बिना काम नहीं हो सकता

रिटायर्ड संयुक्त वन संरक्षक व रालामंडल के अधीक्षक रहे अशोक खराटे के मुताबिक, अभयारण्य में एक भी काम सुप्रीम कोर्ट की साधिकार समिति की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता। कैफेटेरिया, रेस्त्रां जैसी गतिविधि अभयारण्य के अंदर नहीं की जा सकती। रालामंडल जैसी स्थिति में है, उसे वैसा ही रखा जाना उचित होगा। यहां 90 चीतल, 45 काले हिरण, 60 नीलगाय, 15 सांभर, 6 चिंकारा, 6 भेड़की हैं। पांच सौ से ज्यादा मोर 247 हेक्टेयर में फैले हैं। हर साल चीतल की संख्या 20 से 25 बढ़ रही है। यहां सांपों की दर्जनों प्रजातियां हैं, उन पर स्टडी भी हो चुकी है। 30 से ज्यादा तरह की चिड़िया हैं, जिन्हें देखने पर्यटक आते हैं। सांसद शंकर लालवानी कहते हैं कि चिड़ियाघर भी रहना चाहिए और रालामंडल भी विकसित होना चाहिए। ज्यादातर जानवर चिड़ियाघर में ही रखे जाएं, जबकि अधिक संख्या वाले टाइगर, लॉयन और तेंदुए जैसे प्राणियों में से आधे को रालामंडल भेज देना चाहिए। इससे सभी प्राणियों को रहने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी।

एक्सप्रेस-वे ने पकड़ी रफ्तार

लक्ष्य से तेज है बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बैठक में बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से चल रहा है तथा मेन कैरियेज-वे जनवरी 2021 तक चालू हो जाएगा। 22 फ्लाईओवर्स का निर्माण प्रगति पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति करीब 24 प्रतिशत है, लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति अधिक है। 13 पुल बनाने हैं, जिनमें 12 का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे में घाघरा सेतु का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 91 किमी लंबाई की सड़क के मुख्य मार्ग को मार्च, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

बुंदेलखंड के लिए विकास की रीढ़ बनने जा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है। मिट्टी भराई का काम ज्यादातर जिलों में 45 से 60 फीसदी तक पूरा हो गया है, जबकि चित्रकूट में ये स्थिति 100 फीसदी है। छोटे-बड़े पुलों के निर्माण का काम भी अंतिम चरण पर है। अफसरों के मुताबिक, वर्ष 2021 के अंत तक वाहन फर्राटा भरने लगेंगे। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में 61 किलोमीटर का हिस्सा बांदा में हैं। 28 गांवों से होकर गुजरे एक्सप्रेस-वे के लिए 741.314 हैक्टेयर जमीन अधिग्रहीत हो चुकी है। तीन तहसीलों में 29 हैक्टेयर जमीन को लेकर फंसा पेंच भी सुलझ गया है। जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्था यूपीडा की कोशिशों से एक्सप्रेस-वे का काम तेज है। दो फ्लाईओवर, दो बड़े और 22 छोटे पुल, 14 पंप और 82 बॉक्स कलवर्ट का काम अंतिम चरण में है।

मार्च में कोरोना की दस्तक से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का काम बंद हुआ था, लेकिन अब फिर काम प्रगति पर है। चित्रकूट में परियोजना के नोडल अधिकारी और एडीएम जीपी सिंह ने बताया कि जिले में 10.24 किलोमीटर में मिट्टी और गिट्टी का काम पूरा हो चुका है। पेंटिंग का काम बाकी है। पूरे निर्माण में प्रगति 50 फीसदी के आसपास है। वहीं, महोबा में 10 किलोमीटर हिस्से में मिट्टी भराई का काम तेज है। पुल और बाकी निर्माण के काम भी गति पकड़ चुके हैं। जिले की सीमा में करीब 59 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में मिट्टी का काम दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 13.1356 हैक्टेयर भूमि के लिए किसानों से बातचीत कर हल निकालने की दिशा में काम अंतिम चरण पर है। ठेकेदारों के मुताबिक वे समय से काम पूरा कर लेंगे।

इटावा जिले में अब तक मिट्टी का 45 फीसदी, जबकि गिट्टी का 24 फीसदी काम पूरा हो चुका है। 45 किलोमीटर के दायरे में एक्सप्रेस-वे पर 135 छोटे-बड़े पुलों का काम 85 फीसदी पूरा हो चुका है। साथ ही सर्विस रोड भी बन रही है। 850 मीटर इटावा और 6 किलोमीटर औरैया की जमीन का मामला भी जल्द सुलझ जाएगा। एक्सप्रेस-वे निर्माण से इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, औरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद के लोगों को चित्रकूट पहुंचने में आसानी होगी।

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण के लिए 77.278 हैक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के काम में तेजी लाने का रास्ता खुल गया है। अवस्थी ने बताया कि एक्सप्रेस-वे में झांसी-इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग संख्या 35 भरतकूप के पास जनपद चित्रकूट से प्रारंभ होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ग्राम कुदरेल के पास जनपद इटावा में समाप्त होगा। इस परियोजना से जनपद चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपुर जालौन एवं इटावा लाभान्वित होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे एवं यमुना एक्सप्रेस-वे के माध्यम से जोड़ेंगे तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है और 13 अक्टूबर तक कुल 18.30 प्रतिशत भौतिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

अवस्थी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण **तीव्र गति** से कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए जनपद चित्रकूट में 3.2275 हैक्टेयर, जनपद बांदा में 7.8758 हैक्टेयर, जनपद हमीरपुर में 8.65 हैक्टेयर जमीन की स्वीकृति स्टेज 2 के लिए दी गई है। इसके अलावा जनपद महोबा में 2.4868 हैक्टेयर, जनपद जालौन में 11.913 हैक्टेयर, जनपद औरैया में 22.9393 हैक्टेयर तथा जनपद इटावा में 7.2940 अर्थात् कुल 77.278 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की स्टेज-2 की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दी गई है। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 77.278 हैक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने के लिए स्टेज वन की सैद्धांतिक स्वीकृति यूपीडा को प्रदान की जा चुकी है। स्टेज-1 की सभी शर्तों के अनुसार वन भूमि के स्थान पर यूपीडा ने उप्र वन विभाग को गैर वन भूमि उपलब्ध कराई है जिस पर यूपीडा द्वारा वन विभाग को दिए गए धन से पौधरोपण कार्य कराया जाएगा जिसकी देखभाल 10 वर्षों तक वन विभाग द्वारा की जाएगी ताकि पर्यावरण को सुदृढ़ बनाया जा सके।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे निर्माण की बड़ी कीमत हरियाली को चुकानी पड़ी है। एक्सप्रेस-वे वाले सभी सात जिलों में एक लाख 90 हजार से ज्यादा पौधों और पेड़ों का सफाया हुआ है। फिलहाल इनके स्थान पर पौधरोपण नहीं हुआ है। एक्सप्रेस-वे की भेंट सबसे ज्यादा पेड़ बांदा जिले में चढ़े हैं। पौधों का नुकसान सर्वाधिक औरैया जिले का हुआ है। करीब 14 हजार 849 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का पिछले वर्ष से युद्धस्तर पर काम चल रहा है। भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होने के बाद मिट्टी का काम भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। कुछ स्थानों पर पक्का निर्माण शुरू हो गया है। एक्सप्रेस-वे में शामिल सातों जिलों में बड़ी संख्या में पौधे और भारी-भरकम पेड़ थे। इन सभी को मशीनों से धराशायी कर दिया गया है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

शिवराज बने सिरमौर

मप्र की 28 सीटों पर हुआ उपचुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं था। इस चुनाव परिणाम पर प्रदेश सरकार का भविष्य निर्भर था। इस चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए पार्टियों ने वह सभी हथकंडे अपनाए जो नैतिक और अनैतिक भी थे। लेकिन उपचुनाव जीतने में माहिर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार भी करिश्मा दिखाया और 19 सीटें जीतकर न केवल अपनी सरकार बरकरार रखी, बल्कि भाजपा को भी मजबूती प्रदान की।

● राजेंद्र आगाल

मप्र की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि वाकई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मप्र की राजनीति के सिरमौर हैं। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके मुहर लगा दी है। इस उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मामा की छवि के साथ चुनाव प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशियों को हराने के लिए जो भी हथियार चलाए थे, सब असफल रहे। शिवराज के आगे न प्रदेश कांग्रेस प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कोई कमाल कर पाए, और न 'गद्दार' व 'आइटम' जैसे कांग्रेस के जुमलों का जनता पर कोई असर हुआ। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज कर और मजबूती पा ली है। अब भाजपा के 126 विधायक हो गए हैं जबकि बहुमत के लिए 115 (एक सीट खाली है) विधायक ही पर्याप्त हैं।

प्रदेश की जनता ने कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तथा दिग्विजय सिंह की जोड़ी को नकार दिया है। ग्वालियर-चंबल अंचल की कुछ सीटों को छोड़कर शेष प्रदेश की सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। अधिक सीटों पर उपचुनाव की वजह से इसे सत्ता का 20-20 मैच भी माना जा रहा था।

मप्र में हुए उपचुनावों के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान का सितारा अभी भी बुलंद है। मप्र के लोगों में 'मामा' के प्रति अभी तक थकान पैदा नहीं हुई है। लोगों ने नोटबंदी की विभीषिका, जीएसटी के कुलांचे, कोरोना की महामारी और बेरोजगारी आदि कई समस्याओं का सामना किया लेकिन इसके बावजूद शिवराज सरकार के प्रति उसका विश्वास डिगा नहीं है। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 समर्थक विधायकों ने इसी वर्ष मार्च में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर और कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इससे कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

भाजपा हुई दमदार

मप्र की 28 विधानसभा सीटों पर धमाकेदार जीत के साथ भाजपा ने अगले तीन साल के लिए सत्ता में रहने की चाभी हासिल कर ली है। दलबदल पर ठप्पा लगाकर जनता ने भाजपा और शिवराज को बेखटके राज करने का मौका दे दिया है। कोरोनाकाल में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में न तो भाजपा और न ही कांग्रेस की राह आसान थी। वहीं दोनों ही दलों के सामने कई चुनौतियां भी थीं। दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मतदाताओं को उनके घरों से बाहर लाने की थी। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा पैदा किए गए विश्वास और राजनीतिक पार्टियों के आव्हान पर मतदाता वोट डालने निकले और रिकार्ड 71 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई। पूरे चुनाव काल में देखें तो भाजपा और उसके प्रत्याशियों को कई जगह नाराजगी का सामना करना पड़ा। मतदाता उन पूर्व कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों से विशेष रूप से नाराज थे जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बावजूद भी, मतदाता कांग्रेस के प्रति उत्साही नहीं थे। इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के 15 महीने के शासन से संतुष्ट न होना था।

शिवराज है तो विश्वास है

उपचुनाव के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि मप्र में शिवराज है तो विश्वास है। मप्र में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया था, लेकिन करीब दो साल बाद हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मतदाताओं ने एक बार फिर भाजपा सरकार के 7 महीने के कामकाज पर भरोसा जताया है। इस परिणाम के बाद भी 230 सदस्यों वाली मप्र विधानसभा में 229 विधायक ही रहेंगे। उपचुनाव के दौरान ही दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 115 हो गया और कांग्रेस के सामने सभी 28 सीटें जीतने की चुनौती आ गई। इसके बाद से ही भाजपा के लिए रास्ता आसान नजर आने लगा था, लेकिन कांग्रेस की ओर से सभी सीटें जीतने का दावा किया जाता रहा। उपचुनाव के नतीजों और कांग्रेस के दावों में जमीन-आसमान का अंतर रहा। परिणामों व रूझानों ने साबित कर दिया कि मप्र में शिवराज की लोकप्रियता सबसे अधिक है। कोरोनाकाल में मतदान प्रतिशत बढ़ने से लेकर अधिक संख्या में महिलाओं के मतदान करने के पीछे भी उनकी मामा की छवि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कामयाबी में कांग्रेस सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का योगदान भी शामिल है। यकीनन सिंधिया अब भाजपा में एक समानांतर सत्ता केंद्र बनकर उभरेंगे। हां, उनके लिए यह जरूर चिंता की बात होगी कि वे अपने ही गढ़ में साख नहीं बचा सके हैं। मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 समर्थकों के साथ कमलनाथ सरकार की नैया डुबोकर भाजपा का गमछा गले में डाला था। बाद में तीन और कांग्रेस विधायक फुट लिए। तीन सीटें विधायकों की मृत्यु के कारण खाली हुईं। कुल 28 सीटों पर उपचुनाव में 19 सीटें जीतकर भाजपा-शिवराज ने अगले तीन साल के लिए प्रदेश पर निर्द्वन्द राज करने का जनादेश हासिल कर लिया है।

सरकार के सामने चुनाव बहिष्कार भी बड़ी चुनौती थी। कई लोग अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर पहले ही चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर चुके थे। कई कर्मचारी संगठन, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मी, पटवारी भर्ती नियुक्ति समेत रोजगार और सरकारी भर्तियां न निकालने से नाराज युवाओं द्वारा चुनाव बहिष्कार की आशंका थी। ऐसे में शिवराज ने मोर्चा संभाला और सभी को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार में अभी वे टेम्प्रेरी मुख्यमंत्री हैं। आप वोट देकर भाजपा को जिताइए और मैं परमानेंट मुख्यमंत्री होते ही आपकी मांगे पूरी कर दूंगा। मतदाताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर मुहर लगाते हुए 28 में से 19 सीटें भाजपा की झोली में डाल दीं।

9 मंत्रियों को मिली जीत

28 सीटों पर हुए उपचुनाव में 12 मंत्रियों (तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को इस्तीफा देना पड़ा था) सहित 355 उम्मीदवार मैदान में थे। उपचुनावों मैदान में उतरे प्रदेश के 12 मंत्रियों में से 3 को हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ, शिवराज कैबिनेट के 9 मंत्री चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सभी मंत्री मार्च में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और विधायक पद से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हुए थे। इनमें अधिकांश ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। उपचुनाव के घोषित हुए परिणामों के अनुसार, प्रदेश सरकार में सिंधिया समर्थक 2 मंत्री इमरती देवी डबरा से 7,633 मतों के अंतर और गिर्राज दंडोतिया दिमनी से 26,467 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा एक अन्य मंत्री एदल सिंह कंषाना भी सुमावली सीट से 10,947 मतों से चुनाव हार गए हैं। वहीं 9 मंत्री ओपीएस भदौरिया (मेहगांव), प्रद्युम्न सिंह तोमर (ग्वालियर), सुरेश धाकड़ (पोहरी), महेन्द्र सिंह सिसोदिया (बामोरी), ब्रजेन्द्र सिंह यादव (मुंगावली), डॉ. प्रभुराम चौधरी (सांची), राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव (बदनावर) (सभी सिंधिया समर्थक) तथा बिसाहूलाल सिंह (अनूपपुर) और हरदीप सिंह डंग (सुवासरा)

कमलनाथ की आगे की राह आसान नहीं

अपने आधी सदी के राजनीतिक जीवन में सरकार को खो देना और अब उपचुनाव में हार के बाद वे शायद ही कभी इस सदमे से उबर पाएं। लेकिन गत दिनों विधायक दल की बैठक में कमलनाथ नए जोश में नजर आए। उपचुनाव के नतीजे को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा कमलनाथ के दिल्ली रवाना होने के बयानों पर मची हलचल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जो कहते हैं कमलनाथ प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, वह यह सुन लें, कमलनाथ पूरे जीवन प्रदेश में ही रहकर कांग्रेसियों के साथ जनता की सेवा करने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने कभी किसी कांग्रेसी का सिर झुकने नहीं दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कमलनाथ ने उपचुनाव में दम लगाने वाले सभी कांग्रेसियों को धन्यवाद दिया है। कमलनाथ ने कहा कि नतीजे पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन वह हिम्मत हारने वालों में से नहीं है और संघर्ष का रास्ता खुला रखेंगे। उन्होंने कहा कि साल 2023 के लिए अभी से कांग्रेसियों को कमर कसनी होगी। इसके अलावा आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी कमलनाथ ने कांग्रेसियों को अभी से जुटने को कहा है। कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर संघर्ष करना होगा।

से विजयी रहे। गैर विधायक के तौर पर 6 माह का मंत्री पद का कार्यकाल पूरा होने पर कुछ दिन पहले ही मंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले सिंधिया के कट्टर समर्थक तुलसीराम सिलावट (सांवेर) ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 53 हजार से अधिक मतों जीत दर्ज की। गोविंद सिंह राजपूत ने सुरखी सीट से चुनाव जीता। इनके अलावा भाजपा के अम्बाह से कमलेश जाटव, भांडेर से रक्षा सिरोनिया, अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी, मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी, हाटपिपल्या से मनोज चौधरी, मांधाता से नारायण सिंह पटेल, नेपानगर से सुमित्रा देवी और जौरा से सूबेदार सिंह भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे।

उधर, उपचुनाव में 28 में से कांग्रेस के मात्र 9 प्रत्याशी ही जीत प्राप्त कर सके। जिनमें सुमावली से अजबसिंह, मुरैना से राकेश मवई, दिमनी से रवींद्र सिंह, गोहद से मेवाराम जाटव, डबरा से सुरेश राजे, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, करैरा से प्रागीलाल कांग्रेस, ब्यावरा से रामचंद्र दांगी और आगर से विपिन वानखेड़े शामिल हैं।

कांग्रेस का मुद्दा नहीं आया काम

कांग्रेस ने उपचुनाव को 'गद्दार' और 'बिकाऊ-टिकाऊ' पर फोकस किया था लेकिन ये दोनों ही जुमले कांग्रेस के काम नहीं आए। कांग्रेस के साथ दगाबाजी करने और कथित तौर पर भाजपा के हाथों बिक जाने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक अबकी बार भाजपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचने में सफल हो गए। टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दे के साथ उपचुनाव में पूरा जोर लगाने वाली कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव परिणाम से यह तो साफ हो गया है कि जनता ने बिकाऊ और टिकाऊ को नकारते हुए शिवराज पर विश्वास जताया है। दरअसल, उपचुनाव में शिवराज और कमलनाथ के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। जिस तरह से सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके समर्थक भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में चले गए थे। इसके अल्पमत में आई कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और शिवराज ने एक बार फिर प्रदेश की कमान संभाली। इसके बाद उपचुनाव के लिए शिवराज सरकार ने सिंधिया समर्थक अपने 14 मंत्री मैदान में उतारे थे। जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने अपने प्रचार-प्रसार के दौरान खूब टिकाऊ और बिकाऊ का नारा लगाया। लेकिन परिणाम कुछ और निकले। इनमें ज्यादातर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग, महेन्द्र सिंह सिसोदिया और बिसाहूलाल सिंह ने 2018 के चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में ज्यादा वोटों से जीते हैं।

मप्र में उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा के सत्ता पलट पर मुहर लगाई। कांग्रेस के बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ के मुद्दे को खारिज कर दिया। शिवराज के चेहरे पर फिर भरोसा जताया, साथ ही सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के फैसले को भी सही साबित किया है। प्रदेश में सत्ता का भविष्य तय करने वाले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि उसे न तो कमलनाथ सरकार की कर्जमाफी आकर्षित कर सकी और न ही सौदेबाजी के आरोप पसंद आए। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जनता को न तो पार्टी की आक्रामक रणनीति स्वीकार हुई और न ही संगठन टीम भाजपा के आगे टिक सका। मैदानी मोर्चे पर न तो युवा कांग्रेस नजर आई और न ही छात्र इकाई (एनएसयूआई)। महिला कांग्रेस सहित अन्य प्रकोष्ठों की भूमिका भी नगण्य रही। प्रत्याशियों का भी प्रचार अभियान बिखरा-बिखरा रहा। माना जा रहा है कि चुनाव परिणामों का असर संगठन पर भी पड़ेगा और अब परिवर्तन की आवाज बुलंद होगी। उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने कर्जमाफी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए विधायकों की सौदेबाजी को मुख्य मुद्दा बनाया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता इन मुद्दों के ईद-गिर्द ही चुनाव अभियान को केंद्रित रखे रहे। कर्जमाफी को लेकर तमाम प्रमाण भी प्रस्तुत किए पर जनता ने इसे नकार दिया। वहीं, सौदेबाजी, बिकाऊ-टिकाऊ के आरोप, गद्दारी के रेट कार्ड जारी करना भी पसंद नहीं आया। पहली बार मतदान केंद्र स्तर पर तैयारियां की गई थी लेकिन टीम भाजपा के आगे यह टिक नहीं सकी।

भाजपा की चौकड़ी का दिखा दम

विपरीत परिस्थितियों में हुए उपचुनाव में भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाएगी। क्योंकि इस उपचुनाव में कोरोना, आर्थिक मंदी, बगावत, भितरघात के साथ ही भाजपा को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा

था। लेकिन पार्टी की शीर्ष चौकड़ी शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा के साथ ही पार्टी के संगठन की जमीनी मेहनत का बराबर योगदान रहा है। इस जीत में जितना शिवराज, भाजपा संगठन का योगदान है उतना ही नए नवेले भाजपाई ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है। उपचुनाव में न केवल उनकी साख दांव पर लगी थी बल्कि उनके आगे के सियासी सफर का रास्ता भी इसी नतीजे से निकलना था। कोई शक नहीं कि अब उनके केंद्र में मंत्री बनने की राह आसान हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी उपचुनाव में खूब मेहनत की। उनका एक पांव मप्र में तो दूसरा दिल्ली में रहता था। उधर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के लिए तो यह चुनाव अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। उन्होंने संगठनात्मक जिम्मेदारी के साथ ही उपचुनाव की जिम्मेदारी भी पूरी तन्मयता से निभाई। इनके अलावा नरोत्तम मिश्रा की भूमिका भी किसी से कम नहीं रही।

भाजपा की संगठित रणनीति का ही परिणाम है कि नतीजों ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। जिन सीटों पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, वहां भी उसके प्रत्याशी हार गए। कई कांग्रेस प्रत्याशियों की प्रतिद्वंद्वी से हुई हार का अंतर काफी अधिक रहा। इसकी एक वजह यह भी रही कि कांग्रेस में संगठन का बिखराव रहा। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर-चंबल अंचल में हमेशा से ही चुनाव परिणाम सिंधिया राजघराने से प्रभावित रहे हैं। यह पहला मौका है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद इस अंचल में भाजपा की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाली थी। विपरीत हालात में भी भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षित तौर पर संतोषजनक रहा। ऐसे में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने से लेकर बरकरार रखने में सिंधिया का ही योगदान माना जाएगा। भाजपा के बड़े नेताओं का मानना है कि सिंधिया के कितने ही समर्थक जीतें हों, लेकिन उनका कद भाजपा में बढ़ेगा। इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि भाजपा सरकार बहुमत में आई है तो उसका कारण भी सिंधिया ही हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर मनाए गए जश्न में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की शान में कसीदे काढ़कर ये संकेत दे दिए कि 'महाराज' को अभी भाजपा पूरी तवज्जो देगी।

अब इनका क्या होगा?

विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की शानदार वापसी हुई है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर-चंबल में 16 में से 7 सीट नहीं जिता पाए हैं। पिछले चुनाव में उपचुनाव वाली सभी सीट कांग्रेस के पास थी। इन सीटों पर सिंधिया के चेहरे पर जीत मिली थी, लेकिन उपचुनाव में सिंधिया का जादू नहीं चला है। ग्वालियर-चंबल चुनाव मैदान में उतरे 6 मंत्रियों में से तीन को तगड़ी हार भी झेलना पड़ी है। वहीं कुछ सीटों पर तो जीत का अंतर भी काफी कम रहा है। उपचुनाव में ग्वालियर-चंबल अंचल की 13 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का पूरा फोकस रहा था। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य दिग्गजों ने सभाएं और रोड शो किया था। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सचिन पायलट ने सभा और रैली की थी तो वहीं दूसरी पंक्ति के नेताओं ने तो अंचल में कैंप भी किया था। इन 13 सीटों में से कुछ सीटों पर मुकाबला भी काफी रोचक रहा है। भांडेर सीट पर भाजपा की रक्षा सिरोनिया और कांग्रेस के फूल सिंह बरैया के बीच मुकाबला बेहद नजदीकी रहा था। यहां भाजपा प्रत्याशी की सबसे छोटी 161 मतों से जीत हुई है। इसमें खास बात यह है कि यह 13 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाली मानी जाती हैं। इनमें से 7 सीटों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। खासतौर पर अंचल की 3 सीटों पर मंत्रियों के चुनाव हारने से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। अंचल के चुनाव नतीजों से साफ है कि कहीं न कहीं सिंधिया अपने ही गढ़ में कमजोर साबित हुए हैं।

सिंधिया अग्निपरीक्षा में पास

जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें धोखेबाज, गद्दार कहा। इसके बाद ग्वालियर-चंबल अंचल में जीत दर्ज करना ये उनके लिए उपलब्धि है। क्योंकि इन इलाकों में महल का बड़ा मुकाम और प्रतिष्ठा है और वहीं से राजनीति होती है ऐसे में अब भाजपा ने उस पर कब्जा कर लिया है। पहली बार जब चुनाव हुए थे तो ये हिंदू महासभा का गढ़ माना जाता था और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने राजमाता सिंधिया को कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाया था। वो चुनाव भी लड़ीं। कांग्रेस जानती थी कि ये क्षेत्र राइट विंग विचारधारा की तरफ झुक सकता है और इसी बात का कांग्रेस को डर हमेशा था लेकिन इस उपचुनाव में भाजपा से मिली भारी हार से अब ये क्षेत्र उसके हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है। लेकिन क्या इस जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में शीर्ष पद पर जाने की संभावना बढ़ गई है? ज्योतिरादित्य का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली माना जाता है। उनकी अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर अच्छी कमांड है। वे यूपीए के दौरान भी मंत्री रह चुके हैं तो ऐसे में इन सभी चीजों का समावेश करके देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद दूसरी पंक्ति के नेताओं जैसे देवेंद्र फडणवीस, स्मृति इरानी, योगी आदित्यनाथ की कतार में अब उन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है।

जिद में कांग्रेस ने गंवाई कई सीटें

उपचुनाव के परिणाम आने के बाद किए गए विश्लेषण में यह तथ्य निकलकर आया है कि अगर कांग्रेस राजनीतिक चतुराई से चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ और होते। कांग्रेस कई सीटें अपनी जिद के कारण हार गई। मप्र उपचुनाव संग्राम में ग्वालियर-चंबल में दो सबसे बड़े किरदार थे। पहले- ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे- बसपा के उम्मीदवार। राजनीतिक कद की लड़ाई में कांग्रेस ने पहले सिंधिया को खोया और फिर जिद में बसपा से दूरी बना ली। नतीजा सबके सामने है कि ग्वालियर-चंबल की सीटों पर चुनाव लड़ी बसपा कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हो गई। उसने 5 सीटों पर वोट

काटे और जीत भाजपा की झोली में डाल दी। यही कारण रहा कि भाजपा 19 सीटें जीती और कांग्रेस 9। यदि बसपा-कांग्रेस साथ लड़ती तो 5 सीटों पर परिणाम पलट सकती थी। ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम भाजपा, कांग्रेस गठबंधन 14-14 सीट पर बराबर रह सकता था। आंकड़े देखें, तो भाजपा 19 सीट ला पाई है और कांग्रेस दहाई का अंक भी नहीं छू सकी। उसे 9 ही सीट मिलीं, लेकिन यदि भांडेर, जौरा, मल्हरा, मेहगांव और पोहरी जैसी सीटें देखें, तो वहां कांग्रेस की हार का किरदार ही बसपा ने निभाया।

भांडेर सीट पर कांग्रेस के फूलसिंह बरैया और भाजपा की रक्षा सिरोनिया के बीच रोचक मुकाबला हुआ। शुरुआत में बरैया बढ़त में थे और मजबूत भी लगे, लेकिन बाद में पांसा पलट गया। बसपा के महेंद्र बौद्ध ने 7500 वोटों लाकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। बरैया को 45.1 प्रतिशत वोट मिले हैं, जबकि रक्षा को 45.3, जबकि बौद्ध 5.6 प्रतिशत वोट ले गए। यानी यदि कांग्रेस और बसपा के वोट जोड़ दें, तो वह विजयी पार्टी भाजपा से 5.4 पतिशत प्रतिशत ज्यादा होता है। जौरा सीट भी त्रिकोणीय मुकाबले के कारण कांग्रेस के हाथ से छिटक गई। यहां कांग्रेस के पंकज उपाध्याय को 31.2 प्रतिशत वोट मिले हैं, जबकि विजेता उम्मीदवार भाजपा के सूबेदार सिंह को 39 प्रतिशत। इनके बीच बसपा के सोनेराम कुशवाह 28 प्रतिशत वोट ले गए हैं। उनके वोट लगभग-लगभग कांग्रेस से दो प्रतिशत ही कम है। पंकज और सोनेराम के वोट मिला दें, तो वह 59 प्रतिशत प्रतिशत होता है जो कि भाजपा से 20 प्रतिशत ज्यादा हैं। मल्हरा में भाजपा के प्रद्युम्न लोधी की जीत के सबसे बड़े किरदार बसपा के अखंड प्रताप सिंह हैं। वे यहां 20,502 वोट यानी 13.7 प्रतिशत वोट ले गए। कांग्रेस को 33.4 प्रतिशत वोट ही मिले हैं। यदि कांग्रेस की रामसिया भारती और अखंड दादा के वोट जोड़ दें, तो 47.1 प्रतिशत होते हैं। यह भाजपा के उम्मीदवार प्रद्युम्न से दो प्रतिशत ज्यादा हैं। विजेता प्रद्युम्न लोधी को 45.1 प्रतिशत वोट मिले हैं। मेहगांव में मंत्री ओपीएस भदौरिया चुनाव जीत गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से। उन्हें 45.1 प्रतिशत वोट मिले हैं। कांग्रेस के हेमंत कटारे को 37.7 प्रतिशत वोट मिले हैं, जिनके वोट काटते गए बसपा के योगेश नरवरिया। उन्हें 22 हजार 305 वोट मिले हैं जो कि कुल वोट का 13.7 प्रतिशत है। यदि बसपा और कांग्रेस के वोट जोड़ें तो वह मंत्री भदौरिया के वोट शेयर से 6.3 प्रतिशत ज्यादा है। पोहरी में कांग्रेस के हरिवल्लभ शुक्ला की हार का सबसे बड़ा कारण बसपा के कैलाश कुशवाह ही रहे और कांग्रेस को यहां तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। यहां बसपा का वोट शेयर 26 प्रतिशत रहा जबकि कांग्रेस का 25.2 ही रहा। भाजपा के विजेता उम्मीदवार मंत्री सुरेश धाकड़ ने 39.2 प्रतिशत वोट पाए। यदि बसपा-कांग्रेस साथ देखें तो यह भाजपा से 12 प्रतिशत ज्यादा है।

सिंधिया बनेंगे केंद्र में मंत्री

मप्र में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से भाजपा तो उत्साहित है ही लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उत्साहित कुछ समय पहले भाजपा की गोद में बैठने वाले पूर्व कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक हैं। इसकी वजह बेहद साफ है। उन्होंने इस चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाते हुए मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने में सफलता हासिल की है बल्कि इस चुनाव में भाजपा को जीत दिलाकर ये भी बता दिया कि इस क्षेत्र में उनका वर्चस्व पहले की ही तरह जस का तस बना हुआ है। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। इस जीत से उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ नहीं बल्कि उनका क्षेत्र है। आपको बता दें कि ये उपचुनाव कांग्रेस के कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक साख का सवाल बन चुका था। इसकी पटकथा तभी लिखी जा चुकी थी जब मुख्यमंत्री न बन पाने से नाराज ज्योतिरादित्य ने भाजपा ज्वाइन की थी। तभी से दोनों के बीच सबसे बड़ी चुनौती अपनी साख को बचाकर रखने की थी, जिसमें काफी हद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया सफल हुए हैं। कहा जा सकता है कि कमलनाथ के राजनीति के वर्षों पुराने अनुभव पर सिंधिया भारी पड़े हैं। सिंधिया की ये जीत केवल यहीं तक सीमित नहीं रही है। अब इस जीत से उनके आगे की राह भी खुल गई है। ये राह उन्हें कैबिनेट में शामिल होने के दरवाजे खोलती दिखाई दे रही है।

हालांकि इस बात की चर्चा पहले भी होती रही है कि सिंधिया को केंद्र में कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। जिस वक्त उन्होंने भाजपा का परचम थामा था उस वक्त भी ये चर्चा जोरों पर थी कि उन्हें इसके एवज में मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन अब इसके चांसेज काफी बढ़ गए हैं। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह उनकी उपचुनाव में हुई जीत और दूसरी वजह मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों की जगह।

कांग्रेस की हार का ठीकरा 'नाथ' के सिर

उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार का ठीकरा निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सिर पर ही फूटेगा। 2018 में सरकार बनने के बाद उसे बचाए रखने में नाकाम रहे नाथ इस हार के बाद अपने सियासी जीवन की सबसे बड़ी मात का दोष किसी और के मत्थे मढ़ने की हालत में भी नहीं हैं। दोबारा सरकार में आने के लिए पार्टी आलाकमान ने उन्हें पूरी तरह फ्री हैंड दिया था। उम्मीदवारों के नाम तय करने से लेकर पूरे चुनाव अभियान में वे एकला चलो की नीति पर डटे रहे। चंबल से लेकर मालवा तक, निमाड़ से लेकर बुंदेलखंड तक सब जगह अकेले ही दौड़ते रहे। रस्म अदायगी को दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, अरुण यादव आदि का साथ लिया। दिग्विजय सिंह को चुनाव प्रचार के आखिरी तीन-चार दिन में मैदान में भेजा गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उपचुनाव में चेहरा भी वही थे, मुद्दा भी वही। नारे भी उन पर, हरकारे भी उनके ही। अगर जीतते तो जीत का सेहरा उनके ही सिर बंधता। हारे हैं तो हार का हार भी उन्हें अपने गले में ही पहनना होगा।

आंकड़े बदल रहे स्थिति वैसी ही

देश में कुपोषण से मुक्ति के लाख दावे-वादे और घोषणाएं की जाएं परंतु विभागीय आंकड़े ही सबकी पोल खोलते रहते हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि दुनियाभर के बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। विकासशील और गरीब देशों में यह समस्या ज्यादा है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि पिछले तीन दशक से दुनिया के तमाम देश बच्चों के कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए संजीदगी से काम कर रहे थे और ऐसा हो पाने का एक कारण यह माना गया है कि वैश्विक आर्थिक विकास से यह गुंजाइश बनी। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कोई बहुत उत्साहजनक नतीजे देखने को नहीं मिले।

देश के सबसे कुपोषित बच्चों वाले राज्यों में मप्र भी शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बच्चे कम वजन और 1 लाख से ज्यादा अतिकम वजन वाले सामने आए हैं। मतलब साफ है कि प्रदेश में कुपोषण थम नहीं रहा है। मप्र में कुपोषण लगातार पैर पसार रहा है। साल 2017 से लेकर 2019 तक की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा बच्चे कम और अति कम वजन वाले दर्ज किए गए हैं। 2020 में विभाग पोर्टल पर आंकड़ा दर्ज नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने काम ही नहीं किया है।

वैसे मौजूदा वैश्विक मंदी और महामारी ने बच्चों पर कुपोषण की आफत का अंदेशा और बढ़ा दिया। इस बात की तसदीक पिछले पखवाड़े संयुक्त राष्ट्र के दो बड़े अधिकारियों के बयानों से भी हो रही है। ये दो अधिकारी हैं संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक प्रमुख रोजमेरी डिकार्लो और संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी मामलों के प्रमुख मार्क लोकॉक। लोकॉक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि कोराना संकट ने आर्थिक रूप से कमजोर देशों की स्वास्थ्य परिस्थितियों पर बहुत बुरा असर डाला है। लिहाजा उन देशों में गरीबी और भुखमरी बढ़ेगी, लोगों की औसत आयु कम हो जाएगी और शिक्षा की स्थिति खराब हो जाएगी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह कि बच्चों की मौतों की संख्या बढ़ जाएगी। जाहिर है, ये अंदेशे फिजूल नहीं हैं। हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कोराना आने के बाद से दुनिया में हर महीने कमोवेश दस हजार बच्चे सिर्फ भूख से मर रहे हैं। आर्थिक मंदी के गंभीर होने पर यह आंकड़ा और भयावह हो सकता है।

अगर भारत के संदर्भ में इसे देखें तो इस समय आर्थिक मंदी का सबसे घना साया हमारे ऊपर ही है। विशेषज्ञों ने यह हिसाब लगाकर भी बता दिया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के बाकी बचे 5 महीनों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के आसार नहीं हैं। वैसे भी इस साल की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शून्य से भी 23.9 फीसदी की गिरावट के बाद आर्थिक स्थिति को लेकर दुविधा में रहने का कोई कारण बचा नहीं है। दूसरी ओर कोरोना अभी भी अपनी चरम स्थिति में पहुंचा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि संकटकाल में आगे क्या करना जरूरी होगा? खासतौर पर हालात से जूझने के लिए प्राथमिकताएं तय करना ही पड़ेंगी और तात्कालिक व दीर्घावधि की योजनाएं फौरन बनानी पड़ेंगी। बेशक तात्कालिक योजनाओं में देश में कामधंधों को पटरी पर लाना पहला काम होगा। लेकिन दीर्घावधि की योजनाओं में आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जाहिर है, उसके लिए देश के बच्चों के स्वास्थ्य को इस आफत से बचाना उतना ही जरूरी है।

बच्चों में कुपोषण के मोर्चे पर दुनिया में कितना भी काम क्यों न हुआ हो, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अपने देश में आज भी 5 साल से कम उम्र के करीब 8 लाख 80 हजार बच्चे हर साल मर रहे हैं। इनमें 69 फीसदी बच्चों की मौत सिर्फ कुपोषण से होती है। यह आंकड़ा यूनिसेफ की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, 2019 का है। हालांकि सरकार इस आंकड़े को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती दिखती। उसका तर्क होता है कि पिछले कुछ दशकों से बाल विकास के संकेतकों में सुधार आया है। बेशक पिछले तीस-चालीस साल के दौरान रहीं तमाम सरकारों ने बच्चों पर ज्यादा खर्च करके हालात को कुछ संभाला है। इसी दौरान स्कूली बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन की विश्व प्रसिद्ध योजना का क्रियान्वयन भी हुआ। पिछले दशक में खाद्य सुरक्षा कानून ने भी काफी असर डाला। इसका सीधा असर बच्चों में पोषण से जोड़ा जा सकता है।

इधर कुछ वर्षों में जिस तरह से आर्थिक तंगी बढ़ी है, उससे इस तरह की योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाने के काम में अड़चनें आई हैं। कई तिमाहियों से जिस तरह से देश की माली हालत गिरावट पर है, उसका असर बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने की योजनाओं पर पड़ा है। इधर, लगातार बढ़ती आबादी ज्यादा सरकारी खर्च की मांग कर रही है। गौरतलब है कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हम भुखमरी के वैश्विक सूचकांक में अतिगंभीर श्रेणी में हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 117 देशों के बीच हमारा नंबर 102 वां है। यानी देश की मौजूदा माली हालत के मद्देनजर यह मानने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि बच्चों में कुपोषण की समस्या और गहराती जाने वाली है।

● राजेश बोरकर

पर्याप्त मात्रा में धन की दरकार

जहां तक बच्चों और किशोरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सवाल है, तो यह भी तय है कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन की दरकार होगी। अलबत्ता सरकार के तरफदार विशेषज्ञ एक ही बात निकालकर लाएंगे कि अगर आर्थिक मोर्चे को संभाल लिया जाए यानी पहले सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा लिया जाए तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए कि माली हालत सुधारने का काम लंबा खिंचने वाला है। इस मोर्चे पर पिछले दो साल से हम जिस तरह से लगातार नीचे आते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर आने वाले साल-दो साल में किसी चमत्कार की उम्मीद बेमानी है और तब तक स्थायी नुकसान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा अंदेशा बच्चों की एक भरी-पूरी पीढ़ी के अविकसित या कमजोर हो जाने का है। यह अपूरणीय क्षति होगी।

केंद्र और राज्यों के बीच टकराव

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बेहद जरुरी है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि केंद्र की भाजपानीत एनडीए सरकार का राज्यों की अन्य पार्टियों की सरकार से समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि राज्यों का विकास तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही राज्यों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है।

आखिर केंद्र और राज्यों के बीच शून्य की एक स्थिति पैदा हो गई है। कारण यह है कि मजबूत केंद्र शायद राज्यों के प्रति अपने दृष्टिकोण में सहभागिता की भूमिका से दूर चला गया है और इसका नतीजा राज्यों में केंद्र के प्रति सम्मान की कमी के रूप में सामने आया है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ बहुतायत में प्रतिरोध है। महाराष्ट्र सरकार का बिना उसकी मंजूरी के सीबीआई जांच के फैसले पर रोक लगाना इसका एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा केरल जैसे प्रदेशों में इस बात को लेकर केंद्र के प्रति विकट नाराजगी है कि केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रही है।

पंजाब, जो केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों का केंद्र है; ने विधानसभा में केंद्रीय कानूनों को नहीं मानने के लिए बाकायदा प्रस्ताव पास किया है और अपने स्तर पर तीन विधेयक पास किए हैं। यह इस बात का संकेत है कि राज्य इस मसले पर लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुका है; भले ही उसे भी अपने ये विधेयक पास करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत रहेगी। पंजाब के इन विधेयकों में एमएसपी से नीचे की उपज की बिक्री या खरीदी करने पर कम से कम तीन साल की कैद का प्रावधान है। राज्य इस कानून के अधीन समवर्ती सूची के तहत लागू केंद्रीय कानूनों में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि उन्हें इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी, क्योंकि इसके बगैर यह कानून लागू नहीं हो सकते।

वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधारों के प्रस्ताव के नाम पर अध्यादेशों का मार्ग अपनाने के बाद से केंद्र व राज्यों में विश्वास की कड़ी टूटी है। इसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में वहां के लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका (वैक्सीन) देने के भाजपा के वादे ने अन्य राज्यों में आक्रोश पैदा किया है। उनका मानना है कि भाजपा ने ऐसा करके सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक महामारी की आड़ लेकर अनैतिक रूप से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। यही नहीं, केंद्र और राज्य के संबंधों में एक और खराब मोड़ तब आया, जब उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई की किसी भी जांच के लिए राज्य की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया।

केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। आजादी के पहले चार दशक के दौरान हमने केंद्र और राज्यों के **अच्छे संबंधों** के तौर पर एक मजबूत केंद्र और अब की अपेक्षा शानदार राज्य भी देखे हैं। इसके बाद 1989 से 2014 के बीच गठबंधन युग के चलते क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने के साथ एक कमजोर केंद्र और मजबूत राज्य सामने आए। 2014 के बाद एक मजबूत केंद्र का उदय हुआ और राज्य फिर कमजोर दिखने लगे। लेकिन इन दिनों केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन छिन्न-भिन्न हुआ है; क्योंकि पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल समेत कई बड़े राज्य विपक्ष के पास हैं। यहां यह बताना जरूरी

केंद्र के रवैए से खफा हैं कैप्टन

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से पंजाब में बढ़ते संकट की ओर ध्यान देने की अपील की थी। समस्या का समाधान करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने 21 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन को पत्र भेजकर मीटिंग का समय मांगा था। 29 अक्टूबर को ज्ञापन के जवाब में सीएमओ के मीटिंग के आग्रह को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि प्रांतीय संशोधन बिल अभी राज्यपाल के पास लंबित पड़े हैं। इस रवैए से कैप्टन काफी नाराज हैं। प्रदेश के दो मंत्रियों ने भी रेलवे और वित्त मंत्रालयों से मालगाड़ियों के निलंबन व जीएसटी बकाया की अदायगी न होने के मामले में चर्चा के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें भी मंत्रियों ने समय नहीं दिया। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में पहले की तरह बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए हमने नेशनल ग्रिड से बात की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। पंजाब को नेशनल ग्रिड का 10 हजार करोड़ रुपए देना है। मार्च से जीएसटी का पैसा भी नहीं मिला है। केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है।

भाजपा गठबंधन से इतर दलों के राज्य सरकारों की अलग राय

गौरतलब है कि जो 21 राज्य उधार लेने के लिए तैयार हैं, उन्होंने भी प्रथम विकल्प पर ही हामी भरी है। लेकिन भाजपा गठबंधन से इतर दलों की सरकारों के वित्त मंत्री उसके लिए भी तैयार नहीं हैं। समझना होगा कि वर्तमान में जब सभी प्रकार के राजस्व कम हो रहे हैं और केंद्र सरकार का राजस्व भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, तो ऐसे में केंद्र सरकार से यह उम्मीद करना कि राज्यों के राजस्व की क्षतिपूर्ति तुरंत हो सकेगी, सही नहीं होगा। वैसे भी राज्यों के जीएसटी के हिस्से की क्षतिपूर्ति पूर्व में भी सेस के माध्यम से ही होती रही है। ऐसे में चूंकि राज्यों के राजस्व की क्षतिपूर्ति हेतु लिए गए ऋणों के ब्याज और मूल दोनों की अदायगी उसी सेस से ही होनी है, तो राज्यों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती असहमति के बीच केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है, जिसके अनुसार राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपए के बिना ब्याज के 50 वर्षीय ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसका उपयोग वे अपने राज्यों में पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्पन्न परिस्थितियों का सभी को मिलकर सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को राजस्व की भरपाई का एक अच्छा विकल्प दिया है, जिसे कई राज्यों ने स्वीकार भी किया है। यह उम्मीद की जा सकती है कि सभी के लिए स्वीकार्य एक समाधान, शायद आने वाले दिनों में संभव हो सकेगा।

है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र और राज्यों की सरकारों को एक निश्चित सीमा की स्वतंत्रता का आश्वासन देने के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व और परस्पर-निर्भरता दिखाने पर जोर दिया है। पिछले काफी समय तक हमने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में भी काफी तनातनी देखी। बाद में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दोनों सरकारों के बीच सत्ता के टकराव पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। समय आ गया है जब केंद्र और राज्य, दोनों सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अपने-अपने दृष्टिकोणों का पुनर्निरीक्षण करें; ताकि संघीय मतभेदों से संवैधानिक संकट जैसी स्थिति न बन जाए।

केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति बनाते हुए उनके लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करते हुए जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के नाम से एक कर 2017 के जुलाई माह से लागू कर दिया गया। गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद इस कर से होने वाले संपूर्ण राजस्व के दो बराबर के हिस्से होते हैं। इसमें से एक हिस्सा केंद्र सरकार के पास आता है और दूसरा राज्यों के पास। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र के सभी करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित होता है। वर्तमान में यह हिस्सा 42 प्रतिशत है। यानी जीएसटी की कुल प्राप्तियों में से 71 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के पास जाता है। जिस समय जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी, राज्यों में यह चिंता व्याप्त थी कि नई प्रणाली में उनका राजस्व घट सकता है, इसलिए कई राज्य जीएसटी प्रणाली के लागू होने का विरोध कर रहे थे। ऐसे में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने **एक फार्मूला** लागू किया, जिसके अनुसार राज्यों को उनके उन करों से प्राप्त आमदनियों को न केवल जीएसटी में राज्यों के हिस्से में सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि उनमें हर वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि की भी गारंटी होगी। ऐसी व्यवस्था 5 वर्ष तक चलेगी।

केंद्र सरकार की यह अपेक्षा थी कि जीएसटी एक महत्वपूर्ण कर सुधार है और इससे न केवल कर एकत्रीकरण में कुशलता बढ़ेगी, बल्कि इससे करों की चोरी भी थमेगी और करों के कारण बिना वजह कीमत बढ़ने (कासकेडिंग इफेक्ट) जैसी स्थिति भी समाप्त होगी। इसका अभिप्राय यह होगा कि एक ओर कर राजस्व बढ़ेगा तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी इस व्यवस्था का लाभ होगा, क्योंकि इससे कीमतें भी कम होंगी। हालांकि जीएसटी को व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लगा, और जीएसटी से कुल प्राप्तियां घटती-बढ़ती रहीं।

जहां सरकार की यह अपेक्षा थी कि हर महीने जीएसटी से कुल प्राप्तियां कम से कम एक लाख करोड़ रुपए रहेंगी, दिसंबर 2019 तक के जीएसटी के 30 महीनों में से सिर्फ 9 महीनों में ही एक लाख करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की जीएसटी की प्राप्तियां हुई। इसका एक प्रमुख कारण देश में अपेक्षा से कम जीडीपी ग्रोथ था। स्वाभाविक तौर पर इसके कारण, खासतौर पर वर्ष 2019 में केंद्र सरकार पर अपने वचन के अनुसार राज्यों की भरपाई के कारण बोझ बढ़ गया।

गौरतलब है कि जीएसटी पर एक सेस लगाकर केंद्र सरकार ने राज्यों के नुकसान की भरपाई का निश्चय किया। वर्ष 2017-18 में यह भरपाई 41,146 करोड़ रुपए और 2018-19 में 69,275 करोड़ रुपए की रही। वर्ष 2019-20 में हालांकि जीएसटी की औसतन प्राप्तियां लगभग एक लाख करोड़ रुपए की रही, लेकिन राज्यों के राजस्व की भरपाई की अपेक्षा पिछले साल से भी ज्यादा हो गई। पिछले वर्ष का बकाया अभी बाकी था, कि नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले ही माह से जीएसटी की प्राप्तियां कोरोना महामारी के चलते नीचे जाने लगी। हम देखते हैं कि अप्रैल माह में जीएसटी की कुल प्राप्ति 32,172 करोड़ रुपए, मई माह में 62,152 करोड़ रुपए, जून में 90,917 करोड़ रुपए, जुलाई में 87,422 करोड़ रुपए और अगस्त माह में 86,449 करोड़ रुपए और सितंबर माह में 95,480 करोड़ रुपए रही। हालांकि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण जीएसटी राजस्व प्रभावित होने के बाद, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ-साथ राजस्व पुनः पटरी पर लौट रहा है, लेकिन राजस्व के नुकसान के बावजूद केंद्र के वचन के अनुसार राज्यों की भरपाई करना केंद्र का दायित्व बना हुआ है। चूंकि केंद्र के पास भी राजस्व घटा है, लिहाजा वह भी भरपाई करने में स्वयं को असमर्थ पा रही है। इन परिस्थितियों के संदर्भ में बीते माह ही जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न हुई, लेकिन इस हेतु मतैक्य के साथ समाधान नहीं हो सका। उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष में 2.35 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की कमी रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को यह सुझाव दिया है कि इस कमी को पूरा करने के लिए वे उधार लेना शुरू करें, लेकिन सभी राज्यों में इस बाबत सहमति नहीं बन पाई है।

● **इन्द्र कुमार**

कोविड-19 के दौरान हुए श्रमिकों के पलायन के कारण देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। कोरोना के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक गांवों में पहुंचे हैं। बेरोजगार हो चुके इन श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का दावा सरकार द्वारा किया गया। लेकिन मनरेगा की हकीकत सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ है कि देशभर में मनरेगा के तहत केवल 2 प्रतिशत लोगों को ही 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो पाया है।

केवल 2 फीसदी को 100 दिन काम

कोरोनाकाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना को काफी महत्व मिला। राज्य सरकारों ने दावा किया कि ग्रामीणों और गांवों में लौटे प्रवासियों को मनरेगा के तहत काफी काम दिया गया, लेकिन मनरेगा के अब तक आंकड़े बताते हैं कि साल 2020-21 में इस योजना के तहत बेशक 6.26 करोड़ परिवारों को काम दिया गया, लेकिन 100 दिन का काम 13,53,994 (2.16 प्रतिशत) परिवारों को ही मिल पाया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पोर्टल रुरल दीक्षा के मुताबिक, औसतन 199.12 रुपए प्रतिदिन दी गई। वहीं एक परिवार ने औसतन 38.24 दिन का काम दिया गया। यानी कि एक परिवार को अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक सात माह के दौरान औसतन केवल 7,000 रुपए ही मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनरेगा का यह पैसा ग्रामीणों और प्रवासियों के कितने काम आया होगा।

मनरेगा के लिए केंद्र की ओर से 26 अक्टूबर तक 68 हजार 298 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। हालांकि बजट लगभग 72,658 करोड़ रुपए का है। लेकिन जो रकम केंद्र जारी कर चुका है, उसमें से 91.55 प्रतिशत यानी 66,521 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें लगभग 48,212 करोड़ रुपए मजदूरी पर खर्च किए गए हैं। शेष 25.46 फीसदी राशि मटेरियल और स्किल्ड वेज पर खर्च की गई है और 2.76 फीसदी राशि प्रशासनिक खर्च है। इस तरह एक व्यक्ति पर 263.73 रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि प्रति व्यक्ति मजदूरी 199.12 रुपए दी गई है।

मनरेगा के तहत इस साल अब तक जो काम हुए हैं, उनमें सबसे अधिक कृषि एवं कृषि से जुड़े कार्यों पर खर्च किया गया है। इस मद में 71.41 प्रतिशत खर्च किया गया है। अब तक 1.29 लाख काम पूरे हो चुके हैं, जबकि 1.75 लाख काम चल रहे हैं। अब तक 17.50 करोड़ जॉब कार्ड जारी हो चुके हैं, लेकिन इनमें 8.90 करोड़ जॉब कार्ड एक्टिव हैं। एक्टिव वर्कर्स की संख्या 13.80 करोड़ है, हालांकि पिछले सात महीनों में 9 करोड़ 59 हजार वर्कर्स को ही काम दिया गया।

लॉकडाउन के बाद मनरेगा में काम मांगने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी और लगभग सभी राज्य सरकारों ने ग्रामीणों और प्रवासियों को मनरेगा का काम देने का दावा किया था। जून में सबसे अधिक काम की मांग की गई। इस महीने 4.47 करोड़ लोगों ने काम मांगा था, लेकिन इसके बाद **वर्क डिमांड** घटी और अक्टूबर में यह लगभग आधी रह गई। अक्टूबर में 2.28 करोड़ लोगों ने काम की मांग की।

वर्तमान लोकसभा सत्र में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण मनरेगा में इस वर्ष 22.49 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 38.79 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले वर्ष काम मांगने वालों की संख्या 16.2 करोड़ थी। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष 8.29 करोड़ लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया जा चुका है। केंद्र सरकार ने मनरेगा का इस वर्ष 2020-2021 का बजट 61,500 करोड़ बनाया था। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोनाकाल में जारी आर्थिक पैकेज में मनरेगा को 40 हजार करोड़ की अतिरिक्त मदद दी है। जिससे ये आंकड़ा एक लाख करोड़ के पार जा सका है।

कुछ राज्यों से तो 200 दिन के रोजगार की जोरशोर से मांग उठाई जा रही है। इसमे राजस्थान सबसे मुखर है। विभिन्न राज्य सरकारें ढोल पीट रही हैं कि उन्होंने मनरेगा कार्यों के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया है। ये बात सही है कि कोरोनाकाल के समय मनरेगा के

दावे और हकीकत में अंतर

विभिन्न राज्य सरकारों का दावा है कि मनरेगा ने सामाजिक न्याय व उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके जरिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े व गरीब लोगों के उत्थान में मदद मिली है। सुनने में तो ये दावा भी पहले वाले दावे जैसा ही लगता है। शायद उस दावे से ज्यादा गहराई को समेटे हुए है। जब इस दावे की पड़ताल करते हैं तो कुछ और ही दिखलाई पड़ता है। निसंदेह उत्थान तो हुआ है, किंतु किसका हुआ है? क्या पेंशनधारियों, सरकारी मुलाजिमो, हॉलसेल के कारोबारी और बड़े-बड़े खेतों के मालिकों को उत्थान की आवश्यकता है? सामाजिक न्याय व उत्थान के नाम पर चल तो यही रहा है। इस विषय को कुछ उदाहरणों के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के बूंदी जिले में पेंच की बावड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत मनरेगा का कार्य संपन्न हुआ है। इस पंचायत के अंतर्गत दलित, आदिवासी, घुमंतू, गुर्जर व ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। इस पंचायत में कलंदर-मदारी समुदाय के करीब 50 लोग रहते हैं। जो पहले बंदर-भालू का खेल तमाशा दिखाकर अपना घर-परिवार चलाते थे। इनके पास कोई जोतने की जमीन नहीं है और न ही कोई सरकारी नौकरी। इसमें मात्र तीन लोगों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया गया वो भी मात्र एक मस्ट रोल का (13 दिन के लिए)।

जरिए लोगों के हाथ में कुछ रुपया आ सका जिससे उनको कुछ सहूलियत मिली लेकिन ये कहना कि इससे सभी समस्याओं का समाधान हो गया है ये सही नहीं है। सवाल यहां ये है कि क्या केवल रुपए देना ही मनरेगा का उद्देश्य है? क्या समस्या मात्र इतनी ही थी? यदि ऐसा था तो फिर इसका सबसे सरल और भरोसेमंद तरीका तो कैश ट्रांसफर है। किंतु सरकार ने ऐसा तो नहीं किया। उसने तो रुपए सीधे ट्रांसफर नहीं किए।

मतलब समस्या कुछ और थी, दावा कुछ ओर है। विभिन्न राज्य सरकारों का दावा है कि उन्होंने मनरेगा कार्यों के जरिए न केवल लोगों को रोजगार दिया बल्कि ग्रामीण जीवन का उत्थान किया है। इसके साथ महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, पारिस्थितिकी प्रबंधन, अवसंरचना विकास और कौशल निर्माण के जरिए मानव संसाधन का प्रबंधन किया है। दूसरी तरफ पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकताओं, लोक संस्कृति के संरक्षकों और **नीति निर्माताओं** के एक धड़े का कहना है कि मनरेगा ने समाज में इतने गड्ढे कर दिए हैं जिनको भरने में हमारी न जाने कितनी पीढियां खप जाएंगी। मनरेगा ने हमारी पारिस्थितिकी, लोक कला एवं संस्कृति, सामूहिकता के दर्शन को समाप्त किया है और भ्रष्टाचार के नए-नए रूपों को हमारे आचरण का हिस्सा बनाया है।

हम राज्य सरकारों के एक-एक दावे की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये दावे किस हद तक सही हैं? क्या वाक्य में ही मनरेगा ने ग्रामीण जीवन को बदला है? क्या मनरेगा ने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के सपने को बल दिया है? क्या मनरेगा ने पारिस्थितिकी प्रबंधन और मानव संसाधन का विकास किया है?

मनरेगा के जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार उप्र ने 78 लाख परिवारों के 95 लाख व्यक्तियों को मनरेगा में कार्य दिया है। राजस्थान सरकार का दावा है कि कोरोना के दौरान उन्होंने 64.8 लाख परिवारों के 89.91 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया है। गुजरात सरकार की रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने 9.43 लाख परिवार के 16 लाख लोगों को रोजगार दिया है जबकि हरियाणा सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 3.25 लाख परिवारों के 4.59 लाख व्यक्तियों को काम दिया है।

मनरेगा का जहां पर कार्य चलता है उसे मनरेगा साइट कहा जाता है। एक मनरेगा साइट पर करीब 60-70 या 80 लोग काम करते हैं। इन लोगों को मनरेगा श्रमिक कहा जाता है। प्रत्येक 40 मनरेगा श्रमिक पर एक मनरेगा 'मेट' नियुक्त किया जाता है। मनरेगा मेट का काम मनरेगा साइट पर छायां और पीने के पानी की व्यवस्था देखना, सभी मजदूरों को दिए गए कार्य का बराबर बंटवारा करना, जोहड़-तालाब की छंटाई करनी है तो सभी मनरेगा श्रमिकों को बराबर गड्ढे नांपकर देना और मस्ट रोल (मनरेगा कार्य की पुस्तक) में उनकी हाजिरी लगाना है।

मनरेगा मेट बनने के लिए यदि कोई महिला दलित या आदिवासी है तो उसे पांचवीं पास, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग की महिला को आठवीं पास होना अनिवार्य है जबकि पुरुष के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। राजस्थान सरकार के आंकड़ों के अनुसार 89.91 लाख लोगों ने मनरेगा में कार्य किया। हमें ये पता है कि 40 लोगों पर एक मनरेगा मेट नियुक्त होता है। इस लिहाज से अकेले राजस्थान में करीब 2.20 लाख मेट नियुक्त हुए। उप्र के जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 95 लाख लोगों ने मनरेगा श्रमिक के रूप में कार्य किया। इस लिहाज से वहां करीब 2.37 लाख मनरेगा मेट बने। गुजरात सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वहां 16 लाख मजदूरों में करीब 40 हजार मेट बने और हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार 4.59 लाख मनरेगा मजदूरों में करीब 11 हजार मेट नियुक्त हुए।

सरकारों ने कहा कि मनरेगा से महिला सशक्तिकरण हुआ है किंतु किसी भी राज्य सरकार ने अपने आंकड़ों में ये नहीं बताया कि आखिर उनके यहां कितनी महिलाओं को मनरेगा मेट के रूप में कार्य करने दिया? राजस्थान सरकार ये नहीं बताती की उसके यहां 2.20 लाख मनरेगा मेट में कितनी महिलाएं मेट बन सकीं? क्या 30 फीसदी महिलाओं को भी मेट बनाया गया? 30 फीसदी छोड़िए। क्या 10 फीसदी महिलाओं को भी मनरेगा मेट के रूप में नियुक्त किया गया? उप्र में नियुक्त 2.30 लाख मनरेगा मेट में कितनी महिलाओं को मेट की भूमिका दी? क्या 10 हजार महिलाओं को भी मेट बनाया? ऐसे ही गुजरात और हरियाणा में 40 हजार और 11 हजार मेट में कितनी महिलाओं को मेट की भूमिका मिली?

यहां एक बात ध्यान रखने की है। हम महिला को महिला ही मान रहे हैं। उसे दलित, आदिवासी या अन्य पिछड़े वर्ग में नहीं जोड़ रहे हैं। यदि दलित महिला, आदिवासी महिला, अन्य पिछड़े वर्ग की महिला के मनरेगा मेट के रूप में भूमिका को देखना हो तो शायद ये आंकड़ा महज 2-4 महिलाओं तक सीमित होकर रह जाए। राजस्थान समग्र सेवा संघ के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गोस्वामी इस विषय पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि हम महिला को क्या मानते हैं? जो महिला चिलचिलाती धूप में मनरेगा में गड्ढे खोद सकती है। दिसंबर और जनवरी के महीनों में खेत में पानी दे सकती है। क्या वो महिला गड्ढे नापकर नहीं दे सकती? जो महिला घर-परिवार, पशुधन और खेत-खलिहान को संभाल सकती है। क्या वो मनरेगा साइट पर पानी और छायां की व्यवस्था नहीं कर सकती?

● दिल्ली से रेणु आगाल

महिला सशक्तिकरण के दावे खोखले साबित हुए

सरकारों ने कहा कि मनरेगा से महिला सशक्तिकरण हुआ है किंतु किसी भी राज्य सरकार ने अपने आंकड़ों में ये नहीं बताया कि आखिर उनके यहां कितनी महिलाओं को मनरेगा मेट के रूप में कार्य करने दिया? सरकारों ने ये तो कहा कि महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मनरेगा में कार्य किया है। लेकिन वे ये नहीं बताते की उस कंधे से कंधा मिलाने में क्या मजदूर ही बनाकर रखा या मेट के रूप में नेतृत्व करने का मौका भी दिया? राजस्थान में आदिवासियों के जीवन को संहिताबद्ध करने में लगी फोटोग्राफर और कार्टूनिस्ट अंजली का कहना है कि हमने बहुत बड़ा मौका गवां दिया। मनरेगा मेट वो कड़ी है जहां महिला को नेतृत्व करने का मौका दिया जा सकता था। उसके साहस को उभारा जा सकता था। इससे समाज में सहज तरीके से उसकी भूमिका में बदलाव आता।

जेसीसी का भविष्य खतरे में

एक ओर जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का परिवार अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर उसके नेतृत्व वाली प्रदेश की एकमात्र मान्यता प्राप्त रीजनल पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसी) का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पार्टी के चार में से दो विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में वापसी की इच्छा जाहिर की है जिसका कांग्रेस ने स्वागत किया है। मरवाही के पूर्व विधायक अजीत जोगी की मौत और उनके परिवार के सदस्यों का जाति के आधार पर उपचुनाव लड़ने से वंचित होने के बाद जेसीसी के विधायकों का कहना है कि पार्टी का भविष्य अब खतरे में है। पार्टी के दो विधायकों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस में वापसी की कवायद शुरू कर दी है। विधायकों ने कहा है कि अजीत जोगी भी जीवित रहते हुए पार्टी का कांग्रेस में विलय करना चाहते थे लेकिन 29 मई 2020 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण यह नहीं हो पाया। जेसीसी के खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने बताया है कि कांग्रेस उनके खून में है और उनका भविष्य वहीं है। उनका पूरा परिवार हमेशा कांग्रेस की विचारधारा का रहा है और 2016 में जेसीसी के गठन से पहले वह तीन बार कांग्रेस के विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। सिंह के अनुसार उनके सहयोगी और जेसीसी के दूसरे विधायक प्रमोद शर्मा भी उनसे पूरी तरह सहमत हैं।

अजीत जोगी की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में उनकी पत्नी डॉ. रेणु जोगी, धर्मजीत सिंह, देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा सहित जेसीसी के चार विधायक हैं। देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा का मानना है कि पार्टी का दमखम अजीत जोगी से था। उनके बाद जेसीसी का वजूद खतरे में पड़ गया है। देवव्रत सिंह ने बताया, 'मेरा कांग्रेस के प्रति झुकाव स्वाभाविक है। हमने हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह ही काम किया है। अजीत जोगी के नेतृत्व में प्रदेश में एक मजबूत **तीसरा विकल्प** खड़ा करने की कोशिश की गई थी लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। जोगी के जाने बाद ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पार्टी को नेतृत्व दे सके। इससे पार्टी के भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है।' लेकिन सिंह का यह भी कहना है कि वे और प्रमोद शर्मा अभी संवैधानिक रूप से जेसीसी के साथ ही हैं क्योंकि 'कांग्रेस में प्रवेश के लिए उन्हें कम से कम तीन विधायक चाहिए और वे ऐसे पार्टी नहीं छोड़ना चाहते। इसके अलावा अंतिम निर्णय कांग्रेस को करना है।'

देवव्रत सिंह के वक्तव्य का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, 'देवव्रत सिंह पुराने कांग्रेसी हैं और उनकी घर वापसी पार्टी के लिए ठीक होगी लेकिन इस मामले में अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। मरकाम के अनुसार प्रदेश में जेसीसी का भविष्य संकट में है। पार्टी का नेतृत्व जनता को गुमराह कर रहा है। जेसीसी नेताओं का कहना है कि दिवंगत अजीत जोगी भी कांग्रेस में वापस लौटना चाहते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद एआईसीसी के बड़े नेताओं के साथ कई बार बातचीत हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई। देवव्रत सिंह के अनुसार, 'यह सच्चाई है कि अजीत जोगी कांग्रेस में वापस जाना चाहते थे जिसके लिए वे डेढ़-दो सालों से प्रयासरत थे। उन्होंने मुझे कई बार कहा कि तीसरी पार्टी चलाना मुश्किल है जिस पर मेरा सुझाव था कि हमें कांग्रेस में वापस चले जाना चाहिए। इस पर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। 2018 में अहमद पटेल समेत कुछ और नेताओं के साथ इस मुद्दे पर एक बैठक भी हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई।'

जेसीसी विधायक के अनुसार 2019 लोकसभा चुनाव के पहले अजीत जोगी ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को सुझाव दिया था कि वे पार्टी के लिए मरवाही की विधायकी छोड़कर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लेंगे लेकिन कांग्रेस नेतृत्व नहीं माना। बल्कि कांग्रेस ने जोगी को अपने उम्मीदवारों को समर्थन देने को कहा।

जेसीसी के एक नेता का कहना है कि 19 अप्रैल 2020 को जोगी को दिल का दौरा पड़ने के बाद रेणु जोगी और उनके बेटे अमित जोगी ने राहुल गांधी, सोनिया और अन्य नेताओं से आग्रह किया था कि उनके कोमा में रहते हुए जेसीसी का पार्टी में विलय हो जाए। इस नेता के अनुसार, 'कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए राजी भी हो गया था कि अजीत जोगी को कोमा की स्थिति में ही सत्तारूढ़ दल में शामिल कर लिया जाए और मृत्यु होने पर उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के झंडे में लेकर जाया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि विधानसभा सचिव और विधि विशेषज्ञों की राय इसके विपरीत थी। जोगी के कोमा में होने की वजह से यह कार्रवाई संभव नहीं हो सकती थी।'

● **रायपुर से टीपी सिंह**

अवसरवादी नेता ही पार्टी बदलेंगे

जेसीसी अध्यक्ष अमित जोगी का कहना है कि पार्टी विधायक देवव्रत सिंह न तो कांग्रेसी हैं और न ही जनता कांग्रेसी, वे सिर्फ अवसरवादी हैं। जो पार्टी मेरे स्वर्गीय पिता के निधन के बाद भी उनका लगातार अपमान कर रही है, उस पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। बतौर जोगी, 'ऐसा कुछ लोग उपचुनाव के ठीक पहले अचानक क्यों कह रहे हैं, यह तो वो ही बता पाएंगे। मैं उनको जोगी जी की आत्मकथा पढ़ने की सलाह जरूर दूंगा। उनकी सारी गलतफहमी मिनटों में दूर हो जाएगी। जिनको कांग्रेस में प्रवेश करने का शौक है, वे पंजा छाप से उपचुनाव लड़ें। उनका जवाब जेसीसी बखूबी देना जानती है। अपनी जमानत बचा पाएं तो अजूबा होगा। मुख्यमंत्री भूपेश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।' पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से मुलाकात को लेकर चर्चा का विषय बन चुके जेसीसी विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस में जाने से साफ इनकार कर दिया है। देवव्रत सिंह के वक्तव्य पर बोलते हुए धर्मजीत ने कहा है कि, 'जिसको जहां जाना है वे जा सकते हैं लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है। वे तीन विधायक साथ लेकर जा सकते हैं।' डॉ. रमन सिंह से बंद कमरे में तकरीबन एक घंटे तक हुई मुलाकात को लेकर धर्मजीत सिंह ने कहा, 'अभी हमारा एकमात्र लक्ष्य स्वर्गीय अजीत जोगी और उनके परिवार को अपमानित करने वालों के खिलाफ न्याय दिलाना है और इसके लिए मुझे जिससे मिलना पड़ेगा, उससे मिलूंगा। हमारे दल अलग हैं लेकिन इस मुद्दे को लेकर हमारे दिल अलग नहीं हैं।'

गुर्जर आंदोलन धुआं-धुआं

राजनीति के चौबीसों घंटे के खिलाड़ी

अशोक गहलोत को पहचानने वाले जानते हैं कि गहलोत राजनीति के चौबीसों घंटे के खिलाड़ी हैं जो हर वक्त शतरंज खेलते हैं और सबसे अच्छी उनकी चाल घोड़े की होती है। वह हमेशा ढाई घर की चाल चलते हैं। दो घर आगे बढ़ते हैं तो एक घर पीछे भी हटते हैं और यहीं से उनकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे में सचिन पायलट अगर कोई उम्मीद पाले बैठे हैं कि राज्य की राजनीति में अशोक गहलोत के रहते नंबर एक की हैसियत पा लेंगे तो सचिन पायलट को किसी करिश्मे से उम्मीद करनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि इस आंदोलन के माध्यम से किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को एक गुर्जर नेता के रूप में स्थापित किया जा रहा है। दरअसल सचिन पायलट के समानांतर एक और गुर्जर नेता अशोक गहलोत खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट के लिए राह आसान नहीं है।

आखिरकार राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन 12वें दिन खत्म हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर सहमति बन गई है। सब कमेटी और गुर्जर संघर्ष समिति के बीच वार्ता में 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है। 5 मांगों पर गुर्जर समाज ने सहमति दी। मारे गए 3 आंदोलनकारी के परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी, आंदोलन में लगे मुकदमों को सरकार वापस लेगी, नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी गहलोत सरकार। अब सवाल उठता है कि क्या गुर्जर आंदोलन राजनीति के चतुर सुजान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक है? इस बार गुर्जर आंदोलन जिस दिन से शुरू हुआ है उसी दिन से इस बात को लेकर आम लोगों में चर्चा है कि क्या इस गुर्जर आंदोलन के जरिए अशोक गहलोत एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। निशाना भी ऐसा साध रहे हैं कि जिसे लगे उसका जख्म भी न दिखे। कहा जा रहा है कि इस बार राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की सियासी आग लगी है जिसमें धुआं ही धुआं है।

गौरतलब है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही हाशिए पर जा चुके गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के लिए भी आंदोलन महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस बार के आंदोलन में अपने पुत्र विजय बैंसला को लॉन्च किया। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में भी बैंसला ने आंदोलन के माध्यम से सरकार को अपनी ताकत का अहसास कराया था। जिस बैंसला को लोग चुका हुआ गुर्जर नेता मान चुके थे, वो बैंसला तीन से चार हजार गुर्जरों की भीड़ के साथ सवाई माधोपुर के पास **मलारना रेलवे स्टेशन** पर पटरी पर बैठ गए थे। एक छोटी सी भीड़ को रेलवे ट्रैक पर बैठते हुए बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मी देखते रह गए। बैंसला ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक होगा। अगर हिंसा हुई तो वह आंदोलन को छोड़कर उठ जाएंगे। उस आंदोलन के बाद उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस साल 1 नवंबर से आंदोलन शुरू कर दिया था।

राजस्थान में चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त हो गया है। सरकार द्वारा आंदोलनकारियों की सभी मांगें मान लिए जाने के बाद 12वें दिन आंदोलनकारी दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक से हट गए हैं। वहीं आंदोलन के कारण करौली-हिंडौन सड़क मार्ग पर लगाया गया जाम भी हटा लिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं भी बहाल करवा दी हैं। आंदोलनकारियों के पटरियों से हट जाने के कारण विगत 11 दिनों से बाधित हो रहा दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक अब बहाल हो गया है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की समाप्ति के बाद करौली-हिंडौन मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। करौली से महुआ, मंडावर, अलवर, जयपुर, भरतपुर और दिल्ली सहित अन्य मार्गों पर भी रोडवेज का संचालन शुरू कर दिया गया है। करौली रोडवेज यातायात प्रभारी शिवदयाल शर्मा ने बताया कि सरकार से गुर्जर समाज के हुए समझौते के बाद बस सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। आंदोनलनकारियों ने करौली-हिंडौन सड़क मार्ग पर गुड़ला गांव में लगाया गया जाम हटा दिया है। यहां सड़क पर सूखा पेड़ डालकर जाम लगाया हुआ था। लेकिन इसके बाद गुर्जर आंदोलन नहीं करेंगे, यह सुनिश्चित नहीं हैं। हालांकि इस बार आंदोलन पहले की अपेक्षा कमजोर रहा।

गुर्जर आंदोलन पूरे राजस्थान में इस बार पहले की तरह दिखना तो छोड़िए पिछले गुर्जर आंदोलन की छाया की तरह भी नहीं दिखा। राजस्थान सरकार इस तरह से आचरण कर रही थी जैसे पूरे राजस्थान में गुर्जर सड़कों पर हैं और वह पूरी तरह से चिंतित हैं। बैंसला पहले दिन से संकेत देते रहे कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से काफी उम्मीदें हैं लेकिन सियासत के जानकार कहते हैं गुर्जर आंदोलन से बैंसला को कोई उम्मीद हो या ना हो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच के वोट का अंतर देखें तो कांग्रेस को भाजपा से महज 1 लाख 42 हजार वोट ज्यादा मिले हैं। और माना जा रहा है कि जिस तरह से गुर्जरों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट किए हैं इस 1 लाख 42 हजार में से 80 फीसदी गुर्जर वोट हैं, जबकि 20 फीसदी मुस्लिम वोट हैं। भाजपा का एक भी गुर्जर विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचा है। दरअसल गुर्जर समझ रहे थे कि इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री गुर्जर का बेटा सचिन पायलट बनेगा। मगर यह हो न सका और राजस्थान की कमान राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत के हाथों में चली गई। सचिन पायलट देखते ही रह गए।

अशोक गहलोत राहुल गांधी के बगल से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के पिटारे से मुख्यमंत्री का पद दिल्ली से निकाल लाए। सांत्वना में सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया। सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन अशोक गहलोत को जानने वाला जानते हैं कि गहलोत का काटा पानी नहीं मांगता है। यह पूरे देश में देखा भी की किस तरह उन्होंने सचिन पायलट को कमजोर कर दिया है। ऐसे में इस बार के गुर्जर आंदोलन में सरकार की पूरी कोशिश यह रही कि आंदोलन विकराल रूप धारण न करे। इसलिए सरकार लगातार इस कोशिश में लगी रही कि आंदोलनकारियों से किसी भी तरह वार्ता कर आंदोलन को खत्म कराया जाए।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

नाराजगी के सुर तेज

2014 तक भाजपा की महाराष्ट्र इकाई पर काफी हद तक दो गुटों का नियंत्रण था- एक का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे करते थे और दूसरे का नितिन गडकरी। वर्चस्व की जद्दोजहद में अक्सर दोनों खेमों में टकराव भी होता रहता था। हालांकि, 2014 के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई क्योंकि उसी वर्ष मुंडे का निधन हो गया और गडकरी केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र में चले गए। यही वह वर्ष भी था जब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, इसके साथ ही 'फडणवीस कैंप' के तौर पर पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के भीतर एक नए नेतृत्व के बीज पड़े। इसे भाजपा के 'मोदी-शाह' वाले केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद हासिल था।

6 साल बाद मुंडे और गडकरी दोनों खेमे कमजोर पड़ चुके हैं और पार्टी में मोटे तौर पर दो खेमों के बीच एक हल्की रेखा खिंच चुकी है, एक वे जो 'फडणवीस खेमे' में हैं और दूसरे जो इसमें नहीं हैं, दूसरे वाले खेमे में ज्यादातर पार्टी के बुजुर्ग नेता शामिल हैं। मुंडे और गडकरी शिविरों के बीच टकराव के विपरीत इन दो नए गुटों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद नहीं हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे लेकर नाराजगी के सुर तेज हो जाते हैं- हाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे का इस्तीफा एक ऐसी ही घटना है। 2016 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एक सशक्त राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए खडसे ने भाजपा छोड़ने के लिए पूरी तौर पर फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, फडणवीस के खिलाफ कोई खुली बगावत नहीं हुई है लेकिन पार्टी के ऐसे वरिष्ठ **नेताओं के बीच असंतोष** की सुगबुगाहट तेज हो गई है जिनकी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए फडणवीस को आगे बढ़ाया गया था। राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने वालों का कहना है कि फडणवीस ने 2014 में मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभालने के बाद ही सुव्यवस्थित तरीके से अपने लिए चुनौती बनने वाले वरिष्ठ पार्टी नेताओं के पर कतरने शुरू कर दिए थे। मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखने वाले खडसे इसी का उदाहरण हैं। पिछले सप्ताह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल होने वाले इस नेता को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था।

राजनीतिक विश्लेषक हेमंत देसाई कहते हैं, 'जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने (फडणवीस) अपनी पार्टी या शिवसेना के मंत्रियों को कोई अधिकार दिए बिना हर बड़ा फैसला खुद ही लिया। यह मोदी मॉडल था, जिसमें औद्योगिक नीति से लेकर कृषि और कर्जमाफी तक की नीतियां शामिल थीं। विनोद तावड़े के पर तब कतरे गए जब उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू किए कि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख नेता रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन हासिल है। सुधीर मुंगंटीवार को भी दरकिनार किया गया।' पूर्व मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां खडसे से इस्तीफा देने के लिए कहा था, वहीं उन्होंने तावड़े और गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे जैसे मंत्रियों से कुछ विभाग छीन लिए थे। तावड़े और चंद्रशेखर बावनकुले जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी दरकिनार किया गया क्योंकि उन्हें 2019 के विधानसभा चुनावों के लिए टिकट नहीं मिला था। मुख्यमंत्री पद संभालने वाले राज्य के पहले पार्टी अध्यक्ष बने फडणवीस ने उसी समय गिरीश महाजन, पूर्व एनसीपी नेता प्रसाद लाड और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण दारेकर और राम कदम जैसे विश्वासपात्रों की अपनी टीम बनाई। केवल राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल, जो खडसे के इस्तीफे के बाद तत्कालीन सरकार के मंत्रिमंडल में फडणवीस के बाद नंबर-2 की हैसियत रखते थे, ही अपनी जमीन बचाने में सफल रहे। पाटिल को अमित शाह का करीबी माना जाता है।

जब खडसे ने भाजपा छोड़ी तो गडकरी के करीबी रहे मुंगंटीवार ने बताया, 'वह (खडसे) एक कद्दावर नेता थे, जिन्होंने दशकों तक पार्टी के लिए काम किया और महाराष्ट्र में पार्टी को आगे बढ़ाने में **अहम जिम्मेदारी निभाई।** अगर ऐसे किसी नेता को इस तरह की परेशानी हो रही हो कि वह इसे छोड़ने की हद तक चला जाए तो जरूर कुछ गंभीर मसला है जिसके बारे में पार्टी को निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है।' उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के बाद से महाराष्ट्र भाजपा की चिंतन बैठक यानी राज्य के वरिष्ठ नेताओं के बीच होने वाला मंथन भी पूरी तरह बंद हो गया है। पंकजा मुंडे के करीबी एक भाजपा पदाधिकारी ने कहा, 'बीड में भाजपा कार्यकर्ता और जिला नेतृत्व पंकजा ताई को दरकिनार किए जाने से नाराज थे। वह राज्य विधान परिषद में जगह मिलने की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसने पार्टी के अंदर उनके समर्थकों को नाराज कर दिया, लेकिन जबसे केंद्रीय नेतृत्व की टीम में उन्हें जगह मिली सबकुछ ठीक हो गया है।

● **बिन्दु माथुर**

मोदी-शाह का आशीर्वाद

अपना नाम न बताने की शर्त पर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'पिछले शासनकाल में राज्य में मुंडे, प्रमोद महाजन और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के साथ निर्णय लेने का तरीका ज्यादा लोकतांत्रिक था। अगर सोशल इंजीनियरिंग की गणना के कारण कोई सीट किसी को दी जानी थी, और वहां एक और मजबूत विश्वस्त पार्टी नेता है तो उस नेता को कहीं और समायोजित किया जाता था। उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें या तो राज्य विधान परिषद या राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया जाता था। अब ये निर्णय इस आधार पर भी किए जाते हैं कि कौन नेतृत्व की विचारधारा का प्रतिनिधित्व बेहतर ढंग से कर सकता है।' हालांकि, नेता ने ऐसे संकेत भी दिए कि फडणवीस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लिए निर्णयों को लागू करने के लिए सिर्फ एक चेहरा भर थे। नेता ने कहा, 'इससे पहले कोई फैसला लेने में राज्य की भागीदारी 70 प्रतिशत और केंद्र की 30 प्रतिशत होती थी। अब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पहले से ही जानता है कि पार्टी में क्या चल रहा है। यह राज्य में किसी विशेष शिविर की बात ही नहीं है। नाम न बताने के इच्छुक मुंबई के एक भाजपा पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के संबंध में भाजपा के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी के बारे में बात न करने का अलिखित आदेश दे रखा है।

कमजोर विपक्ष

राजनीतिक सत्ता के लिहाज से देश के सबसे अहम राज्य उप्र में न राजनीतिक तौर पर संवेदनशील घटनाओं की कमी है, न कई मोर्चों पर राज्य सरकार की कमजोरियों का टोटा है, फिर भी विपक्ष की आवाज मंथर और बुरी तरह बंटी हुई लगती है। जब सुर्खियां चीखने लगती हैं, तब विपक्ष की जो सक्रियता दिखती भी है, उसमें मोटे तौर पर उन्हीं किरदारों की आवाज ऊंची गूंजती है, जो राज्य की सियासत में बहुद हद तक हाशिए पर हैं। कांग्रेस, रालोद, कुछ छोटी पार्टियां लगातार राज्य सरकार पर दबाव बनाती दिख रही हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी तो दिवाली बाद लखनऊ को अपना ठिकाना बनाकर राज्य में संगठन में जान फूंकने की योजना बना चुकी हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के लिए लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय को सजाया-संवारा जा रहा है। लेकिन राज्य में विपक्ष के दोनों बड़े दावेदार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बसपा कमोवेश मैदान में गैर-मौजूद हैं। हालांकि उनके बीच सियासी खींचतान जोरों पर है।

लखनऊ में 29 अक्टूबर को ऐसी गहमागहमी मची कि सपा और बसपा का द्वंद्व खुलकर सामने आ गया। अचानक बसपा के 6 विधायक सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले और उनमें 4 ने बसपा के राज्यसभा उम्मीदवार रामजी गौतम के खिलाफ हलफनामा दिया कि उनके आवेदन पर उनके दस्तखत फर्जी हैं। 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव 9 नवंबर को होने हैं। इससे नाराज होकर मायावती ने **प्रेस कॉन्फ्रेंस** करके कहा, सपा को हराने के लिए भाजपा को भी वोट देना पड़ा तो उनकी पार्टी देगी। मायावती ने यह कहकर आगे सपा से किसी तरह के तालमेल की संभावनाओं को खत्म कर दिया कि 1995 में गेस्टहाउस कांड का मुकदमा वापस लेना गलती थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा-बसपा गठबंधन के दौरान ये मुकदमे वापस ले लिए गए थे।

इस जोड़-तोड़ के अलावा दोनों पार्टियों की जनता के मुद्दों पर गैर-मौजूदगी चकित करती रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हाथरस में 19 वर्षीय दलित बच्ची के साथ गैंगरेप और बेतरह मारपीट की हैरतनाक घटना थी, जिसमें वह बच्ची लगभग दो हफ्ते बाद दम तोड़ बैठी। जब मामला उछला, चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाद में राष्ट्रीय लोकदल ने ही अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। सपा थोड़ी-बहुत सक्रिय दिखी भी, लेकिन बसपा ने तो महज ट्विटर बयानबाजी से ही काम चलाया। सपा और बसपा ही राज्य में विपक्ष की मुख्य दावेदार हैं।

प्रियंका गांधी सबसे अधिक सक्रिय

उप्र में सबसे अधिक सक्रिय कांग्रेस दिख रही है। प्रियंका गांधी भले 2019 में प्रदेश की प्रभारी महासचिव बनाए जाने के बाद लोकसभा चुनावों में खास असर न दिखा पाई हों, लेकिन वे लगातार सक्रिय रही हैं। उन्होंने सोनभद्र के उभा गांव में आदिवासियों पर गोलीकांड, उन्नाव में बलात्कार की वारदात, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों, लॉकडाउन में मजदूरों की गांव-घर वापसी, हाथरस कांड सबमें जोरदार सक्रियता दिखाई है। इस तरह उन्होंने और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक जुझारू नेता की अपनी छवि बनाई है। इसी सक्रियता और जूझारूपन के बूते कांग्रेस की योजना राज्य में संगठन खड़ा करने की है। पार्टी के सूत्रों की मानें तो इसका पार्टी और प्रियंका को अच्छा-खासा लाभ भी मिला है। राज्य पार्टी में सक्रिय एक नेता के मुताबिक, हर जिले में ब्लॉक स्तर पर पार्टी का ढांचा तैयार किया जा रहा है। सूत्रों का दावा तो यह भी है कि पार्टी ने इस दौरान 74 लाख लोगों से पुख्ता संपर्क स्थापित किया है और उनमें अनेक पार्टी के लिए सक्रियता से काम करने लगे हैं। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि प्रियंका प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के तकरीबन 5,000 कार्यकर्ताओं के निरंतर संपर्क में हैं, जो उनसे सीधे बात कर सकते हैं और सूचनाएं मुहैया कराते हैं। यह देखना बाकी है कि उनकी कोशिशों से कांग्रेस में कितनी जान लौटती है। उप्र में विपक्ष की यही सबसे बड़ी पहेली है।

सपा के धर्मेंद्र यादव जरूर पहले हाथरस में और फिर लाठीचार्ज के बाद रालोद के नेता जयंत चौधरी की मुजफ्फरनगर, मथुरा, बागपत की महापंचायतों में शिरकत करते दिखे, मगर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्विटर पर ही सक्रियता दिखाई। बसपा की मायावती ने तो ट्विटर और सामान्य बयानों में भी कंजूसी बरती। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि विपक्ष के बड़े किरदार क्यों मैदान में उतरने से परहेज कर रहे हैं। क्या यह लोकसभा चुनावों में हार का सदमा है, जिससे वे अभी तक उबर नहीं पाए हैं? या फिर नई मोर्चेबंदी के लिए दोनों एक-दूसरे की जमीन खंगालने की कवायद में मशगूल हैं?

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य में 2022 के विधानसभा चुनावों में सवा साल से भी कम वक्त बचा है। फिलहाल 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी हो रहे हैं और इसी दौरान राज्यसभा चुनाव की भेरी भी बज चुकी है। हालांकि अखिलेश यादव लंबे समय बाद राज्यसभा चुनाव के लिए अपने चाचा रामगोपाल वर्मा का पर्चा दाखिल करने के दौरान जरूर दिखे। राज्यसभा की 10 सीटों में भाजपा 8 और सपा का एक सीट जीतना विधायकों की संख्या के बल पर जीतना तय है। बसपा के उम्मीदवार के चलते भाजपा के नौवें उम्मीदवार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, लेकिन अब **खेल उलटा** होता दिख रहा है।

सवाल यह भी है कि मायावती अगर बिहार में तीसरे मोर्चे के साथ मैदान में उतरी हैं और पहले चरण के मतदान के पहले मतदाताओं के लिए अपील भी जारी कर रही हैं, तो अपनी मजबूती वाले राज्य में उनकी पार्टी दलित बच्चियों के साथ उत्पीड़न की लगातार घटनाओं पर क्यों नहीं मैदान में उतर रही है? कुछ लोग इसकी वजह केंद्र की जांच एजेंसियों का दबाव बताते हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि बसपा का जाटवों में असर है, इसलिए बाकी दलित जातियों पर अत्याचार के मामलों में उसकी सक्रियता उतनी नहीं दिखती है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

मोदी ने बचाई लाज

बिहार के चुनावी परिणाम हर किसी के लिए बेहद चौंकाने वाले रहे। महागठबंधन को अपनी हार पर विश्वास नहीं हो रहा और न ही कांग्रेस अपनी हार पचा पा रही है। वहीं चुनावों में नीतीश कुमार के लिए जनता की नाराजगी खुलकर दिखी। लॉकडाउन में नीतीश सरकार के कुशासन का सीधा प्रभाव जदयू पर पड़ा। पिछले चुनावों में प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी बनी जदयू खिसककर तीसरे नंबर पर आ गई और केवल 43 सीटों पर सिमट गई। इसका पूरा श्रेय जाता है लोजपा के चिराग पासवान को, जिन्होंने जदयू को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लोजपा के एनडीए से अलग होने के बाद लोजपा ने करीब-करीब हर जदयू के सामने चुनावी प्रत्याशी उतारा जिसने जदयू के वोट काटे। इससे नीतीश की पार्टी कमजोर हुई लेकिन अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में पार्टी की लाज बची।

बिहार चुनावों में चिराग पासवान को एनडीए का विभीषण बताया जा रहा है। यही वजह रही कि जदयू ने चिराग को वोटकटवा तक कह दिया। चिराग चुनावों से पहले ही नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। उन्होंने नीतीश कुमार को जेल तक भेजने की धमकी दे दी थी। चिराग के उम्मीदवारों ने हर जगह जदयू प्रत्याशियों के वोट काटे। इससे जदयू कमजोर हुई और पिछले चुनावों में 71 सीटे जीतने वाली जदयू इस बार केवल 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहां इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि चिराग खुद जीते नहीं लेकिन जदयू को कई जगहों पर हरवा दिया। लोजपा केवल एक सीट पर कब्जा कर पाई। बिहार में चुनाव शुरू होने से पहले ही खासतौर पर मजदूरों और युवाओं में नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी देखने को मिली। प्रदेश में लगातार नए ब्रिज टूटने, प्रवासी मजदूर, रोजगार आदि मुद्दों पर जनता में नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी थी। 10 लाख रोजगार का वादा कर महागठबंधन ने इस हवा को अपने पक्ष में बहाने की कोशिश की। यही वजह रही कि बिहार के एक तबके में तेजस्वी की लहर बह रही थी। इस लहर में बहकर राजद 75 सीटों पर कब्जा करके प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनने में सफल हुई लेकिन कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन ने महागठबंधन को सत्ता के दरवाजे से दूर रखा।

पिछले चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़कर 27 सीटे जीतने वाली कांग्रेस ने इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन कब्जा जमाया केवल 19 सीटों पर। इतने लचर प्रदर्शन की उम्मीद तो खुद कांग्रेस और राहुल गांधी तक को नहीं दी। इतना जरूर है कि कई सीटों पर कांग्रेस और विजेता पार्टी के बीच अंतर 500 वोटों से कम रहा लेकिन हार तो हार है। कांग्रेस के कमजोर होने से महागठबंधन जहां कमजोर हुआ, वहीं एनडीए में भाजपा मजबूत हुई। जदयू ने भी कई सीटों पर कांग्रेस को हराया। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी कांग्रेस को काफी जगह मुंह की खानी पड़ी।

इधर, महागठबधंन को थर्ड फ्रंट को हलके में लेना भारी पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में दो दर्जन के करीब उम्मीदवार खड़े किए और कांग्रेस व राजद से उनके प्रभाव क्षेत्र की सभी सीटे जीत ली। ओवैसी ने पांच सीटें अपने नाम की। बसपा ने भी एक सीट पर जीत दर्ज की। इन सभी सीटों का नुकसान महागठबंधन को हुआ। राजद का एमवाय समीकरण निर्णायक माना जाता रहा है लेकिन इन्हीं सीटों ने महागठबंधन की जीत में रोड़ा अटका दिया। राज्य में करीब 17 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं, जो हार जीत का अंतर पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस बार यही वोटर अलग-अलग हिस्सों में बंटते हुए नजर आए, जिसका फायदा एनडीए को हो गया। राजद का एमवाय समीकरण निर्णायक माना जाता रहा है लेकिन ओवैसी ने इन्हीं सीटों पर महागठबंधन की जीत में रोड़ा अटका दिया। राजद 75 जबकि कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। वाम दलों को 16 सीटों पर जीत मिली। राजद एक बार फिर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी को पांच सीटें कम मिली।

वहीं बिहार में नीतीश कुमार के लिए बह रही नाराजगी की हवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल पहचाना, बल्कि उसे बदलने में भी कामयाबी हासिल की। इसी का नतीजा है कि एनडीए बिहार में बहुमत के आंकड़े के पार पहुंचा। जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ओर से मोर्चा संभाला तो हवा का रुख बदलना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब एक दर्जन सभाएं की, कई रैलियों में वो नीतीश कुमार के साथ भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने लगातार नीतीश की तारीफ की, लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें नीतीश सरकार की जरूरत है। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं का गुणगान हो, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर विपक्ष पर वार करना हो या फिर राजद के जंगलराज का जिक्र कर तेजस्वी पर निशाना साधना हो, प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले दम पर एनडीए के प्रचार को आगे बढ़ाया। जिसने हार और जीत का अंतर तय कर दिया, नतीजों ने भी दिखाया कि जहां जदयू को सीटों में घाटा हुआ वहां पर भाजपा की बढ़त ने एनडीए को बहुमत तक पहुंचा दिया।

● **विनोद बक्सरी**

भाजपा बड़े भाई की भूमिका में

बिहार चुनावों में भाजपा एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आई। भाजपा 74 तो जदयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। जीतनराम मांझी की हम और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही मुकेश सहनी की वाईआईपी ने चार-चार सीट जीतीं। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही चिराग पासवान की लोजपा को रामविलास पासवान के निधन की सहानुभूमि नहीं मिल पाई लेकिन पार्टी खाता खोलने में जरूर कामयाब रही। लोजपा ने वहां-वहां अपने उम्मीदवार खड़े किए जहां जदयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इससे जदयू को खास नुकसान हुआ। जदूय कई बार चिराग को वोटकटवा कह चुकी है। एनडीए की जीत का एक अहम फैक्टर बिहार की महिला वोटर रहीं। बिहार में महिला वोटरों को नीतीश कुमार का पक्का मतदाता माना जाता रहा है, जो हर बार साइलेंट तरीके से नीतीश के पक्ष में वोट करता है। यही नतीजा इस बार के चुनाव में भी दिख रहा है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, शौचालयों का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ महिलाओं को होता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा की गई शराबबंदी के पक्ष में भी बिहार की महिलाएं बड़ी संख्या में नजर आती हैं। ऐसे में फिर एक बार एनडीए की जीत में 50 फीसदी आबादी निर्णायक भूमिका निभाते नजर आए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद महिला वोटरों को खासतौर पर धन्यवाद किया।

बाइडेन से बड़ी उम्मीदें

सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दुनिया की हमेशा से दिलचस्पी रही है। यह इस बार भी है, क्योंकि अमेरिका इसके पहले वैचारिक आधार पर इतना विभाजित कभी नहीं दिखा। वहां दोनों प्रमुख दल-डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसने अमेरिकी समाज के बीच एक खाई पैदा कर दी है, जो आसानी से पटती नहीं दिख रही है। इस खाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार माना जाता है। कहते हैं कि ट्रंप ने तब राष्ट्रपति बनने की ठानी थी, जब एक डिनर में बराक ओबामा ने उनका उपहास उड़ाया था। एक उद्योगपति के तौर पर खुद को कई बार दिवालिया घोषित कर चुके ट्रंप ने आखिर रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल कर ली और 2016 में जब डेमोक्रेट प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, तब उन्होंने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की।

ट्रंप अपने विवादास्पद बयानों और अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन पर न केवल कोरोना की अनदेखी का आरोप लगा, बल्कि अश्वेतों के प्रति पुलिस के आक्रामक रवैए की उपेक्षा करने का भी। इसके चलते चुनाव के पहले श्वेतों और अश्वेतों के बीच तनाव बढ़ा और कई शहरों में हिंसा भी हुई। इस हिंसा को रोकने के लिए जैसे कदम उठाए जाने चाहिए थे, उनसे ट्रंप बचते हुए दिखाई दिए। चुनाव के पहले उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि अगर वह हारे तो अमेरिका में दंगे होंगे। उनका मीडिया से भी झगड़ा जारी रहा। वह इसके लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों को किस तरह उनके पदों से चलता किया। उन पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे। वह पिछले चुनाव में रूस के हस्तक्षेप से इनकार करते, लेकिन अब खुद चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप पर उनसे यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर चुनाव प्रक्रिया की जटिलताओं से परिचित होने के बाद भी उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? ट्रंप मतगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन यह साफ है कि उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा था तो ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर चीन की कठपुतली होने का आरोप लगाकर इस वैश्विक संस्था से निकलने का फैसला किया। वह इस महामारी से लड़ने में भी विफल रहे। शुरू में उन्होंने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि यह जानलेवा बीमारी है। वह लॉकडाउन और मास्क को भी गैरजरूरी बताते रहे। परिणाम यह हुआ कि जो अमेरिका खुद को विज्ञान और तकनीक में अव्वल मानता है, वहां इस महामारी के कारण सबसे अधिक मौतें हुईं। मौतों का सिलसिला अभी भी कायम है।

ट्रंप ने जैसे डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर किया, वैसे ही उन्होंने पेरिस जलवायु संधि से भी बाहर आने का फैसला किया और ईरान से हुई परमाणु संधि से भी। इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान से समझौता किया। उनके ऐसे फैसलों ने विश्व राजनीति को प्रभावित किया। रिपब्लिकन 'अमेरिका फर्स्ट' नीति पर चलते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों और द्विपक्षीय संबंधों में भी इसी नीति का इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी प्रभावित होती है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति को एक अलग ही स्तर पर ले गए, बगैर यह सोचे-विचारे कि इससे विश्व पर क्या असर पड़ेगा। इसी कारण दुनिया के अनेक देश उनके फैसलों को लेकर सशंकित बने रहे। अमेरिका प्रवासियों का देश है। यहां पर हर देश से आकर लोग बसे हैं। यहां भारतीयों का भी अच्छा-खासा असर है। इस बार एक दर्जन से अधिक भारतीय मूल के लोग चुनाव जीते हैं। भारतीय-अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस तो उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी ही हैं। भारत को अपना दोस्त बताने के बाद भी ट्रंप एच-1बी, एच-2बी समेत अन्य विदेशी वीजा पर अंकुश लगाने वाले फैसले करते रहे।

एच-1बी वीजा भारतीयों के लिए बहुत मददगार है। आमतौर पर आईटी सेक्टर के पेशेवर इस वीजा का लाभ उठाते हैं। इस वीजा को लेकर ट्रंप की टेढ़ी निगाह के बाद भी भारत और अमेरिका के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते रहे। पिछले कुछ समय से ट्रंप और मोदी की दोस्ती भी प्रगाढ़ हो गई थी। इसी के चलते अपने कार्यकाल के अंतिम समय में वह भारत के दौरे पर भी आए। ट्रंप ने अनेक देशों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया। हाल के दिनों में उन्होंने चीन के प्रति खासी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने चीन के साथ व्यापार घाटा रोकने के लिए कई अवश्य कदम उठाए, लेकिन उनसे चीन पर बहुत असर नहीं पड़ा। चूंकि ट्रंप यह आरोप लगाते रहे हैं कि बाइडेन चीन के प्रति नरमी रखते हैं, इसलिए देखना यह है कि बतौर राष्ट्रपति वह चीन की ओर से पेश की जा रही चुनौती से किस तरह निपटते हैं? वैसे इस पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों सहमत हैं कि चीन विश्व व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। अमेरिका चीन के मामले में जो नीति अपनाएगा, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। निःसंदेह भारत के प्रति चीन के आक्रामक रवैए की ट्रंप प्रशासन ने निंदा तो की, लेकिन उससे जैसी मदद की दरकार थी, वह नहीं दिखी।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

भारत-अमेरिका की दोस्ती और मजबूत होगी

चूंकि डेमोक्रेट उतने अमेरिका केंद्रित नहीं हैं, जिसका भारत को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यह देखना होगा कि बाइडेन भारत की मूल समस्याओं को हल करने में दिलचस्पी दिखाते हैं या नहीं? इनमें एक समस्या पाकिस्तान के भारत विरोधी रवैए को लेकर है और दूसरी चीन के आक्रामक रुख को लेकर। एक के बाद एक अमेरिकी राष्ट्रपति यह तो मानते रहे कि पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है, पर वे इस आशय के बयान देने तक ही अधिक सीमित रहे। उन्होंने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी अड्डों की ओर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। अमेरिका तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों को पोषित करने वाले पाकिस्तान की मदद करता रहा। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान आतंक से लड़ने के नाम पर अमेरिका से मदद लेता रहा और आतंकियों को पालता रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद तो रोक दी, मगर तालिबान से समझौता कर लिया। देखना है कि बाइडेन क्या रवैया अपनाते हैं? इतना तय है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत-अमेरिका के बीच दोस्ती का सिलसिला थमने वाला नहीं, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां से पीछे नहीं लौटा जा सकता।

ड्रैगन के शिकंजे में नेपाल

चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण जहां एलएसी पर अप्रैल माह से ही तनावपूर्ण हालात हैं, वहीं चीन की गोद में खेल रहा नेपाल भी अब चीन की इन्हीं नीतियों का शिकार हो रहा है। हाल ही में यह खुलासा होने के बाद कि चीनी सैनिकों ने नेपाल के हुम्ला जिले में सीमा स्तंभ से दो किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है, चीन में हंगामा मचा है। दरअसल ड्रैगन नेपाल के इस इलाके में अब तक नौ भवनों का निर्माण कर चुका है। यही नहीं, उसके सैनिकों ने यहां नेपाली लोगों के आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। जैसी कि ड्रैगन की फितरत रही है कि वह किसी भी देश की जमीन कब्जाने के बाद दादागिरी दिखाते हुए उसे अपना ही भू-भाग बताता है, ऐसा ही दावा उसने नेपाली जमीन कब्जाने के बाद भी किया है। हालांकि नेपाली अधिकारियों का कहना है कि चीन ने नेपाली भूमि में अतिक्रमण करते हुए इमारतें बनाई हैं, लेकिन ड्रैगन का दावा है कि उसने जहां इमारतें बनाई है, वह उसका अपना भू-भाग है। गौरतलब है कि नेपाल के सीमावर्ती करनाली प्रांत के दूरस्थ हुमला जिले में दो वर्ष पूर्व तक चीन सीमा पर केवल तीन ही भवन थे लेकिन चीनी सेना पीएलए अब यहां नौ वाणिज्यिक भवन बना चुकी है।

नेपाली जनता के प्रबल रोष का सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तरफ नेपाल से नजदीकियां बढ़ाने की आड़ में चीन नेपाल में अपना आधार मजबूत कर वहां की जमीन हथियाने के मंसूबे पूरे करने के प्रयासों में जी-जान से जुटा है, वहीं उनके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सब कुछ जानते-समझते हुए भी चुप्पी साधे हैं। उनके मौन समर्थन का ही नतीजा है कि नेपाल ड्रैगन के क्रूर पंजों में फंसता जा रहा है और नेपाल को चीन से उनकी यह दोस्ती बहुत महंगी साबित हो रही है। चीन बेकाबू होकर नेपाली जमीनें हथिया रहा है और तिब्बत में सड़क निर्माण के नाम पर भी नेपाली भूमि का अतिक्रमण कर रहा है। हालांकि नेपाली जनता विरोध-प्रदर्शन कर रही है क्योंकि उसका मानना है कि चीन अपनी इन्हीं विस्तारवादी नीतियों के चलते एक दिन तिब्बत की ही भांति नेपाल को भी हड़प लेगा लेकिन ओली सरकार नेपाली गांवों पर चीन के अवैध कब्जों के बावजूद खामोश है क्योंकि वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। ओली और उनकी पार्टी चीनी सत्ता पर काबिज शी जिनपिंग की पार्टी की विचारधारा की ही समर्थक है। इसी कारण ओली ने चीन से प्रेम की पींगें बढ़ाते हुए भारत से दूरियां बढ़ानी शुरू की थीं। भारत के इसी विरोध के चलते ओली ने नेपाल के हिंदू राष्ट्र का दर्जा भी खत्म किया था।

इसी साल जून माह में विपक्षी नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने आरोप लगाया था कि चीन ने देश के दोलखा, हुमला, सिंधुपालचौक, संखुवासभा, गोरखा और रसुवा जिलों में 64 हैक्टेयर भूमि का अतिक्रमण किया है। नेपाली कांग्रेस द्वारा नेपाली संसद के निचले सदन में रेजॉल्यूशन पेश करते हुए ओली सरकार से चीन की छीनी हुई जमीन वापस लेने को भी कहा गया था। ओली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को बचाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। नेपाली जमीनों पर चीनी कब्जों के बावजूद अगर नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यवली कहते रहे हैं कि नेपाल का सीमा विवाद चीन के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ है तो समझा जा सकता है कि नेपाल में निर्णय लेने की क्षमता पर किस कदर चीनी दबाव हावी है।

दो नेपाली एजेंसियों द्वारा नेपाली जमीन हड़पने की खबरों के अलावा हाल ही में नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि ड्रैगन सात सीमावर्ती जिलों में फैले कई स्थानों पर नेपाल की जमीनों पर कब्जा कर चुका है। सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा जमीन का अतिक्रमण कर रहा है। रिपोर्ट में 33 हैक्टेयर दायरे में फैले उन 10 इलाकों का भी जिक्र है, जहां चीन ने बागडारे खोला, करनाली, सिनजेन, भुरजुक, जंबुआ खोला इत्यादि नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीनें कब्जाई हैं। इन चार नेपाली जिलों में अधिकांश क्षेत्र नदियों के जलग्रहण क्षेत्र हैं, जिनमें हुमला, कर्णली, संजेन, लेमडे, भृजुग, खारेन, सिंधुपालचौक, भोटेकोसी, जाम्बु नदीय कामाखोला, अरूण नदी प्रमुख हैं। नेपाल के सर्वे और मैपिंग विभाग का कहना है कि चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नेपाल के दोलखा में 1500 मीटर अंदर धकेल दिया गया है। इस विभाग के मुताबिक चीन ने गोरखा और दारचुला जिलों में नेपाली गांवों पर कब्जा कर लिया है। अपने ही मंत्रालयों और सरकारी विभागों की ऐसी रिपोर्ट्स सामने आने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री ओली चीन की गोद में खेल रहे हैं तो हैरानी होती है।

● **कुमार विनोद**

भारत हमेशा रहा है नेपाल का शुभचिंतक

भारत ने नेपाल को सदैव अपना छोटा भाई मानते हुए हर कदम पर उसकी मदद की है जबकि चीन की विस्तारवादी नीतियों और नेपाली जमीनों पर कब्जे की चीनी नीति से ओली भी अनजान नहीं हैं लेकिन अगर फिर भी वे राष्ट्रहितों को दरकिनार कर भारत से दुश्मनी बढ़ाने पर उतारू हैं तो यह तय है कि चीन से उनकी यह दोस्ती उनके देश को अंततः बहुत महंगी पड़ने वाली है। ओली कुछ महीनों से जिस प्रकार चीन की ही बोली बोलकर भारत जैसे उसके हितैषी और परम मित्र देश के साथ भी दुश्मनी मोल लेने पर उतारू दिखाई दिए हैं, उसका उन्हीं के देश में प्रबल विरोध हो रहा है। नेपाली नागरिक मानने लगे हैं कि चीन भारत के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नेपाल को मोहरा बना रहा है और नेपाली जमीनें कब्जा कर भारत तक अपनी पहुंच आसान करना चाहता है। ड्रैगन के इशारों पर ओली के नाचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे नेपाल में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए ड्रैगन का सहारा ले रहे हैं और ड्रैगन उनकी इसी मजबूरी का भरपूर लाभ उठा रहा है। भारत द्वारा पूरी दुनिया के समक्ष चीन के विस्तारवादी प्लान की पोल खोले जाने और चीन द्वारा लगातार नेपाली जमीनों पर कब्जे किए जाने के बाद भी अगर ओली को सद्बुद्धि नहीं मिल रही है तो यह नेपाली जनता का दुर्भाग्य ही है, जिनकी सरकार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कठपुतली की भांति कार्य कर रही है।

और एक प्रतिभा की मौत

अच्छी बेटी न बन पाने का गम

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की रहने वाली ऐश्वर्या ने अपने सुसाइड नोट में माता-पिता को संबोधित करते हुए लिखा है- मुझे माफ कर देना। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी। उसके इस सुसाइड नोट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। ऑटो मैकेनिक श्रीनिवास रेड्डी और कपड़े सिलने का काम करने वाली मां की बेटी ऐश्यर्या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते उसके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। हालात इस कदर खराब हो गए थे कि वह पढ़ाई आगे जारी रख पाने में खुद को असमर्थ पा रही थी। पढ़ाई-लिखाई में बेहद प्रतिभाशाली ऐश्वर्या ने अपने स्कूल में टॉप किया था। अपने मेरिट के दम पर ऐश्वर्या का दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय के नामी कॉलेज लेडी श्रीराम में हुआ। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और एनएसयूआई (नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया) ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि छात्रा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इंस्पायर फेलोशिप मिलनी थी। नियम के मुताबिक मार्च में फेलोशिप मिल जाना चाहिए थी जो नहीं मिली।

देश की होनहार छात्राओं में शुमार ऐश्वर्या की मौत दरअसल, प्रतिभा की मौत है। ऐश्वर्या को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। ऐश्वर्या की मां ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में ऐश्वर्या शादनगर स्थित घर आ गई थी। इसके बाद कॉलेज से छात्रावास खाली करने का नोटिस आया था, जिसके बाद ऐश्वर्या ने 40 हजार रुपए मांगे थे और कहा था कि वे दिल्ली जाकर सिविल सेवा की तैयारी जारी रखना चाहती है। वहीं, परिवार पहले ही एक बार दो लाख रुपए लोन एवं बाद में एक लाख रुपए गोल्ड लोन ले चुका था। ऐसे में आगे की पढ़ाई के लिए और पैसे का प्रबंध करने में परिवार सक्षम नहीं था। उधर, ऐश्वर्या सिविल सेवाओं के लिए भी तैयारी कर रही थीं। दिल्ली में रहने के दौरान अगर वह कमरा किराए पर लेकर दिल्ली में रहतीं तो पढ़ाई व कोचिंग का कुल खर्च प्रतिमाह 50 हजार रुपए होता जिसे परिवार किसी भी तरीके से वहन करने में सक्षम नहीं था।

मां ने बताया कि ऐश्वर्या अक्सर कहती थीं कि वे दिल्ली के कॉलेज से पढ़ाई छोड़कर शादनगर में ही किसी कॉलेज में दाखिला ले लेगी, लेकिन उन्हें इस बात की हिचकिचाहट भी रहती थी कि यदि लेडी श्रीराम कॉलेज को छोड़कर आएंगी तो लोग उन पर हंसेंगे। शायद इसी वजह से ऐश्वर्या ने जिंदगी जीने और मुश्किलों से लड़ने की बजाय मौत को गले लगा लिया। यहां पर बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज में बीएससी ऑनर्स (गणित) द्वितीय वर्ष की छात्र ऐश्वर्या ने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के चलते पढ़ाई में आ रही चुनौतियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मूलत: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की निवासी ऐश्वर्या के पिता श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ऐश्वर्या दिल्ली में पढ़ाई के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी कर रही थी। 2 नवंबर को उसने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि वह अपनी पढ़ाई के लिए माता-पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती। पिता श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि उनकी बेटी ने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे जिसके आधार पर उसे डीयू के प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश मिला था। वहीं, ऐश्वर्या रेड्डी की मां सुमति रेड्डी ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इंस्पायर फेलोशिप मिलनी थी, लेकिन अब तक नहीं मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार से उनकी दूसरी बेटी की पढ़ाई में मदद करने की मांग भी की है।

नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सफदरजंग रोड स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय प्रभारी रुचि गुप्ता ने कहा कि यदि समय रहते फेलोशिप दी होती तो ऐश्वर्या की मौत नहीं होती। वहीं, लेडी श्रीराम कॉलेज की प्राचार्या सुमन कुमार ने कहा कि ऐश्वर्या ने कभी परेशानी साझा नहीं की। छात्रावास सिर्फ प्रथम वर्ष की छात्राओं को ही अलॉट होता है, कॉलेज की काउंसलर छात्राओं से बात करती रहती हैं। ऐश्वर्या ने परेशानी साझा की होती तो जरूर मदद की गई होती।

देश की होनहार छात्रा द्वारा आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर की गई नोटबंदी और देशबंदी से भाजपा सरकार ने अनगिनत घर उजाड़ दिए हैं। यही सच्चाई है। राहुल ने छात्रा के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आत्महत्या के पहले छात्रा ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से भी मदद मांगी थी। छात्रा ने अभिनेता को पत्र लिखकर बताया था कि लैपटॉप नहीं होने के कारण वह ऑनलाइन क्लासेज नहीं कर पा रही है साथ ही प्रैक्टिकल भी नहीं हो पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक छात्रा के पिता श्रीनिवास रेड्डी मैकेनिक हैं वहीं मां कपड़े सिलती है। लॉकडाउन के दौरान उन्हें काम नहीं मिल पाया था जिसके वजह से वह ऐश्वर्या के लिए पुरानी लैपटॉप भी नहीं खरीद सकते थे। ऐश्वर्या की छोटी बहन वैष्णवी ने स्कूल के बाद की पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि उसकी बड़ी बहन पढ़ाई कर सके। यहां तक कि ऐश्वर्या के एडमिशन के दौरान उसके परिजनों ने अपना बेडरूम का घर तक गिरवी रख दिया था।

ऐश्वर्या की मां सुमति रेड्डी कहती हैं कि उन्हें इस बात का अहसास नहीं था कि बेटी चुपचाप दुनिया ही छोड़कर चली जाएगी। उन्होंने मीडिया को बताया है कि हमारी आर्थिक स्थिति के कारण वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उसे अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना था, उसके सभी दोस्तों ने जाना शुरू कर दिया था। हम लोन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं कर सके। ऐसे में वह डिप्रेशन में आ गई। वह सिविल सर्विसेस के एक्जाम में बैठना चाहती थी लेकिन उसे चिंता सता रही थी कि हम उसकी पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर पाएंगे।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

वनवासियों के रोम-रोम में राम

आज भी भारत में वनवासी मूल रूप में प्रभु श्रीराम की प्रतिमूर्ति ही नजर आते हैं। दिल से एकदम सच्चे, धीर गंभीर, भोले-भाले होते हैं। यह प्रभु श्रीराम की उन पर कृपा ही है कि वे आज भी सतयुग में कही गई बातों का पालन करते हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि प्रभु श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना वनवासियों एवं वानरों की सहायता से ही बनाई थी। केवट, शबरी आदि के उद्धार संबंधी कहानियां तो हम सब जानते हैं। परंतु, जब वे 14 वर्षों के वनवास पर थे तो इतने लंबे अर्से तक वनवास करते-करते वे स्वयं भी एक तरह से वनवासी बन गए थे। इन 14 वर्षों के दौरान, वनवासियों ने ही प्रभु श्रीराम की सेवा सुश्रुषा की थी एवं प्रभु श्रीराम भी इनके स्नेह, प्रेम एवं श्रद्धा से बहुत अभिभूत थे। इसी तरह की कई कहानियां इतिहास के गर्भ में छिपी हैं।

यह भी एक कटु सत्य है एवं इतिहास इसका गवाह है कि हमारे ऋषि-मुनि भी वनवासियों के बीच रहकर ही तपस्या करते रहे हैं। अत: भारत में ऋषि, मुनि, अवतार पुरुष, आदि वनवासियों, जनजातीय समाज के अधिक निकट रहते आए हैं। इस प्रकार, हमारी परम्पराएं, मान्यताएं एवं सोच एक ही है। जनजातीय समाज भी भारत का अभिन्न एवं अति महत्वपूर्ण अंग है। आज भी भारत में वनवासी मूल रूप में प्रभु श्रीराम की प्रतिमूर्ति ही नजर आते हैं। दिल से एकदम सच्चे, धीर गंभीर, भोले-भाले होते हैं। यह प्रभु श्रीराम की उन पर कृपा ही है कि वे आज भी सतयुग में कही गई बातों का पालन करते हैं। परंतु, ईसाई मिशनरियों एवं कुछ लोगों द्वारा आज वनवासियों को उनके मूल स्वभाव से भटकाकर लोभी, लालची एवं रावण वंशज बताया जा रहा है। वनवासी रावण के वंशज कैसे हो सकते हैं? जब रावण स्वयं तो वनवासी कभी रहे ही नहीं थे एवं वे श्रीलंका के एक बुद्धिमान राजा थे। इस बात का वर्णन जैन रामायण में भी मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब रावण स्वयं एक ब्राह्मण था तो वंचित वर्ग का मसीहा या पूर्वज कैसे हो सकता है? जैन रामायण की तरह गोंडी रामायण भी रावण को पुलत्स वंशी ब्राह्मण मानती है, न कि आदिवासियों का पूर्वज, कुछ गोंड पुजारी रावण को अपना गुरु भाई भी मानते हैं, चूंकि पुलत्स ऋषि ने उनके पूर्वजों को भी दीक्षा दी थी। इस तरह के तथ्य भी इतिहास में मिलते हैं कि रावण अपने समय का एक बहुत बड़ा शिव भक्त एवं प्रकांड विद्वान था। रावण जब मृत्यु शैया पर लेटा था तब प्रभु श्रीराम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा था कि रावण अब मृत्यु के निकट है एवं प्रकांड विद्वान है अत: उनसे उनके इस अंतिम समय में कुछ शिक्षा ले लो। तब लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ खड़े होकर शिक्षा लेने पहुंचे थे तो लक्ष्मण को कहा गया था कि शिक्षा लेनी है तो रावण के पैरों की तरफ़ आना होगा। तब लक्ष्मण, रावण के पैरों के पास आकर खड़े हुए तब जाकर रावण ने लक्ष्मण को अपने अंतिम समय में शिक्षा प्रदान की थी। अत: रावण अपने समय का एक प्रकांड पंडित था।

भारतीय संस्कृति पर पूर्व में भी इस प्रकार के हमले किए जाते रहे हैं। भारत में समाज को आपस में बांटने के कुत्सित प्रयास कोई नए नहीं हैं। एक बार तो रामायण एवं महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथों को भी अप्रामाणिक बनाने के कुत्सित प्रयास हो चुके हैं। वर्ष 2007 में तो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के मातहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक हलफनामा (शपथ पत्र) दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वाल्मीकीय रामायण और गोस्वामी तुलसीदासजी कृत श्रीरामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन इनके पात्रों को ऐतिहासिक रूप से रिकार्ड नहीं माना जा सकता है, जो कि निर्विवाद रूप से इनके पात्रों का अस्तित्व सिद्ध करता हो या फिर घटनाओं का होना सिद्ध करता हो।

ये बातें कितनी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यह कहना कि प्रभु श्रीराम और रामायण के पात्र (राम, भरत, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव और रावण आदि) ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक सिद्ध नहीं होते, एक प्रकार से भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात ही था। हालांकि भारतीय जनमानस के आंदोलित होने पर उस समय की भारत सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने अपने शपथ पत्र (हलफनामे) को न्यायालय से वापस मांग लिया था। विभिन्न देशों में वहां की स्थानीय भाषाओं में पाए जाने वाले ग्रंथों एवं विदेशों तक में किए गए कई शोध पत्रों के माध्यम से भी यह सिद्ध होता है कि प्रभु श्रीराम ने 14 वर्ष तक वनवासी बनकर ही वनों में निवास किया था। अत: यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रभु श्रीराम भी अपने वनवास के दौरान वनवासियों के बीच रहते हुए एक तरह से वनवासी ही बन गए थे। साथ ही, वनों में निवासरत समुदायों ने सहज ही उन्हें अपने से जुड़ा माना और प्रभु श्रीराम उनके लिए देव तुल्य होकर उनमें एक तरह से रच बस गए थे। फिर आज किस तरह से रावण इन वनवासियों के मसीहा हो सकते हैं?

कई वनवासी एवं जनजाति समाजों ने तो अपनी रामायण ही रच डाली है। जिस प्रकार, गोंडी रामायण, जो रामायण को अपने दृष्टिकोण से देखती है, हजारों सालों से गोंडी व पंडवानी वनों में रहने वाले जनजाति समाजों की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा रही है। गुजरात के आदिवासियों में 'डांगी रामायण' तथा वहां के भीलों में 'भलोडी रामायण' का प्रचलन है। साथ ही, हृदय स्पर्शी लोक गीतों पर आधारित लोक रामायण भी गुजरात में राम कथा की पावन परम्परा को दर्शाती है। भारतीय साहित्य की विशिष्टताओं और गहनता से प्रभावित होकर तथा भारतीय धर्म की व्यापकता एवं व्यावहारिकता से प्रेरित होकर समय-समय पर चीन, जापान आदि एशिया के विभिन्न देशों से ही नहीं, यूरोप में पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों से भी अनेक यात्री, धर्म प्रचारक व्यापारी साहित्यकार आदि यहां आते रहे हैं। इन लोगों ने भारत की विभिन्न विशिष्टताओं और विशेषताओं के उल्लेख के साथ-साथ भारत की बहुप्रचलित श्रीराम कथा के संबंध में भी बहुत कुछ लिखा है। यही नहीं, विदेशों से आए कई विद्वानों ने जहां इस संदर्भ में स्वतंत्र रूप से मौलिक ग्रंथ लिखे हैं, वहीं कई ने इस कथा से संबंधित 'रामचरितमानस' आदि विभिन्न ग्रंथों के अनुवाद भी अपने-अपने भाषाओं में किए हैं और कई ने तो इस विषय में शोध प्रबंध तैयार किए हैं।

● ओम

मिट्टी की महक

दीपावली का दीया खरीदने आकाश बाजार में जगह-जगह घूम रहा था। पर यादों में बसी मिट्टी की महक और कच्चा दीया पूरे बाजार में नहीं मिला।

ओह अम्मा कितने प्यार से गीली मिट्टी की गोलियां बनाकर दीया बनाती थी। साथ में हर साल मिट्टी से आकाश खूब खेलता था।

तीन चार दिन तो मिट्टी की तलाश में हर खेत खलिहान से मिट्टी लाता तब जाकर मां कहती वाह मेरे लल्ला तुझे माटी की पहचान है इसका दीया बहुत बढ़िया बनेगा।

आकाश शहर से दूर चिकनी मिट्टी की तलाश में गांव की ओर बढ़ गया उसे ध्यान ही नहीं रहा। अचानक सड़क किनारे खेतों में घुसकर मिट्टी तलाशने लगा, तभी एक किसान दूर से ही चिल्ला पड़ा अरे! ओ शहरी बाबू मेरे खेतों में क्या कर रहे हो?

घबराहट में वह धान की बालियों पर गिर पड़ा एक मीठा सा अहसास जैसे बाबा धान की बालियों से सहला कर जगा रहे हों।

तीन सालों से बढ़िया नौकरी की तलाश में आकाश भटक रहा था।

वह बिना दीया खरीदे घर लौट आया और अपना सामान पैक कर मकान मालिक को कमरे की चाभी सौंप कर गांव की ओर चल पड़ा।

घर पहुंचकर पीछे से मां की आंखों पर अपने हाथ रख दिए।

अरे लल्ला हाथ हटाओ और दीया बनाने में मदद करो। अच्छा है तू लौट आया खेतों की नमी सूख रही है और तेरे बाबा के आंखों में समा रही है।

सच में सारी नमी तो अम्मा और बाबा की आंखों में दिखाई दे रही थी। अब अपने वतन और चमन दोनों की महक का अहसास हर बच्चों में शिक्षा के माध्यम से जगाऊंगा।

- आरती रॉय

समय बहुत बलवान

समय बहुत बलवान रे साथी
समय बहुत बलवान।
आज तेरा तो कल मेरा है
समय बहुत बलवान।
वक्त की धारा बहती जाए
पीछे सब कुछ छूटा जाए।
मिथ्या नैया पर तू अपनी
ना करना अभिमान।
समय बहुत बलवान रे साथी
समय बहुत बलवान।
समय का पंछी उड़ता जाए
दूर गगन में पंख फैलाए।
खंडित पंखों पर तू अपनी
ना करना गुमान।
समय बहुत बलवान रे साथी
समय बहुत बलवान।
नीरव बेला बीती जाए
हाथों से सब छूटा जाए।
इसके आगे बस चले ना
टूटे सब अरमान।
समय बहुत बलवान रे साथी
समय बहुत बलवान।
काल को कोई पकड़ न पाए
कदम मिलाकर चलता जाए।
ये नहीं है रुकने वाला
तू इसको पहचान।
समय बहुत बलवान रे साथी
समय बहुत बलवान।
सब गुलाम हैं इसके आगे
इससे छिपकर कोई न भागे।
सहता इसके झंझानिल को
बनता वही महान।
समय बहुत बलवान रे साथी
समय बहुत बलवान।

- निशा नंदिनी भारतीय

रक्तबीज

आज मेरी पत्नी बहुत परेशान थी। इन दिनों अखबारों में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं की खबरों ने उसे डरा दिया है, तभी तो वह बेटी को स्कूल भेजने को अब तैयार नहीं है।

मैंने उसे लाख समझाया पर वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी।

उसके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि रक्त बीज की तरह पैदा हो रहे इन दरिंदों से कोई अपनी बहन-बेटी को कैसे बचाए?

आखिर वो एक मां होने के साथ-साथ एक औरत भी है। इसलिए उसके पास उस डर को महसूस करने का भाव हम मर्दों से कहीं अधिक है।

उसका डर जायज है और तर्क संगत भी। परंतु घर में बेटी को कैद कर उसका भविष्य भी तो बर्बाद नहीं किया जा सकता।

अंततः किसी तरह समझा-बुझाकर मैनें आत्मरक्षा के लिए पत्नी और बेटी दोनों को कराटे का प्रशिक्षण दिलाने का आज से ही फैसला कर लिया।

अब उसे थोड़ा सुकून का अहसास हो रहा था। शायद रक्तबीजों से उसका डर कुछ कम हुआ था।

- सुधीर श्रीवास्तव

आईपीएल में बेस्ट प्लेइंग इलेवन

लगभग 2 महीने बाद हमको आखिरकार आईपीएल 2020 का समापन देखने को मिला जहां मुंबई इंडियंस ने पांचवी बार विजयी पताका फहराते हुए फिर से खुद को लीग की बादशाह टीम साबित कर दिया। इस सीजन में हमको गेंदबाजी और बैटिंग के क्षेत्र में कई भारतीय प्रतिभाएं देखने को मिली जिन्होंने काफी प्रभावित किया। देवदत्त पड्डिकल, टी नटराजन, अब्दुल समद, ऋतुराज गायकवाड़ आदि जैसे नामों के अलावा स्थापित भारतीय नामों ने भी कमाल किया है।

दिल्ली के क्रिकेटर शिखर धवन पूरे सत्र में देखने के लिए एक ट्रीट रहे हैं। दिल्ली ने निडर क्रिकेटर में निवेश किया और अनुभवी धवन ने इसका बखूबी भुगतान किया। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में, भारतीय क्रिकेट का गब्बर 22 गज की दूरी पर बल्ले से सभी तरह के शॉट्स उड़ा रहा था। यूएई में ट्रिकी सतहों से अधिकांश बार खुद को ढालते हुए, धवन ने 17 मैचों में 600 रन बनाए। तेज गेंदबाजों पर दबाव डालते हुए, तेज बल्लेबाज ने 145 की स्ट्राइक रेट के साथ 45+ के औसत के साथ रन बनाए। देवदत्त पड्डिकल आईपीएल 2020 में सबसे बड़े खोज में से एक रहे है। बैंगलोर ने 13वीं आईपीएल नीलामी में नवोदित प्रतिभाओं में रुचि दिखाई और इस अनुभवहीन कर्नाटक के क्रिकेटर ने बल्ले से अपनी क्षमता साबित की। शीर्ष क्रम पर उन्होंने 15 आउटफिट में 473 रन बनाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 124.80 की शानदार स्ट्राइक रेट से रन बटोरे। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों से सीख लेते हुए, देवदत्त आगामी वर्षों में एक छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। केएल राहुल ने अपने मानकों के साथ-साथ अपने प्रशंसकों की नजरों में भी नाम कमाया है। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए भारतीय बल्लेबाज ने अपना शत-प्रतिशत दिया। उन्होंने 14 मैचों में 670 रन बनाए, और वह इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में सबसे ऊपर हैं। होनहार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने क्रिकेट के मैदान में पिछले 3 से 4 वर्षों में स्पष्ट रूप से कुछ भी गलत नहीं किया है। अनुभवी घरेलू बल्लेबाज फिर से बल्ले के साथ अपने मानकों पर खरा उतरा। क्योंकि दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक 16 पारियों में 480 रन बनाए हैं। 40.00 की औसत से शानदार रन बनाते हुए, सूर्या भारतीय टीम में उनकी अनुपस्थिति के लिए एक चर्चा का केंद्र बन गए हैं जो इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने के लिए तैयार हैं।

पटना के विकेटकीपर-बल्लेबाज इस समय शानदार फॉर्म में हैं। मुंबई इंडियंस ने चालाकी से आईपीएल 2020 की नीलामी में घातक पॉवर-हिटर को बरकरार रखा। 22 वर्षीय ने 13 पारियों में अपने आकर्षक खाते में 516 रन जमा किए हैं। 57.33 के शानदार औसत से लगातार खेलते हुए, ईशान ने रन बनाने की भूख दिखाई है। बड़ौदा के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बल्ले और गेंदबाजी की लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। होनहार ऑलराउंडर ने मुंबई इंडियंस के लिए 13 पारियों में 178.98 की स्ट्राइक रेट से 281 रन बनाए। टीम में उनकी उपस्थिति टीम को एक अतिरिक्त संतुलन प्रदान करती है। अभी वे हल्की-फुल्की समस्या के चलते गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उम्मीद है जल्दी ही गेंद से भी उनकी वापसी होगी।

सौराष्ट्र के क्रिकेटर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 करोड़ की शानदार कीमत पर उतारा। उन्होंने 232 रन बनाए, जिसमें 22 चौकों और 11 छक्कों के साथ 14 मैचों की 11 पारियां शामिल हैं। हाथ में गेंद के साथ उन्होंने 6 महत्वपूर्ण विकेट हासिल करते हुए महत्वपूर्ण मोर्चे पर विजय प्राप्त की। हालांकि, तीन बार के खिताबी दावेदार प्लेऑफ में जगह नहीं बना सके, लेकिन रवींद्र जडेजा ने बल्ले या गेंद और मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। शानदार कैच पकड़ने के साथ-साथ रन बनाने और विकेट लेने के लिए उनका यहा स्थान बनता है। बंगाल के क्रिकेटर शमी अपने घातक गेंदबाजी आक्रमण के लिए जाने जाते हैं जो बल्लेबाजों को अपनी धुनों पर नाचने के लिए मजबूर करते हैं। पंजाब इकाई के गेंदबाजी विभाग का नेतृत्व करते हुए, शमी ने 14 मैचों में 20 बड़े विकेट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा सत्र में 8.57 की प्रभावशाली रन दर के साथ लगातार गेंदबाजी की। अपरंपरागत-गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भारतीय गेंदबाजी परिदृश्य को बदल दिया है। अनुभवी लसिथ मलिंगा के मार्गदर्शन में, जसप्रीत ने अपनी गेंदबाजी एक्शन में सही बदलाव किया। जसप्रीत भरोसेमंद गेंदबाज हैं, जो नियमित अंतराल पर विकेट ले सकते हैं। 13वें संस्करण में जसप्रीत बुमराह ने मुंबई के आउटफिट में 27 विकेट झटके। 6.71 की इकॉनमी से गेंदबाजी करते हुए, 27 वर्षीय टीम के लिए इस अवसर पर पहुंचे और कुछ आवश्यक विकेट लिए।

भारतीय क्रिकेट टीम में प्रमुख चेहरे युजवेंद्र चहल की कलाइयों में अपार प्रतिभा है। टीम को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए, स्पिनर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए क्रिकेट कार्निवल में अपनी ड्यूटी निभाई। चहल ने नियमित अंतराल पर अपनी उड़ान भरी हुई गेंदों से बल्लेबाजों को पटखनी दी। 30 वर्षीय ने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में सबकुछ संजोया है। लाल पोशाक में विराट के नेतृत्व में कताई विभाग का नेतृत्व करते हुए, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने कई शीर्ष श्रेणी के बल्लेबाजों को चौंका दिया। उन्होंने 15 मैचों में 21 विकेट लिए 20 से कम का औसत रहा। उनकी इकॉनमी दर भी 7.08 रही। यूएई के स्टेडियमों में प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु के युवा टी नटराजन क्रिकेट बिरादरी में चर्चा का विषय बन गए हैं। बाएं हाथ के सीमर को सनराइजर्स हैदराबाद ने लिया था। अधिक से अधिक अवसर बनाते हुए, उन्होंने अपने कप्तान डेविड वार्नर और कई अन्य लोगों को डेथ ओवर में गेंद के साथ अपने शानदार प्रदर्शन से हैरान कर दिया। उन्होंने 16 मैचों में 16 विकेट झटके, नटराजन को टीम में बिली स्टानलेक की पसंद की मौजूदगी के बावजूद प्लेइंग इलेवन से नजरअंदाज नहीं किया जा सका। टीम में अपनी स्थिति को सही ठहराते हुए, नटराजन के पास नारंगी सेना के लिए अच्छा सीजन था। नटराजन को उनके प्रदर्शन के इनाम भी मिल गया है और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह पर उनका चयन हो गया है।

● आशीष नेमा

अनुप्रिया गोयनका का खुलासा

आध्यात्मिक गुरु ने की थी फायदा उठाने की कोशिश

प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम और आश्रम 2 में नजर आई एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका ने खुलासा किया है कि रीयल लाइफ में एक आध्यात्मिक गुरु ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी।

एक इंटरव्यू में अनुप्रिया ने कहा, मेरा परिवार उस बाबा पर बेहद विश्वास करता था। मैं भी उस पर विश्वास करने लगी। उनकी बातें तार्किक होती थीं और वह सही बातें कहते थे। वह प्रैक्टिकल लगते थे लेकिन उन्होंने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की जब मैं 18 साल की थी। इस वजह से मैं लंबे समय तक डरी-डरी रही। भगवान का शुक्र है कि मैंने उसे अपना फायदा नहीं उठाने दिया। मैं उससे बचकर निकलने में कामयाब रही। पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ शोषण की कोशिश हो रही है। मुझे इस बात को मानने में वक्त लगा। शुरुआत में मुझे खुद पर डाउट हो रहा था कि मैं उस पर इतना भरोसा करती हूं और ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रही हूं लेकिन फिर मुझे धीरे-धीरे समझ आ गया कि उसके इरादे क्या हैं।

'ऐतराज' के 16 साल बाद एक्ट्रेस खुलासा

प्रियंका बोलीं- तब मैं इंडस्ट्री में नई थी और...

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फिल्म ऐतराज के 16 साल पूरे होने पर इससे जुड़ा बड़ा खुलासा किया है। स्क्रीन पर कमाल के कॉन्फिडेंस के साथ दिखने वाली प्रियंका असल में बहुत डरी हुई थीं। प्रियंका ने इसके पीछे का कारण भी बताया है। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के साथ-साथ प्रियंका ने विलेन के रोल में भी शानदार काम किया है। उनके ऐसी ही एक बोल्ड किरदार वाली फिल्म ऐतराज को 16 साल पूरे हो गए हैं। प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार और करीना कपूर स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल तो रही थी, इसके साथ ही इस फिल्म में प्रियंका की परफॉर्मेंस को खूब तारीफें मिली थीं। प्रियंका चोपड़ा ने ऐतराज के 16 साल पूरे होने पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें फिल्म से उनकी कुछ क्लिपिंग्स देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा- 2004, एक एक्टर के तौर पर एक साल, मैंने अब्बास-मस्तान की थ्रिलर फिल्म ऐतराज में सोनिया रॉय का किरदार निभाया था। ये मेरे द्वारा निभाए गए किरदारों में सबसे बोल्ड था, जो एक बड़ा रिस्क भी था क्योंकि मैं उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नई थी। मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बुरी तरह डरी हुई थी लेकिन मेरे अंदर का आर्टिस्ट रो रहा था कि मैं कुछ दिलचस्प करूं और सोनिया वही किरदार थी... चालाक, शिकारी, उलझी हुई और खुद के बारे में सोचने वाली लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इमोशनल।

यादगार किरदारों में हमेशा जीवित रहेंगे आसिफ बसरा

बॉलीवुड के लिए ये साल काफी मुश्किलों से भरा मालूम होता है। हाल ही में इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर आई है। गत दिनों दिग्गज अभिनेता आसिफ बसरा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आसिफ बसरा बीते दिनों चर्चित वेब सीरीज पाताल लोक में नजर आए थे। इसके अलावा वो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म काय पो छे में भी अहम किरदार में दिखाई दिए थे। इसके साथ ही आसिफ बॉलीवुड मूवी 'परजानियां', 'ब्लैक फ्राईडे' के अलावा, हॉलीवुड मूवी में भी नजर आए थे। उन्होंने अजय देवगन की फिल्म 'वन्स अपॉन अ टाइम' में इमरान हाशमी के पिता का रोल निभाया था। 20 साल से आसिफ ने अभिनय को अपना फुल टाइम कैरियर बना लिया था। वे अपने किरदारों के लिए बॉलीवुड में हमेशा यादगार बने रहेंगे। हालांकि वो समय-समय पर थिएटर में भी नजर आ जाते थे। इसके अलावा बाइकिंग भी उनके पैशन में से एक था। वो कई बार अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट के साथ देश भर के भ्रमण पर निकल जाते थे।

ऋषि कपूर के निधन के बाद पहली फिल्म पर भावुक हुईं नीतू कपूर

बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू कपूर बुरी तरह टूट गई थीं। वहीं अब वो परिवार और करीबियों के सपोर्ट से धीरे-धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर ला रही हैं। उन्होंने ऋषि कपूर के निधन के बार अब अपनी आने वाली फिल्म के लिए काम शुरू कर दिया है। हाल ही में नीतू सिंह ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी कास्ट के साथ चंडीगढ़ रवाना होने की तस्वीर शेयर की है। जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर को याद करते हुए कुछ लाइनें लिखी हैं।

जब सरकार ने यह अनुभव किया और देखा कि नारियों की 'इज्जत' पर डाका पड़ने के मामले थानों में भरे पड़े हैं, तो सरकार के कान खड़े होना स्वाभाविक था। कान ही नहीं, सरकार की आंखें भी खुलने लगीं और उसने यह महत्वपूर्ण निर्णय कर डाला कि अंधेरे-उजेरे या रात में इज्जत की चोरी ही नहीं, डाके के मामले कुछ ज्यादा ही होने लगे, तो सोचा गया गांव-गांव में घर-घर में 'इज्जतघर' बनवा दिए जाएं। योजना प्रारंभ हुई और वे बाकायदा बन भी गए। अब ये बात अलग है कि निर्माता, कर्ता-धर्ता, प्रधानों और सचिवों की मिलीभगत के परिणाम ज्यादा सुखद नहीं रहे।

इज्जतघर की बात

अपनी-अपनी सबको प्यारी है। अब चाहे वह घरवाली हो अथवा इज्जत। हमारे यहां घरवाली को इज्जत का पर्याय भी माना जाता है। घरवाली से ही घर की इज्जत है। इसीलिए तो कहा गया है कि 'बिन घरनी घर भूत का डेरा।' जब वही नहीं तो आपको कौन पूछने वाला है भला! इसीलिए तो यह भी कहा गया : 'लेखनी पुस्तिका नारि परहस्ते न दीयते।' अब यदि उसे कोई ले जाए या वह स्वत: चली जाए, तो घर की इज्जत ही चली गई मानो। इसलिए इस 'इज्जत' और उस 'इज्जत' दोनों का बहुत ही अनमोल महत्व है! इसकी रक्षा अर्थात् इज्जत की रखवाली। इज्जत की रखवाली करना हर पुरुष का धर्म है। शादी से पहले वह कलाई में राखी बांधकर इसकी रक्षा का वचन लेती है और शादी के बाद पतिगृह में वही 'करवा चौथ' बन जाता है, मानो कह रही हो कि शादी से पहले तो पिता भाई ने उसकी और उसकी इज्जत की रखवाली की अब तेरी बारी है, अब तू कर। इसीलिए तेरी बड़ी उम्र की कामना करती हूं कि यदि तू रहा तो मुझे भी बचाएगा और मेरी अमूल्य 'इज्जत' को भी।

जब सरकार ने यह अनुभव किया और देखा कि नारियों की 'इज्जत' पर डाका पड़ने के मामले थानों में भरे पड़े हैं, तो सरकार के कान खड़े होना स्वाभाविक था। कान ही नहीं, सरकार की आंखें भी खुलने लगीं और उसने यह महत्वपूर्ण निर्णय कर डाला कि अंधेरे-उजेरे या रात में इज्जत की चोरी ही नहीं, डाके के मामले कुछ ज्यादा ही होने लगे, तो सोचा गया गांव-गांव में घर-घर में 'इज्जतघर' बनवा दिए जाएं। योजना प्रारंभ हुई और वे बाकायदा बन भी गए। अब ये बात अलग है कि निर्माता, कर्ता-धर्ता, प्रधानों और सचिवों की मिलीभगत के परिणाम ज्यादा सुखद नहीं रहे। मानो कुएं में भांग पड़ी हो। वही पीलिया ईंटें, नब्बे फीसदी बालू और सीमेंट का बघार लगाकर उन्हें नई नवेली दुल्हन की तरह चमका दिया गया। धक्का मार खनखनाते फाइबर या चद्दर के गेट में किवाड़ भी लगवा दिए गए। वैसे वे चाहते तो यही थे, कि इनमें किवाड़ों की जरूरत ही क्या है! वे खुले खेतों में जाती/जाते हैं, उससे तो यह बिना किवाड़ के ही बेहतर हैं। पर योजना भी तो पूरी करके दिखानी थी, सो वे भी अटका दिए गए।

बन गए 'इज्जतघर'। अब बारी आती है उनका इस्तेमाल करने की। सो उनका इस्तेमाल न होना था, न हुआ, न हो रहा है और न ही होगा। गांव के लोग आप शहरियों से कम अक्लमंद थोड़े होते हैं! तो उन्होंने अपनी अति अक्ल मंदी का सदुपयोग किया और अपनी-अपनी बुद्धि और अपने पांव पसारने की सामर्थ्य के अनुसार किसी ने उनमें उपले, लकड़ी भर लिए, तो किसी ने स्नानागार बनाकर नहाना शुरू कर दिया। कुछ ज्यादा ही अक्लमंदों ने उनमें कुरकुरे, टेढ़े-मेढ़े, कोल्ड ड्रिंक, बीड़ी, माचिस, नमक, मिर्च, हल्दी, आलू, अरबी, गोभी, मिर्च, धनियां, टमाटर की बहुउद्देशीय दुकानें ही खोल डालीं और ठाठ से मूंछों पर ताव देकर लाला बने आसीन हो गए। और उधर घर की 'इज्जतें' आज भी घर के पिछवाड़े में लोटा लेकर ऊंची मेड़ों, मूंज, दाब, काश के झाड़ों के पीछे जगह तलाशती देखी जा रहीं हैं, जैसे वे 'इज्जतघर' बनने से पहले आती-जाती थीं। कहीं कोई अंतर नहीं आया है। आंधी चले, तूफान आए, भीषण ठंड हो, तेज चिलचिलाती धूप पड़े, लेकिन उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले की तरह आज भी यदि कोई इधर-उधर आता-जाता दिख जाता है, तो अपने मानवीय संस्कारवश वे उठकर खड़ी हो लेती हैं और फिर अपने दैनिक कार्य-निष्पादन में व्यस्त हो जाती हैं। मगर अपने 'इज्जतघरों' की इज्जत को किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं लगने देतीं। 'इज्जतघर' तो 'इज्जतघर' ही रहना चाहिए न? हमारी पुरानी खेतों में जाने की सभ्यता की आदत इतनी जल्दी कैसे भुलाई जा सकती है भला? इस काम के लिए तो खेत ही भले! जहां खाना बने, उसके पास ही पाखाना! छि! छि!! छि!!! राम! राम!! राम!!! भला ये कैसे हो सकता है?

इतना ही नहीं लालाजी बने हुए 'इज्जतघर' के इज्जत वाले भी वही कर रहे हैं, जो उनकी घर की 'इज्जतों' के द्वारा किया जा रहा है। कहीं-कहीं तो बने हुए 'इज्जतघरों' की इज्जत पर ही बन आई है। छत और दीवारें गिर चुकी हैं। किवाड़ भैसों की लड़ामनी या चारा ढंकने के काम आ रहा है। कहीं-कहीं छप्पर का काम भी लिया जा रहा है। 'इज्जतघर' के गड्ढ़े और सीट सब नदारद हैं। थानों में आज भी वैसे ही 'इज्जत' पर डाके की रपट लिखाई जा रही हैं और ये 'इज्जतघर' बाइज्जत या तो जमींदोज हो चुके हैं या स्टोर या दुकान बने हुए लालाजी कमाई का घर बने हुए हैं।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5 PH. : +91-0755-4241102, 4257687

Email : shbpl@rediffmail.com Fax : +91-0755-4257687